



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतीपक्षार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1996/भाद्र 2, 1918

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1996/BHADRA 2, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

सूचना

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

((Department of Legal Affairs))

(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 25th July, 1996

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1996

का.आ. 2422.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि
श्री सुधीर कुमार एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के
नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है
कि उसे फौज रोड क्षेत्र (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में)
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (162)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्,

सक्षम प्राधिकारी

S.O. 2422.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Sudhir Kumar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Faiz Road area of Delhi (i.e. N.C.T. of Delhi).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(162)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का. आ. 2423.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रविन्द्र राम चन्द्र गिते, एडवोकेट, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय नासिक (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(163)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2423.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Ravindra Ramchandra Gite, Advocate for appointment as a Notary to practise in Distt. Courts Nashik, (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(163)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का. आ. 2424.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सिरिश पोपटराव धुमाने, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नासिक जिला (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(164)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2424.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Shirish Popatrao Dhumane, Advocate for appointment as a Notary to practise in Nashik Distt. (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(164)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का. आ. 2425.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी

जाती है कि श्री मधुकर एन. पुरकर एडवोकेट ने उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला न्यायालय नासिक (महाराष्ट्र) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(165)/96-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन्, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2425.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Madhukar N. Purkar, Advocate for appointment as a Notary to practise in Distt. Courts Nashik (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(165)/96-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1996

का. आ. 2426.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग में अवर सचिव श्री आर एस. अहूजा को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

2. इसके द्वारा दिनांक 01-08-1994 की अधिसूचना संख्या 1(4)-93/बंदोबस्त का अधिष्करण किया जाता है।

[संख्या 1(4)/93 बंदोबस्त]

पां. के. शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 23rd July, 1996

S.O. 2426.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri R. S. Ahuja, Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division as Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act.

2. This supersedes notification No. 1(4)/93-Settlement dated the 1st August, 1994.

[No. 1(4)/93-Settlement]

P. K. SHARMA, Director

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और शिक्षण विभाग)

दिल्ली, 2 अगस्त, 1996

का. आ. 2427 :—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (8) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री अवतार सिंह दत्ता, अधिवक्ता को विशेष न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में मामला संख्या आर. सी. 1 (एस)/87-ए. सी. यू.-4, एस. आई. सी. -I सी. बी. आई., नई दिल्ली (श्री एस.एम. अहलूवालिया तत्कालीन मुख्य सचिव, नागालैंड के विरुद्ध भ्रानुपातिक परिसम्पत्ति का मामला) और उससे जुड़े अथवा उसके साथ धारित किसी अन्य मामले के संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/49/95-ए.वी.डी. -II]

सतीश चन्द्र तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE
AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 2nd August, 1996

S.O. 2427.—In exercise of powers conferred by the proviso to sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Central Government hereby appoints Shri Avtar Singh Datta, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of Case No. RC.1(S)/87-TCU-I SICI CBI, New Delhi (proportionate to case against Shri S. S. Ahluwalia, the then Chief Secretary, Nagaland) and any other matter connected therewith or incidental thereto, in the court of Special Judge, Delhi.

[No. 225/49/95-AVD.II]

S. C. TEWARY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त 1996

का. आ. 2428:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 के अधिनियम, 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार के लोत (विधि एवं आदेश ई.) विभाग की दिनांक 28-7-96 की अधिसूचना सं. 10582-एल एण्ड ओ. ई-95 द्वारा प्राप्त सहमति से, इसके द्वारा प्राप्त विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 के केन्द्रीय अधिनियम 6) आयुध अधिनियम, 1959 और भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों और दिनांक 31-8-95 को कोडियानकुलम, जिला चिदम्बरनार में निम्नलिखित मामलों में ऊपर वर्णित अपराधों के संबंध में यह उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यन्त्रों अथवा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार, संपूर्ण तमिलनाडु राज्य पर करती है।

1. मनीयाची पुलिस स्टेशन, जिला चिदम्बरनार तमिलनाडु में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 3 और 4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 307, 332, 120ब और 153क के तहत दर्ज मामला सं. 243/95।

2. मनीयाची पुलिस स्टेशन जिला चिदम्बरनार, तमिलनाडु में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 448 427 और 380 के तहत दर्ज मामला संख्या 246/95

[संख्या 228/53/96-ए. वी. डी.-II]

एस. सी. तिवारी, उप सचिव

New Delhi, the 30th August, 1996

S.O. 2428.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of Tamil Nadu vide public (Law and Order B) Department Notification No. 10582/L&O.E/95 dated 28-7-96 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Tamil Nadu for investigation of offences punishable under the Explosive Substances Act, 1908 (Central Act 6 of 1908), the Arms Act, 1959 and of India Penal Code and attempts, abetments and conspiracies in relation or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts that occurred at Kodanakulam in Shidambaranar Dist. 31-8-95 in regard to the following cases :

1. Crime No. 243/95 under sec. 147, 148, 149, 341, 307, 332, 120-B, 153A IPC r/w 3 & 4 of Explosive Substances Act, 1908 (Central Act 6 of 1908), of Maniyachi Police Station in Chidambaranar Dist. of Tamil Nadu, and
2. Crime No. 246/95 under sec. 147, 148, 448, 427 and 380 IPC of Maniyachi Police Station in Chidambaranar Dist. of Tamil Nadu.

[No. 228/53/96-AVD.II]

S. C. TEWARY, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1996

का.आ. 2429:— केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 के अधिनियम 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार की दिनांक 3 अगस्त, 1996 की अधिसूचना संख्या एस.आर. III/1448-1/96 पब्लिक (एस.सी.) विभाग द्वारा प्राप्त सहमति से, एतद्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) के तहत दंडनीय अपराधों और सी.बी.सी.आई.डी. भद्रास दारा सी बीसी आई डी मुख्यालय में तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सेल्वी. जे. जयललिता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 धारा 13 (1) (ड) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत पंजीकृत अपराध संख्या 15/96 के संबंध में उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किया गया या किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली

विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिनियम का विस्तार संपूर्ण तमिलनाडु राज्य पर करती है

[संख्या 228/52/96-ए.बी.डी.-II]

एस.सी. तिवारी, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1996

S.O. 2429.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Tamil Nadu vide Notification No. SR. III/1448-1/96 Public (SC) Department dated 3rd August, 1996 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Tamil Nadu for investigation of the offences punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988) and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to Cr. No. 15/96 registered by the CB CID, Madras at the C.B.C.I.D. Head Quarters under section 13(2) read with 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 against Selvi J. Jayalalitha, former Chief Minister of Tamil Nadu.

[No. 228/52/96-AVD.II]

S. C. TEWARY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का. आ. 2430.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारों द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग 8 अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (a) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) में दी गई रिस्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी,

पी.ओ. सेवा, ग्राम, वर्धा,

महाराष्ट्र, पी.आई.एन.-442102

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संसंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1623 (एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/

एम-31/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Office of the Director General of Income Tax (Experts)

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2430.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and
- It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemptions was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Kasturba Health Society, P.O. Sevagram, Wardha, Maharashtra, PIN-442102.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1623 (F. No. DG/IT(E)/CAL/M-31/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का. आ. 2431.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन

विहित प्राधिकारों द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

के.ई.एम. हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, सरदार मुद्लियान रोड, रास्तापोट, पुना-411011

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन को अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1624/एफ.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/कल/एम-20
35(1)(ii)]
आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2431.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION
K.E.M. Hospital Research Centre, Sardar Mudliar Road, Rashtapeth, Pune-411011.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1624/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-30/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का.प्रा. 2432-—तरीफाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारों द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, के.जे. मेहता, टी.बी. हॉस्पिटल, अमरगढ़-364210, डिस्ट-भावनगर, गुजरात

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन का अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. : 1625/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/कल/जी.-2/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2432.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category 'institution' subject to the following conditions :—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Tuberculosis Research Centre, K.J. Mehta, T. B. Hospital, Amargadh-364210, Distt.-Bhavnagar, Gujarat.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1625/F. No. DG/IT(E);CAL/G-2/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का. आ. 2433.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा

(1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा को प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हार्टफा उण्डेशन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट

सी-II सिलभर आर्च, नीयर

गुजरात कालेज रेलवे क्रॉसिंग,

इलीस ब्रीज, अहमदाबाद-380006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संव' जैसा संवर्ग के लिए लागू हो होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. : 1626/एफ.सं. म.नि./आ. क. (छूट)/कल/जी.-2/35/(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2433.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35

of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Heart Foundation and Research Institute, C-11 Silver Arc,
Near Gujarat College Railway Crossing, Ellisbridge,
Ahmedabad-380006.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1626/F. No. DG/IT(E)/CAL/G-24/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का.आ. 2434.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संस्थान' के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रायोगिक भवन" न्यू मुहुरेली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिर्देशक क (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कामयानी प्रशिक्षण एण्ड संशोधन
सोसायटी, 270-बी, गोरखले नगर,
पूना-53

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :

- (1) उपर्युक्त शर्त (1) 'संव' जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
- (2) संगठन को सूझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिर्देशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1627/(फ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/कल/एम
45/35(1) (ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2434.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities

for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Kamayani Prashikshan & Sanshodhan Society, 270/B, Gokhale Nagar, Pune-53.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1627/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-45/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का.आ. 2435--सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड(ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:--

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहीयां रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन "न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित प्राप्त-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउण्डेशन,
हिन्दी नगर, वर्धा-442103.

यह अधिपूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1628/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-118/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME-TAX

S.O. 2435.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:--

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; &
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Gandhi Memorial Leprosy Foundation, Hindinagar, Wardha-442103.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1628/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-118/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का. प्र. 2436—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रयोगिकी भवन "न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिन्हें क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

आई रिसर्च सेंटर,

13, कैथोडल रोड, मद्रास-600086.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक को अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तान प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1629/एफ.सं. व.नि./आ.क. (छूट)/कल/टो.एन.-22/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 14th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2436.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 1959 GI/96—2

of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Eye Research Centre, 13, Cathedral Road, Madras-660086

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1629 (F. No. DG/IT(E)/CAL/TN-22/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 14 मई, 1996

आयकर

का. प्र. 2437—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर या अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रयोगिकी भवन "न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बी रिसर्च सोसाइटी ग्रान्ट मेडिकल कॉलेज एण्ड जे. जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुम्बई,

सेक्रेण्ड फ्लोर; फ्रंट विंग, स्किन एंड एस.टी. डी. बिल्डिंग जे जे हॉस्पिटल कॉम्पाउण्ड ब्याकुला मुम्बई -400008.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1630/फा.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/एम/84/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 20th May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2437.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Research Society Grant Medical College & J. J. Group of Hospitals, Bombay, 2nd Floor, Front Wing, Skin and S.T.D. Building, J. J. Hospital Compound Byculla, Bombay-400008.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner

of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1630/F. No. DG/IT(E)/M-84/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 21 मई, 1996

आयकर

का.आ. 2438—सर्वसाधारण की एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन "न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बी साउथ इंडियन सुगरकेन एण्ड सुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन, 21-111,

मेन रोड, गांधी नगर, भद्रद्वार,

मद्रास-600020.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1631/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/कल/टी.एन. -62/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 21st May, 1996

INCOME TAX

S.O. 2438.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

"The South Indian Sugarcane and Sugar Technologists Association 21, III, Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Madras-600020.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1631/F. No. DG/IT(E)/CAL/TN-62/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 21 मई, 1996

आयकर

का.भा. 2439.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल इंजिनियरिंग, विहार लेक, पी. ओ. एन. आई. टी. आई. ई., बम्बे-400087

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1632/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/
कल०/एम.-72/35(1)(ii)]

भार. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 21st May, 1996

कलकत्ता, 5 जून, 1996

INCOME TAX

S.O. 2439.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax|Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Institute of Industrial Engineering,
Vihar Lake, P.O. NITIE, Bombay-400087.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1632/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-72/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

आयकर

का.प्रा. 2440.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहिया रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव/वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकी भवन, "न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

वी आई रिसर्च फाउण्डेशन, विजया हॉस्पिटल, 180, ए. एस. के. सलाई, बदायलानी, मद्रास-600026.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1633/एफ. सं. म. नि./प्रा. क. (छूट)/कल./टी. एन. 21/35(1)(ii)]

प्रा. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th June, 1996

कलकत्ता, 5 जून, 1996

INCOME TAX

आयकर

S.O. 2440.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION :

The Eye Research Foundation, Vijaya Hospital,
180, N.S.K. Salai, Vadapalani,
Madras-600026.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1633/F. No. DG/IT(E)/CAL/TN-21/35(1)(ii)]
R. SINGH, Dy. Director

का. आ. 2441.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिये अलग लेखा बहियां रखेगा,
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

हस्तीमल संजेंती रिसर्च फाउण्डेशन,
16, शिवाजी नगर,
पुना-5.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिये लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिये आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किये आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1634/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/कज/एम-92/35(1)(ii)]

आर. सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 5th June, 1996

INCOME TAX

S.O. 2441.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Hastimal Sancheti Research Foundation,
16, Shivajinagar, Pune-5.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension

of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1634/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-92/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 12 जून, 1996

आयकर

क्र.आ. 2442.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के उप-धारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के वर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए प्रलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर प्रायुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दो गई विस्तृत विवरण संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

इण्डियन कैंसर सोसायटी,
74, जेरबाई बडिया रोड, पारेल,
मुम्बई-400012.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की प्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा वर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूचित किया जाता है कि वे अनुमोदन की प्रवधि बढ़ाने के लिए आयकर प्रायुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की प्रवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रति, सचिव, वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1635/एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)/
कल./एम.-59/35(1)(ii)]

एम. कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 12th June, 1996

INCOME TAX

S.O. 2442.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the

category "Institution" subject to the following conditions :—

कलकत्ता, 12 जून, 1996

भा.क. 2443

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Cancer Society, 74, Jerbai Wadia Road, Parel, Bombay-400012.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax (Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1635/F. No. DG/IT(E)/Cal/M-59/35(1)(ii)]

M. KUMAR, Addl. Director

को.भा. 2443:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, भा.क. अधिनियम, 1961 को धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए भा.क. नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए भ्रमण लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) भा.क. महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) भा.क. आयुक्त/भा.क. महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और भा.क. अधिनियम, 1961 को धारा 35 (1) में दिये गये रिसर्वे क्रि.क.लाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गोवा कैंसर सोसायटी, डा. ई. ब्रोगस रोड, दोना पौला, गोवा-403004.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपयुक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूचित किया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए भा.क. आयुक्त/भा.क. निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से भा.क. महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए जावेदन-पत्र की छः प्रति सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1636/एफ.सं. म.नि./भा.क. (छूट)/
कल./गोवा-2/35(1)(ii)]

एस. कुमार अपर निदेशक

Calcutta, the 12th June, 1996

INCOME TAX

S.O. 2443.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax [Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Goa Cancer Society, Dr. E. Borges Road,
Dona Paula, Goa-403004.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-97.

Note : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax [Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation]. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1636/F. No. DG/IT(E)/Cal/Goa-2/35(1)(ii)]

M. KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 12 जून, 1996

आयकर

का. आ. 2444.—पर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii)

के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट); (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्व क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

श्री अरविन्द सोसायटी, सोसायटी हाउस,
पाण्डेचेरी-605002.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उद्धृत शर्त (1) "सं" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की प्रति सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1637/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/
कल./पॉन्ड-1/35(1)(iii)]

एम. कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 12th June, 1996

INCOME TAX

S.O. 2444.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the

purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sri Aurobindo Society, Society House,
UPondicherry-605092.

This Notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-99.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1637/F. No. DG/IT(E)/Cal/Pond-1/35(1)
(iii)]

M. KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 17 जून, 1996

आयकर

का. आ. 1445.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन का, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 को उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संदर्भ में अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में जेआ परीक्षांत आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट,
62- एफ, सुजान सिंह पार्क,
नई दिल्ली-110003.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन का अग्रिम बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन का अग्रिम बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र को विभाग को प्रस्तुत करता है।

[सं. 1638/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/
कल/एन डी-1/35(1) (iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 17th June, 1996

कलकत्ता, 18 जुलाई, 1996

INCOME TAX

S.O. 2445.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities.
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Institute of Marketing Management,
62-F, Sujana Singh Park, New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

Notes : (1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

आयकर

का. आ. 2446.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारों द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" के संगर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए असंग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दो गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

एस्कोर्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च केंद्र,
ओखला रोड,
नई दिल्ली-110025.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संगर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विषय को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1639/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)/
कल./एनडी-5/35(1)(ii)]

[No. 1638/F. No. DG/IT(E)/Cal/ND-1/35(1)(iii)]

M. KUMAR, Addl. Director

मुकेश कुमार अपर निदेशक

Calcutta, the 18th July, 1996

INCOME TAX

S.O. 2446.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Returns of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Escort Heart Institute and Research

Centre, Okhla Road, New Delhi-110025.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1998.

Notes.—(1) Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1639/F. No. DG/IT(E)/Cal/ND-5/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1996

स्टाम्प

का. आ. 2447 :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा मै. हिन्दुस्तान विकास निगम लिमिटेड कलकत्ता को मात्र एक लाख पचास हजार रु. का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है, जो कि मै. हिन्दुस्तान विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा जारी किए गए दो करोड़ रु. के कुल मूल्य के सौ-सौ रु. अंकित मूल्य के सममूल्य पर 32983207 से 33183206 तक की विशिष्ट संख्या वाले

18.5% सुरक्षित अपरिवर्तनीय श्रृणपत्रों पर स्टाम्प के कारण प्रभाव है।

[सं. 41/96-स्टाम्प/फा. सं. 15/10/96-बि. क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st August, 1996

STAMPS

S.O. 2447.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Hindustan Development Corporation Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees one lakh fifty thousand only, chargeable on account of the stamp duty on 18.5 per cent secured Non-convertible Debentures of series XIV bearing distinctive numbers 32983207 to 33183206 of the face value of rupees one hundred each at par of the aggregate value of rupees two crores to be issued by the said company.

[No. 41/96-Stamps/F. No. 15/10/96-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

(आयकर)

का. आ. 2448 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा "भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन नई दिल्ली" को 1995-96 से 1997-98 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के संचयन हेतु उक्त खंड (23) द्वारा यथा-संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा अनन्वयता उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक वंश अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु, जिसे उपर्युक्त खंड (23) के तीसरे परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भाग का संवितरण अपने से सम्बद्ध किसी ए एसिएसन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा; और

(iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हों जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 10166/फा. सं. 196/16/96-आयकर नि. I]

एच. के. चौधरी, अवसर सचिव

New Delhi, the 5th August, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 2448.—In exercise of the powers conferred by clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Indian Olympic Association, New Delhi" for the purpose of the said clause for assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provision to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) the assessee will not distribute any part of its income, in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and
- (iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 10166/F. No. 196/16/96-ITA-II]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996

का. आ. 2449 :—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए कर-निर्धारितियों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में धारा 139 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण

के प्रयोजनार्थ 31 अक्टूबर, 1996 को देय तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है :—

कर-निर्धारिती वर्ग

आयकर नियम, 1961 की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (4) में यथा परिभाषित फर्मों में, कार्य करने वाले भागीदारों, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44-क ख के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के संगत 31-3-96 को समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अपने खातों की लेखा-परीक्षा करानी आवश्यक होती है, बशर्ते कि ऐसे कार्यरत भागीदार सहभागिता विलेख द्वारा यथा प्राधिकृत या उसकी शर्तों के अनुसार 31-3-96 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एसी फर्मों से पारिश्रमिक प्राप्त करने के पाल हों, और उक्त पारिश्रमिक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (3) में यथा परिभाषित खाता लाभों के अनुपात के रूप में भुगतान योग्य हो।

[अधिसूचना सं. 10173/फा. सं. 220/2/96 आयकर नि. II]

मालती आर. श्रीधरन, अवसर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th August, 1996

S.O. 2449.—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of Section 119 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the due date for the purposes of Explanation under sub-section (1) of Section 139 as 31st October, 1996, in respect of the following class of assesseees for the assessment year 1996-97 :—

CLASS OF ASSESSEES

The working partners as defined in Explanation (4) under sub-clause (v) of clause (b) of Section 40 of the Income-tax Act, 1961, in firms which are required to get their accounts, audited in respect of the previous year ended 31st March, 1996 relevant to the assessment year 1996-97 in accordance with the provisions of Section 44AB of the Income-tax Act, 1961, provided that such working partners are entitled to receive remuneration for the previous year ended 31st March, 1996 from such firms, as authorised by or in accordance with the terms of partnership deed and the said remuneration is payable as a proportion of the book profits as defined in Explanation (3) under sub-clause (v) of clause (b) of section 40 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 10173/F. No. 220/2/96/ITA, II]
MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1996

का. आ. 2450 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/44/96—सी. शु.—8 दिनांक 31-5-96 को यह निदेश जारी किया था कि श्री विष्णु कुमार नाथमल उर्फ तुंगुर सोनी, कमरा नं. 53, तीसरी मंजिल बिल्डिंग नं. 187, सिंघानिया बादी वादी सेठ अगियारी लेन, मुम्बई—400002 (2) 165 महात्मा

गांधी मार्ग, बड़ा बाजार, कलकत्ता को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार यरवदा (पुणे) में अभिरक्षा में रखा जाए, ताकि उसे विदेशी मुद्रा संवर्धन के विरुद्ध कार्य करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके।

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त/डायरेक्टर जनरल पुलिस बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/44/96-सी. शु.-8]

प्रकाश चन्द्र, अधर सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1996

S.O. 2450.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/44/96-Cus. VIII dated 31st May, 1996 under the said sub-section directing that Shri Vishnu Kumar Nathmal Tungar @ Soni (i) Room No. 53 3rd Floor, Building No. 187, Singhania Wadi, Dadiseth Agiary Lane, Bombay-400002 (ii) 165, Mahatma Gandhi Road, Bada Bazaar, Calcutta be detained and kept in custody in the Central Prison Yerawada, Poona with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation in the Official Gazette.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police, Mumbai within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/44/96-Cus. VIII]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1996

का. आ. 2451 :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा के के अधीन आदेश फा. सं. 673/43/96—सी. शु.-8 दिनांक 31-5-96 को यह निर्देश जारी किया था कि श्री रमेश बी. पालीवाल, अलाशय रमेश चन्द्र पालीवाल, पुत्र भदुर लाल पालीवाल (1) तीसरी मंजिल, महालक्ष्मी बिल्डिंग 37 मारुति लेन, फोर्ट मुम्बई-400001 (2) ब्रह्मपुरी बी. पी. थो. गोंडा तहसील जिला राजसमन्द राजस्थान को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार यरवदा (पुणे) में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे विदेशी मुद्रा के संवर्धन के विरुद्ध कार्य करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त/डायरेक्टर जनरल पुलिस बम्बई के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/43/96-सी. शु. 8]

प्रकाश चन्द्र, अधर सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1996

S.O. 2451.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/43/96-Cus. VIII dated 31st May, 1996 under the said sub-section directing that Shri Ramesh B. Paliwal @ Ramesh Chandra Paliwal S/o Shri Bherulal Paliwal (i) 3rd Floor, Mahalaxmi Building, 37, Maruti Lane, Fort, Bombay-400001 (2) Brahmmapuri, VPO : Gaonguda, Tehsil : Nathdwara, District : Rajsamand, Rajasthan be detained and kept in custody in the Central Prison Yerawada, Poona with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign Exchange.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/43/96-Cus. VIII]

PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1996

का. आ. 2452 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा, श्री आर. बी. शास्त्री वर्तमान में महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में पदनामित) नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 9/28/95-बी. ओ.-1]

सुधीर भार्गव, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th August, 1996

S.O. 2452.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri R. V. Shastri presently General Manager, Punjab National Bank as a whole time Director (designed as the Executive Director) of Indian Overseas Bank for a period of five years from the date of his taking charge.

[F. No. 9/28/95-B.O.1]

SUDHIR BHARGAVA, Director

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1996

का.आ. 2453:— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा के अधीन आदेश सं. 673/42/96-सी.शु. 8 दिनांक 22-5-96 को यह निदेश जारी किया था कि श्री आर. शशीधरन पुत्र श्री राघवन गीतान्जलि हाउस नं. 4/532 वाकन पंचायत चिरयन रिज, त्रिवेन्द्रम को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मदुरई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त/डायरेक्टर जनरल पुलिस त्रिवेन्द्रम (केरला) के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/42/96-सी.शु. 8]

जमना दास, अवसर सचिव

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1996

S.O. 2453.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/42/96-Cus. VIII dated 22-5-1996 under the said sub-section directing that Shri R. Sasidharan, S/o Shri Raghavan, Geethanjali House No. IV/532, Vakkan Panchayat Chiravin-keezh, Trivandrum be detained and kept in custody in the Central Prison Madurai with a view to preventing him from smuggling goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/42/96-Cus. VII.]

JAMNA DAS, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1996

का.आ. 2454:— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/41/96-सी.शु. 8 दिनांक 22-5-96 को यह निदेश जारी किया था कि श्री आर. शशीधरन पुत्र श्री राघवन गीतान्जलि हाउस नं. IV/532 वाकन पंचायत चिरयन रिज, त्रिवेन्द्रम को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मदुरई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे भविष्य में सामान की तस्करी करने से रोका जा सके।

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त/डायरेक्टर जनरल पुलिस त्रिवेन्द्रम (केरला) के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/41/96-सी.शु.-8]

जमना दास, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1996

S.O. 2454.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/41/96-Cus. VIII dated 22-5-1996 under the said sub-section directing that Shri Ravindradass, S/o Shri Bhanu Panicker, Indira Nivas, Punthura, Trivandrum, Kerala be detained and kept in custody in the Central Prison Madurai with a view to preventing him from smuggling goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner/Director General of Police Trivandrum within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/41/96-Cus. VIII.]

JAMNA DAS, Under Secy.

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

अधिसूचना संख्या 132/96

इन्दौर, 1 अगस्त, 1996

का.आ. 2455 : आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर के निम्नलिखित समूह "ख" अधिकारी निवर्तन आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए दिनांक से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए :—

क्र. अधिकारी का नाम पदनाम निवर्तन आयु प्राप्त करने से पर सेवा निवृत्ति की तारीख

- | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| 1. श्री एन. आर. दुबे | अधीक्षक | 30-4-96 (अपरान्ह) |
| 2. श्री एस. सी. गुप्ते | " | 31-5-96 (अपरान्ह) |
| 3. श्री प्रो. आर. जाम्बुलकर | " | 30-6-96 (अपरान्ह) |
| 4. श्री एन. ए. कुरैसी | " | 31-7-96 (अपरान्ह) |
| 5. श्री पी. सी. प्रेमानी | " | 31-7-96 (अपरान्ह) |

[फा.सं. II (3) 9-गोप./93/3308]

गोविन्दन शो. तंपी, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL
EXCISE & CUSTOMS

NOTIFICATION NO. 132/96

Indore, the 1st August, 1996

S.O. 2455.—The following Group 'B' Officers of Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Indore having attained the age of superannuation retired from Govt service from the dates as shown against their names:—

S. No.	Name of the Officer	Designation	Date of retirement on super-annuation
01.	Shri N.R. Dubey	Superintendent	30-04-96 (AN)
02.	Shri S.C. Gupta	-do-	31-05-96 (AN)
03.	Shri C.R. Jambulkar	-do-	30-06-96 (AN)
04.	Shri N.A. Qureshi	-do-	31-07-96 (AN)
05.	Shri P.C. Premani	-do-	31-07-96 (AN)

[F.No. II(3)9-Con/93/3308]

GOVINDAN S. TAMPI, Commissioner

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1996

का.आ. 2456 :—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा भारत का उच्चयोग लागूश में सहायक श्री विनोद कुमार आजाद को 2 अगस्त, 1996 से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी.-4330/2/96]

आई.पी. मोहनन, अधर सचिव (पी. वी. एस.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th August, 1996

S.O. 2456.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri Vinod Kumar Azad, Assistant in the High Commission of India Lagos to perform the duties of Consular Agent with effect from 2nd August, 1996.

[No. T-4330/2/96]

I. P. MOHANAN, Under Secy. (Cons.)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1996

का.आ. 2457 :—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवम् शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा भारत का दूतावास प्राग में सहायक श्री बी.के. पामी को 2 अगस्त, 1996 से कौंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/2/96]

आई.पी. मोहनन, अधर सचिव (पी. वी. एस.)

New Delhi, the 12th August, 1996

S.O. 2457.—In pursuance of the Clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri V. K. Passy, Assistant in the Embassy of India Prague to perform the duties of Consular Agent with effect from 2nd August, 1996.

[No. T-4330/2/96]

I. P. MOHANAN, Under Secy. (Cons.)

खाद्य मंत्रालय

(खाद्य प्रापण और वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 1996

का. आ. 2458 :—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य मंत्रालय, क्षेत्रीय खाद्य निदेशक उपायुक्त निदेशालय और खाद्य मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारण, संचलन, परिवहन वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया था जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 12 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य थे।

और अतः खाद्य मंत्रालय क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी ना बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12 (i) की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा केन्द्रीय सरकार के दिनांक 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें उल्लिखित निर्धारित तिथि के अन्दर यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी थी।

और जब कि निम्नलिखित कर्मचारी की सेवाएं अभी तक भारतीय खाद्य निगम को अन्तरित नहीं की गई हैं।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अधिनियम संशोधन की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम में स्थानांतरण की तारीख
1.	रत्नेश्वर दाम	सिलाई मशीन आपरेटर	सिलाई मशीन आपरेटर	1-3-1969

[संख्या ए—38 022/1/95—एफ. सी. 3]

सत्य नारायण गुप्त, अवसर सचिव

MINISTRY OF FOOD

(Department of Food Procurement & Distribution)

ORDER

New Delhi, the 30th May, 1996

S.O. 2458.—Whereas the Central Government, had ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transportation, distribution and sale of foodgrains done by the Ministry of Food Regional Director of Food, the procurement Directorates and the Pay & Accounts Office of the Ministry of Food which under Section 12 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) were the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following employee serving in the Regional Directorate of Food, and engaged in the performance of the functions mentioned above had not, in response to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971, intimated, within the date specified therein their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of Section 12(1) of the said Act.

And whereas the services of the following employee have not yet been transferred to Food Corporation of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964),

as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following employee to the Food Corporation of India with effect from the date indicated against his name.

Sl. No.	Name of the officer/Employee	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the Food Corpn. of India
1.	Sh. Ratneswar Das	Sewing Machine Operator	Sewing Machine Operator	1-3-1969

[No. A-38022/1/95/FC-3]

S. N. GUPTA, Under Secy.

नागरिक प्रति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1996

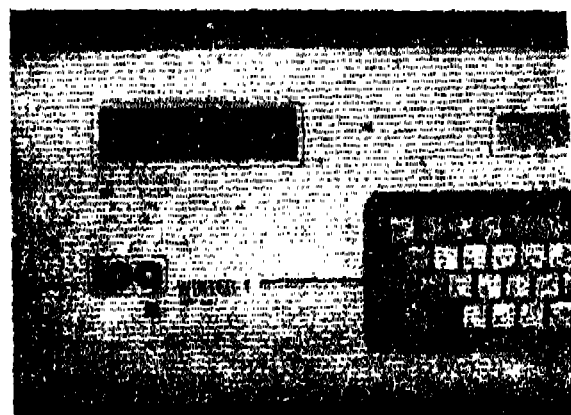
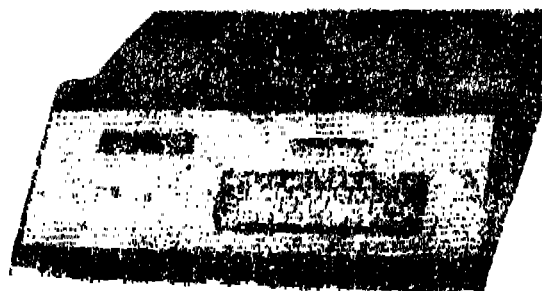
का. आ. 2459 :—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा निवेदित रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माइल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माइल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 36 उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एम. एल. डब्ल्यू.—30 रिपोर्ट वर्ग III टाइप के स्वतः सूचक गैर-स्व-गलित इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी के माइल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माइल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स इंडोप्रेटेड प्रोसेस ऑटोमेशन, 472/बी—2, 12 वां फ़्लास, 4 वां फेस, पीनीया इंडस्ट्रीयल एरिया, बंगलौर-560058 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन बिहू न आई. एन. डी./09/95/07 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माइल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 किलोग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ई) 10 किलोग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक

प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही आयताकार आकृति का है जिसका पार्श्व—9000×3000 मिलीमीटर के हैं। 3.5 मिलीमीटर आकार के 16 संप्रतीकों का अक्षर अंकित एल. सी. डी. संप्रदर्श या 13 मिलीमीटर ऊंचा 7 खंडीय संप्रतीक आकार का प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है।

आगे, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 40 टन की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मैक, यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी है।



[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21(16) / 93]

राष्ट्रीय श्रीधरास्व, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS
AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 2nd August, 1996

S.O. 2439.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

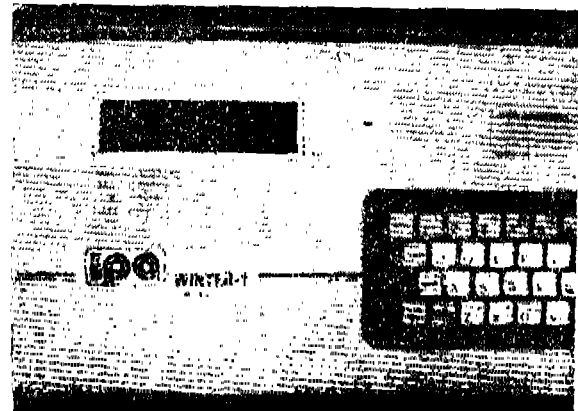
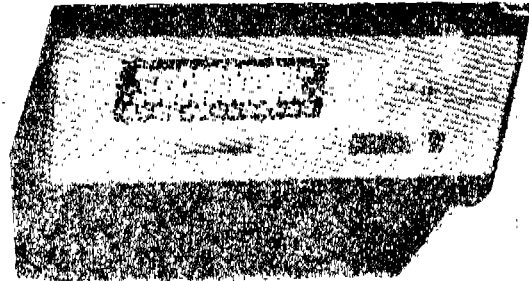
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model

of the self-indicating non-automatic electronic weighbridge of type "SLW-30" series class III (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Integrated Process Automation, 472/B2, 12th cross, IV phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560058, and which is assigned the approval mark IND/09/95/07 :

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 30000 kg. and minimum capacity of 200 kg. The verification scale interval (e) is 10 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular shape of sides 9000×3000 millimetre. The alpha numeric LCD display of 16 characters of size 3.5mm or 7 segment LED display of character size 13 millimetre height indicates the weighing result. The instrument operates on 250 volts 50 hertz alternate power supply.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with maximum capacity of

40 tonne, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.



[F. No. WM-21(16)/93]

RAJIVSHIVASTAVA, Jt. Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जून, 1996

वा.आ. 2460.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि हमारे उपायद्व अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किये जाने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं. टी.आई.एल.ए./एल.एस.ई./96/1 तारीख 10 जनवरी, 1996 का रीक्षण निदेशक (तकनीकी), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सैक्टोरिया, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्द्धवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हिवद्व सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य वस्तुओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सैक्टोरिया, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्द्धवान (पश्चिमी बंगाल) को भेजेंगे।

अनुसूची

रानीगंज कोथला क्षेत्र

तिलाबोनी खान (बंकोला क्षेत्र)

(रेखांक सं. टी.आई.एल.ए./एल.एस.ई./96/1, तारीख 10-1-1996)

(पूर्वोक्षण के लिये अधिसूचित भूमि दर्शाती है)

क्र. सं.	मौजा/ग्राम का नाम	अधिकारिता सूची सं.	थाना	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पण
1.	नाबाधनपुर	19	फरीदपुर	बर्दवान	25.3	भाग
2.	तिलाबोनी	20	फरीदपुर	बर्दवान	59.6	भाग
3.	झांजरा	33	फरीदपुर	बर्दवान	180.6	भाग
4.	सर्पी	35	फरीदपुर	बर्दवान	1.0	भाग

कुल 266.5 एकड़ (लगभग)

या 108 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :-

क—ख	रेखा "क" बिन्दु से आरंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वाड़ों से जाती है, और "ख" बिन्दु पर मिलती है।
ख—ग	रेखा "ख" बिन्दु से आरंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी-पूर्व वाड़ों से जाती है और उसी मौजा में "ग" बिन्दु पर मिलती है।
ग—घ	रेखा "ग" बिन्दु से आरंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वाड़ों से होकर जाती है तथा नाबाधनपुर मौजा और झरिया मौजा के बीच सम्मिलित सीमा के बिन्दु "घ" पर मिलती है।
घ—ङ	रेखा "घ" बिन्दु से आरंभ होती है और झरिया मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वाड़ों से होकर जाती है तथा झरिया और सर्पी मौजा के बीच सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
ङ—च	रेखा "ङ" बिन्दु से आरंभ होती है और सर्पी मौजा के भीतर दक्षिणी पश्चिम वाड़ों से होकर जाती है तथा सर्पी मौजा में "च" बिन्दु पर मिलती है।
च—छ	रेखा "च" बिन्दु से आरंभ होती है और सर्पी मौजा के भीतर दक्षिणी पूर्व वाड़ों से होकर जाती है तथा झांजरा और सर्पी मौजा के बीच सम्मिलित सीमा रेखा के बिन्दु "छ" पर मिलती है।
छ—ज	रेखा "छ" बिन्दु से आरंभ होती है और झांजरा मौजा के भीतर दक्षिणी पूर्व वाड़ों से होकर जाती है और उसी मौजा में "ज" बिन्दु पर मिलती है।
ज—झ	रेखा "ज" बिन्दु से आरंभ होती है और झांजरा मौजा के भीतर उत्तरी-पूर्व वाड़ों से होकर जाती है और झांजरा और तिलाबोनी मौजा के बीच सम्मिलित सीमा रेखा के बिन्दु "झ" पर मिलती है।
झ—ञ	रेखा "झ" बिन्दु से आरंभ होती है और तिलाबोनी मौजा के भीतर उत्तर-पूर्व वाड़ों से होकर जाती है तथा उसी मौजा में "ञ" बिन्दु पर मिलती है।
ञ—ट	रेखा "ञ" बिन्दु से आरंभ होती है और तिलाबोनी मौजा के भीतर उत्तरी पश्चिम वाड़ों से होकर जाती है तथा नाबाधनपुर और तिलाबोनी मौजा के भीतर सम्मिलित सीमा के बिन्दु "ट" पर मिलती है।
ट—क	रेखा "ट" बिन्दु से आरंभ होती है और नाबाधनपुर मौजा के भीतर उत्तरी पश्चिम वाड़ों से होकर जाती है और फिर नाबाधनपुर मौजा के प्रारंभिक "क" बिन्दु पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/4/96-एल.एस. डब्ल्यू.]

श्रीमती प्रेम लता सेनी, अधीक्षक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 12th June, 1996

S.O. 2460.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. TILA/LSE/96/1, dated 10th January, 1996 of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Director (Technical), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan (West Bengal) or in the Office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the Office of the Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta (West Bengal).

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Officer-in-Charge/Head of the Department (Revenue), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan (West Bengal) within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE
RANIGANJ COALFIELDS
TILABONI MINE (BANKOLA AREA)

(Drawing No. TILA/LSE/96/1, dated the 10th January, 1996)

(Showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Name of Mouza/ Village	Jurisdiction list number	Thana	District	Area in acres	Remarks
1.	Nabaghanapur	19	Faridpur	Burdwan	25.3	Part
2.	Tilaboni	20	Faridpur	Burdwan	59.6	Part
3.	Jhanjra	33	Faridpur	Burdwan	180.0	Part
4.	Sarpi	35	Faridpur	Burdwan	1.0	Part

Total Area : 266.5 Acres (approximately)

or

108.0 Hectares (approximately)

Boundary description :—

- A-B Line starts from point 'A' and passes South-Westward within Nabaghanapur Mouza and meets at point 'B'.
- B-C Line starts from point 'B' and passes South-Eastwards within Nabaghanapur Mouza and meets at point 'C' in same Mouza.
- C-D Line starts from point 'C' and passes South-West wards within Nabaghanapur Mouza and meets at point 'D' common boundary between Nabaghanapur Mouza and Jhanjra Mouza.
- D-E Line starts from point 'D' and passes South-Westwards within Jhanjra Mouza and meets at point 'E' common boundary between Jhanjra and Sarpi Mouza.
- E-F Line starts from point 'E' and passes South-Westwards within Sarpi Mouza and meets at point 'F' in Sarpi Mouza.
- F-G Line starts from point 'F' and passes South-Eastwards within Sapri Mouza and and meets at point 'G' common boundary line between Jhanjra and Sapri Mouza.
- G-H Line starts from point 'G' and passes South-Eastwards within Jhanjra Mouza and meets at point 'H' insame Mouza.

H-J Line starts from point 'H' and passes North-Eastwards within Jhanjra Mouza and meets at point 'I' common boundary line between Jhanjra and Tilaboni Mouza.

I-J Line starts from point 'I' and passes North-Eastwards within Tilaboni Mouza and meets at point 'J' in same Mouza.

J-K Line starts from point 'J' and passes North-Westwards within Tilaboni Mouza and meets at point 'K' common boundary within Nabaghanapur and Tilaboni Mouza.

K-A Line starts from point 'K' and passes North-Westwards within Nabaghanapur Mouza and then meets at starting point 'A' at Nabaghanapur Mouza.

[No. 43015/4/96-LSW]

Mrs. P.L. SAINI, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1996

का.आ. 2461 केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 जुलाई, 1995 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.सं. 2009 तारीख 26 जून, 1995 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 70 हेक्टर (लगभग) है, कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त संपूर्ण भूमि में कोयला अभिप्राय है

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 70 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण : 1. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. ई सी एल/एल/ए/एस आई एन/एम एच एन/1/(बी) तारीख 21-12-95 का निरीक्षण कलक्टर, बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सैक्टरिया, डाकघर दिशोरगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण : 2. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:

“8. अर्जन के प्रति आक्षेप—(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी सक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जायगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधिव्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिये देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये वह व्यक्ति किसी भूमि में हितवद्ध समझा जायेगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये जाते हैं।

टिप्पणी : 3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अनुसूची

मोहनपुर कोयला खान

रानीगंज कोयला क्षेत्र

[रेखांक सं. ई सी एल/एल ए/एस एल एन/एम एच एन/1/(बी) तारीख 21-12-95]

क्रम सं. मौजा/ग्राम का नाम	अधिकार क्षेत्र सूची सं.	पुलिस थाना	जिला	क्षेत्र हैक्टेयर में	टिप्पणियां
1. पहाड़गौड़ा	64	सालनपुर	बर्दवान	70	भाग कुल क्षेत्र : 70 हैक्टेयर (लगभग)

संपूर्ण राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट— 248 से 260, 264 से 273, 285 से 464, 465 से 493, 495 से 497, 537 से 539, 542, 543, 578 से 698, 702 से 735, 738, 745, 739

भागतः राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट— 14, 247, 261, 262, 278, 494, 498, 541

सीमा वर्णन :

- क—ख रेखा ग्राम (मौजा) सामदी, क्षेत्राधिकार सूची सं. 63 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु “क” से आरम्भ होती है और ग्राम (मौजा) पहाड़गौड़ा क्षेत्राधिकार सं. 64 की उत्तरी तरफ से होकर जाती है और ग्राम (मौजा) पहाड़गौड़ा, क्षेत्राधिकार सूची सं. 64 और ग्राम (मौजा) मोहनपुर, क्षेत्राधिकार सं. 65 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु “ख” पर मिलती है।
- ख—ग रेखा ग्राम (मौजा) मोहनपुर, क्षेत्राधिकार सूची सं. 65 की सम्मिलित सीमा से आरम्भ होती है और ग्राम (मौजा) मोहनपुर, क्षेत्राधिकार, सूची सं. 65 और ग्राम (मौजा) पहाड़गौड़ा क्षेत्राधिकार सूची सं. 64 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और मौजा मोहनपुर क्षेत्राधिकार सूची सं. 65 तथा पहाड़गौड़ा क्षेत्राधिकार सूची सं. 64 और बोलकुंडा क्षेत्राधिकार सूची सं. 67 के त्रिकोणीय बिन्दु “ग” पर मिलती है।
- ग—घ रेखा मौजा पहाड़गौड़ा, क्षेत्राधिकार सूची सं. 64, मोहनपुर क्षेत्राधिकार सूची सं. 65 और बोलकुंडा क्षेत्राधिकार सूची सं. 67 के त्रिकोणीय बिन्दु से आरम्भ होती है और ग्राम (मौजा) पहाड़गौड़ा क्षेत्राधिकार सूची सं. 64 और ग्राम बोलकुंडा, क्षेत्राधिकार सूची सं. 67 से होकर जाती है और मौजा बोलकुंडा सामदी और पहाड़गौड़ा के त्रिकोणीय बिन्दु “घ” पर मिलती है।
- घ—क रेखा मौजा पहाड़गौड़ा, बोलकुंडा तथा सामदी के त्रिकोणीय बिन्दु से आरम्भ होती है और ग्राम (मौजा) पहाड़गौड़ा तथा ग्राम (मौजा) सामदी की सम्मिलित सीमा से होकर जाती है और बिन्दु “क” पर मिलती है।

[फा.सं. 43015/10/95-एल एस डब्ल्यू]

श्रीमती पी.एल. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th August, 1996

S.O. 2461.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2009 dated the 26th June, 1995 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 22nd July, 1995 issued under Sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 70 hectares (approximately) of lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that Coal is obtainable in the whole of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 70 hectares (approximately) described in the Schedule annexed hereto.

Note 1.—The plan bearing number ECL/LA/SLN/MHN/1 (B) dated 21st December, 1995 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta (West Bengal) or in the office of the Director (Technical), Project and Planning, Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan (West Bengal).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) which provides as follows:—

Objection to acquisition :

“8(1). Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different report in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

MOHANPUR COLLIERY
RANIGANJ COALFIELDS

[Plan number ECL/LA/SLN/MHN/1(B) dated 21-12-95]

Sl. no.	Mouza/ Village	Jurisdiction list No.	Police Station	District	Area in hectares	Remarks
---------	----------------	-----------------------	----------------	----------	------------------	---------

1.	Pahargora	64	Salanpur	Burdwan	70	Part
Total Area : 70 Hectares (approximately)						

R.S. Plots in full—248 to 260, 264 to 273, 285 to 464, 465 to 493, 739, 495 to 497, 537 to 539, 542, 543, 578 to 698, 702 to 735, 738, 745

R.S. Plots in part—14, 247, 261, 262, 278, 494, 498, 541

Boundary description

A-B The line starts from point 'A' the common boundary of village (Mouza) Samdi, Jurisdiction list No. 63 and passes through north side of village (Mouza) Pahargora, Jurisdiction list No. 64 and meets at point 'B' common boundary of village (Mouza) Pahargora, Jurisdiction No. 64 and village (Mouza) Mohanpur, Jurisdiction list No. 65.

B-C The line starts from the common boundary of village (Mouza) Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 and passes through the common boundary of village (Mouza) Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 and village (Mouza) Pahargora, Jurisdiction list No. 64 and meets at point 'C' the triangulation point of Mouza Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 and Pahargora, Jurisdiction list No. 64 and Bolkunda, Jurisdiction list No. 67.

C-D The line starts from the triangulation point of Mouza Pahargora, Jurisdiction list No. 64, Mohanpur, Jurisdiction list No. 65 and Bolkunda Jurisdiction list No. 67 and passes through the common boundary of village (Mouza) Pahargora, Jurisdiction list No. 64 and village Bolkunda, Jurisdiction list No. 67 and meets at point 'D' the triangulation point of Mouza Bolkunda, Samdi and Pahargora.

D-A The line starts from the triangular point of Mouza Pahargora, Bolkunda and Samdi and passes through the common boundary of village (Mouza) Pahargora and village (Mouza) Samdi and meets at point 'A'.

[No. 43015/10/95-LSW]

MR. P. L. SAINI, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

का. आ. 2462 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (i) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 24 जून, 1995 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1733, तारीख 7 जून, 1995 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 378.01 हैक्टर (लगभग) या 934.10 एकड़ (लगभग) है, खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने, तलाश करने और उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में जिसका माप 378.01 हैक्टर (लगभग) या 934.10 एकड़ (लगभग) है, खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और ले जाने के अधिकारों को अर्जित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में जिसका माप 378.01 हैक्टर (लगभग) या 934.10 एकड़ (लगभग) है, खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, निष्पादन के लिए, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जित किया जाना है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई)/III/एफ. आर./588-0895, तारीख 19 अगस्त, 1995 का निरीक्षण कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक-1, कार्डिसल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता—700001 या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व विभाग), कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर—440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

सावनेर खान सं. 1 विस्तार क्षेत्र

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

[रेखांक सं. सी. I (ई)/III/एफ. आर./588—0895, तारीख 19 अगस्त, 1995]

खनिज अधिकार

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी संकेत सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	आंगैवाड़ा	33	सावनेर	नागपुर	10.65	भाग
2.	पटकाखड़ी	33	सावनेर	नागपुर	227.09	भाग
3.	कोटोडी	30	सावनेर	नागपुर	140.27	भाग

कुल क्षेत्र 378.01 हैक्टर (लगभग)
या
934.10 एकड़ (लगभग)

ग्राम आंगैवाड़ा में अर्जित प्लॉट सं.

38 से 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42 से 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 52 भाग।

ग्राम पटकाखेड़ी से अजित प्लाट सं. :

121 से 129, 130/1, 130/2, 131 से 137, 138/1, 138/2, 139 से 143, 144/1---144/2, 145 से 164, 165/1, 165/2, 166 से 172, 173/1, 173/2, 174 से 188, 189/1, 189/2, 189/3, 190, 191/1, 191/2, 192 से 198, 199/1, 199/2, 199/3, 200 से 204, 205/1 205/2, 206क---206ग, 207, 208, 209/1, 209/2 210, 211, 212/1, 212/2, 213 से 219, सड़क भाग, नाला भाग।

ग्राम कोटोड़ी से अजित प्लाट सं. :

1, 8 से 11, 12/1, 12/2, 13 से 35, 36/1, 36/2, 37 से 40, 106 से 118, 119/1, 119/2, 120 से 142, 256 से 260, 265, 266 सड़क भाग, नाला भाग।

सीमा वर्णन :

- क---घ : रेखा बिन्दु "क" से प्रारंभ होती है और प्लाट संख्यांक 42, 41/1---41/2, 41/3, 41/4, 40, 39, 38, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम आंगेवाड़ा से होकर जाती है और ग्राम आंगेवाड़ा तथा पटकाखेड़ी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है, फिर प्लाट सं. 171, 219, 217, 216, 215 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम पटकाखेड़ी से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।
- घ---ग : रेखा प्लाट संख्यांक 215, 214, 213, 212/1, 212/2, 211, 210, 205/1, 205/2, 204, 203, 202, 197, 196, 195, 194 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम पटकाखेड़ी से होकर जाती है, सड़क को पार करती है, फिर सड़क की उत्तरी सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है और ग्राम पटकाखेड़ी तथा कोटोड़ी, पटकाखेड़ी तथा कोटोड़ी की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।
- ग---घ : रेखा प्लाट सं. 140, 141, 142, 136, 1 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम कोटोड़ी से होकर जाती है, फिर नाले के पूर्वी किनारे के साथ-साथ जाती है, नाले को पार करती है तथा बिन्दु "घ" पर मिलती है।
- घ---ङ : रेखा नाले की बाहरी सीमा (पश्चिमी और दक्षिणी किनारा) के साथ-साथ ग्राम कोटोड़ी से होकर जाती है, फिर ग्राम कोटोड़ी और अदामा, पटकाखेड़ी और अदामा की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है तथा बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
- ङ---क : रेखा ग्राम पटकाखेड़ी और बोयगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ जाती है, फिर प्लाट सं. 52 से प्लाट संख्यांक 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम आंगेवाड़ा से होकर आगे बढ़ती है, फिर प्लाट सं. 43, 42 की बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/6/92-एल. एस्. डब्ल्यू.]

श्रीमती प्रेम लता मैत्री, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 19th August, 1996

S.O. 2467:—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, No. S.O. 1733 dated the 7th June, 1995, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 24th June, 1995, under sub-Section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 378.01 hectares (approximately) or 934.10 acres (approximately) in Mining Rights in the locality specified in the schedule annexed to that notification:

And whereas the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government:

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashtra, is satisfied that the mining rights to mine, quarry, bore, dig and search for win, work and carry away minerals in the lands measuring 378.01 hectares (approximately) or 934.10 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that the mining rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 378.01 hectares (approximately) or 934.10 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto are hereby acquired.

The Plan bearing number C-I(E) III/FR/588-0895 dated the 19th August, 1995, of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, J, Council House Street, Calcutta-700 001 or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra).

SCHEDULE

SAONER MINE NO. 1 EXTENSION BLOCK NAGPUR AREA

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA)

(Plan No. C-I(E) III/FR/588-0895 dated the 19th August, 1995)

Mining Rights

Serial number	Name of Village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Angewada	33	Saoner	Nagpur	10.65	Part
2.	Patkakhedi	33	Saoner	Nagpur	227.09	Part
3.	Kotodi	30	Saoner	Nagpur	140.27	Part
Total area :					378.01 hectares (approximately) or 934.10 acres (approximately)	

Plot numbers acquired in village Angewada :

38 to 40, 41/1-41/2-41/3-41/4, 42 to 44, 45/1-45/2-45/3-45/4-45/5-45/6-45/7-45/8-45/9-45/10, 52 Part.

Plot numbers acquired in village Patkakhedi :

121 to 129, 130/1-130/2, 131 to 137, 138/1-138/2, 139 to 143, 144/1-144/2, 145 to 164, 165/1-165/2, 166 to 172, 173/1-173/2, 174 to 188, 189/1-189/2-189/3, 190, 191/1-191/2, 192 to 198, 199/1-199/2-199/3, 200 to 204, 205/1-205/2, 206A-206B, 207, 208, 209/1-209/2, 210, 211, 212/1-212/2, 213 to 219, Road Part, Nalla Part.

Plot numbers acquired in village Kotodi :

1, 8 to 11, 12/1-12/2, 13 to 35, 36/1-36/2, 37 to 40, 106 to 118, 119/1-119/2, 120 to 142, 256 to 260, 266, 265, 266, Road Part, Nalla Part.

Boundary description :

A-B : Line starts from point 'A' and passes through village Angewada along the outer boundary of plot numbers 42, 41/1-41/2-41/3-41/4, 40, 39, 38, 41/1-41/2-41/3-41/4 and proceeds along the common village boundary of villages Angewada and Patkakhedi, then passes through village Patkakhedi, along the outer boundary of Plot numbers 171, 219, 217, 216, 215, and meets at point 'B'.

B-C : Line passes through village Patkakhedi along the outer boundary of plot numbers 215, 214, 213, 212/1-212/2, 211, 210, 205/1-205/2, 204, 203, 202, 197, 196, 195, 194, crosses road, then proceeds along the northern boundary of road and passes along the common village boundary of villages Patkakhedi and Kotodi, Pandharakhedi and Kotodi and meets at point 'C'.

C-D : Line passes through village Kotodi along the outer boundary of plot numbers 140, 141, 142, 136, 1, then passes along the eastern bank of Nalla, crosses nalla and passes along the common village boundary of villages Kotodi and Yerandgaon and meets at point 'D'.

D-E : Line passes through village Kotodi along the outer boundary (Western and Southern bank) of nalla, then proceeds along the common village boundary of villages Kotodi and Adasa, Pathakhedi and Adasa and meets at point 'E'.

E-A : Line passes along the common village boundary of villages Patkakhedi and Borgaon, then proceeds through village Angewada along the outer boundary of plot number 45/1-45/2-45/3-45/4-45/5-45/6-45/7-45/8-45/9-45/10, in plot number 52, then passes along the outer boundary of plot numbers 43, 42 and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/6/92-LSW]

Mrs. P.L. SAINI, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का. प्रा. 2463—केन्द्रीय सरकार, राजनामा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अन्वय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80% कर्म-चारीयुक्त ने हिन्दी का कार्यमाध्यम ज्ञान प्राप्त लिया है, अधिसूचित करती है :—

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

(रिफाइनरी व पाइपलाइन प्रभाग)

(i) बरौनी—कानपुर पाइपलाइन, शलाहबाद ।

(ii) मथुरा—जालन्धर पाइपलाइन, बिजवासन ।

(iii) मथुरा—जालन्धर पाइपलाइन, मथुरा ।

[सं. 11011/1/96—हिन्दी]

कृष्ण कान्त झा, उपनिदेशक (रा. भा.)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2463.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Public Sector Undertaking under the control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, the 80 per cent Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Indian Oil Corporation Limited

(Refineries and Pipelines Division)

(i) BARAUNI—KANPUR Pipelines, Allahabad.

(ii) MATHURA—JULIANDHAR Pipeline, Bijwasan.

(iii) MATHURA—JULIANDHAR Pipeline, Mathura.

[No. 11011/1/96-Hindi]

K. K. JHA, Dy. Director (OL)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996

का. प्रा. 2464 :— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अधिसूचना सं. का. प्रा. 1951, तारीख 6-7-1995 पृष्ठ संख्या 2729 से 2730 के द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइप लाइन विधान के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 15 जुलाई 1995 को उपलब्ध करा दी गयी थी :

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्वय में मध्यम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी वि-संगमों से रहित इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

राज्यीय : किशनगढ़	जिला : अजमेर	राज्य : राजस्थान		
ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र	वैकट्यर	सर्वेक्षण
1	2	3	4	5
वसुफ	76	0	15	51
	74	0	02	86
	77	0	05	28
	131	0	07	26
गोठियावा	97	0	06	75
	99/2	0	00	48

[संख्या आर-31015/1/93-आयल-1 (पार्ट-1)]

क. सी. कटोच, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 8th August, 1996

S.O. 2464.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1951, dated the 6th July, 95 page no. 2729 to 2730 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (acquisition of Right of User in Lands) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act,) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 15th July 1995;

And whereas the Competent Authority in pursuance to sub-section (1) of section 6 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : KISHANGARH District : AJMER State : RAJASTHAN

Name of Village	Khashra No.	AREA		
		Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Dhasook	76	0	15	51
	74	0	02	86
	77	0	05	28
	131	0	07	26
Gothiyana	97	0	06	75
	99/2	0	00	48

[No. R-31015/44/93-OR-I (Pt. -I)]
K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996

क्र.आ. 2465.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संस्थान की अधिसूचना संख्या का.आ. 1351, तारीख 20 मई, 1995 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आणव्य की घोषणा की थी ;

राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता की तारीख 24 मई, 1995 को उपलब्ध करा दी गयी थी ;

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में संलग्न अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने की वजाह, सभी विह्वलनों से रहित दृष्टियन आँकन कारपॉरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : अंजार	जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात
ग्राम का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्र
		हेक्टेयर आरे. मेट्रीआरे
1	2	3 4 5
मीठीरीहर	73/2	00 05 40
कुडवा	23/1	00 00 78
	23/2	00 01 86
	23/3	00 00 60
	139	00 09 00

[सं.आर-31015/39/93-ओ.आर.-1 (पार्ट-1)]

के.सी. कटोच, प्रवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 1996

S.O. 2465.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1351, dated 20 May, 1995 issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th May, 1995;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Anjar District : Kachchh State : Gujarat				
Name of village	Survey No.	Area		
		Hectare	Acre	Centiare
1	2	3	4	5
Mithirohar Chudva	73/2	00	05	40
	23/1	00	00	78
	23/2	00	01	86
	23/3	00	00	60
	149	00	09	00

[No. R-31015/39/93-OR-I (P-I)]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996

का.प्रा.2466.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संभालय की अधिसूचना संख्या का.प्रा. 1352, तारीख 20 मई, 1995 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अन्तर्गत आणव्य की घोषणा की थी ;

राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता की तारीख 24 मई, 1995 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में मध्य प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करता है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निश्चय देती है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होंगे की वजह से प्राधिकारों में स्थित इंडियन प्रायव कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची				
तहसील : अन्जार		ज़िला : कच्छ		राज्य : गुजरात
ग्राम का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्र		
		हेक्टेयर	आकर	सेंटीआरे
1	2	3	4	5
भानी चौरई	417 पेकी	00	27	00
	413	00	07	69
	411/1	00	01	10
	417 पेकी	00	09	45
	417 पेकी	00	20	70
	417 पेकी	00	31	50
	55	00	43	06
	392/1	00	04	00
	1003/22	00	12	78
	238/2	00	26	10
मांटी चौरई	1003/31	00	16	20
	209	00	05	40
	548	00	15	66
	550	00	09	18
	365/2	00	04	50
	380/2	00	01	95
	317	00	07	03
	318/1	00	01	79
	203	00	06	66
	2000/4 पेकी	00	53	28
भसाऊ	1599	00	37	08
	1605	00	10	80
	1653	00	37	80
	1790/1	00	39	96
	2000 पेकी	00	12	70
	1867	00	16	74
	1868	00	20	34
	1865	00	12	60
	2000 पेकी	00	14	40
	1864 पेकी	00	12	21
बोध	1864 पेकी	00	16	20
	1831	00	02	16
	1832/1	00	03	96
	860	00	28	08
	819	00	09	54
ठाडवाना	837	00	56	34
	841	00	17	10
	834	00	29	34
	560	00	21	60
	184	00	16	20
	835/1	00	03	42
	506 पेकी	00	19	26
	481	00	15	66
	396	00	26	90
	811	00	20	16
	477	00	00	10

New Delhi, the 8th August, 1996

1	2	3	4	5
गामखोवाली	246 पैकी	00	05	40
	250 पैकी	00	20	16
	253	00	07	40
	199	00	23	16
	200	00	16	20
	193	00	16	20
	137 पैकी	00	16	92
	135	00	36	72
	134	00	30	96
	131	00	16	20
	130 पैकी	00	23	94
	130 पैकी	00	33	48
	132	00	29	52
	195	00	27	00
गराणा	155	00	04	23
	158 पैकी	00	30	60
	157	00	04	68
	153	00	40	23
	131	00	19	44
	15	00	03	60
लाफडिया	1158	00	13	32
	825/1	00	02	16
	740	00	12	96
	713	00	06	57
	712 पैकी	00	34	92
	826/3	00	08	64
	823	00	14	58
	1082	00	06	66
	1091/4	00	05	94
	1089/1	00	03	96
श्रीवला	1149	00	14	40
	1150/3	00	09	90
	716	00	15	66
	712	00	15	12
	707/3	00	07	38
	711/2	00	03	15
	711/1	00	08	28
	699/1	00	13	50
	695/2	00	21	96
	375	00	37	26
श्रीवला	376	00	48	60
	346/2	00	16	90
	345/1	00	55	80
	346/3	00	15	66
	707/4	00	13	68
	708	00	12	48
	695/1	00	09	60
	380	00	19	08
	362	00	22	32
	353/1	00	24	12

S.O. 2466.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1352, dated 20th May, 1995 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th May, 1995;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are here by acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Bhachau District : Kachehh State : Gujarat

Name of village	Survey No.	Area		
		Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Nanichirai	417 Paiki	00	27	03
	413	00	07	69
	414/1	00	01	10
	417 Paiki	00	09	45
	417 Paiki	00	20	70
	55	00	43	06
	392/1	00	04	00
	417 Paiki	00	31	50
	1003/22	00	12	78
	238/2	00	26	10
Motichirai	1003/31	00	16	20
	209	00	05	40
	548	00	15	66
	550	00	09	18
	365/2	00	04	50
	380/2	00	04	95
	317	00	07	03
	318/1	00	01	79
	203	00	06	66
	2000/4 Paiki	00	53	28
Bhachau	1599	00	37	08
	1605	00	10	80

{नं. गार.-31015/39/93-खे. गार.-1 (पक्ष-1)}

क.सी. कटोव, धवर. मणिव

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1607/1	00	27	72		695/2	00	21	96
	1653	00	37	80		375	00	37	26
	1790/1	00	39	96		376	00	48	60
	2000 Paiki	00	12	70		346/2	00	16	90
	1867	00	16	74					
	1868	00	20	34		345/1	00	55	81
	1865	00	12	60		346/3	00	15	66
	2000 Paiki	00	14	40		707/4	00	13	68
	1864 Paiki	00	16	20		708	00	12	48
	1864 Paiki	00	12	24		695/1	00	09	00
	1831	00	02	16		380	00	19	08
	1832/1	00	03	96		362	00	22	32
						353/1	00	24	12
Vondh	860	00	28	08	[No. R-31015/39/93-OR-I (Pt.-b)]				
	819	00	09	54	K. C. KATOCH, Under Secy.				
Chhadavala	837	00	56	34	नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996				
	841	00	17	10	का.आ. 1167—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ-				
	834	00	29	34	लाभ (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962				
	560	00	21	60	(1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा				
	484	00	16	20	गया है) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत				
	835/1	00	03	42	सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संचालन की अधिसूचना संख्या				
	506 Paiki	00	19	25	का आ. 1353 तारीख 20 मई, 1995, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन				
	481	00	15	66	के लिए पाइपलाइन विद्युत के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न				
	596	00	36	91	अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अंतर्				
	811	00	20	16	गत की घोषणा की थी;				
	477	00	00	10	राजपत्रित अधिसूचना का प्रतियोगिता को तारीख 24 मई, 1995				
Samkhiali	246 Paiki	00	05	40	को उपलब्ध करा दी गई थी;				
	250 Paiki	00	20	16	उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में				
	253	00	07	20	महाम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;				
	199	00	23	16	केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह				
	200	00	16	20	समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट				
	193	00	16	20	भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,				
	137 Paiki	00	16	92	अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा				
	135	00	36	72	(1) द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न				
	134 Paiki	00	30	96	अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन करने की घोषणा				
	131	00	16	20	करती है;				
	130 Paiki	00	23	94	यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा				
	130 Paiki	00	33	48	प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि				
	132	00	29	52	के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने का बजाय सभी				
	195	00	27	00	विवर्तनों से रहित दृश्यत आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।				
Garana	155	00	04	23	अनुसूची				
	158 Paiki	00	30	60	तहसील : राजपुर				
	157	00	04	68	श्रिता : कवठ				
	153	00	40	23	राज्य : गुजरात				
	131	00	19	44	ग्राम का नाम				
	15	00	03	60	सर्व पक्षों				
Lakadiya	1158	00	13	32	क्षेत्र				
	825/1	00	02	16	हस्तक्षेप आरे सैटीआरे				
	740	00	12	96	1				
	713	00	06	57	2				
	712 Paiki	00	34	92	3				
	826/3	00	08	64	4				
	823	00	14	58	5				
	1082	00	06	66	चित्रा				
	1091/4	00	05	94	546/2				
	1089/1	00	03	96	589/2				
Lakadiya	1149	00	14	40	594				
	1150/3	00	09	90	00				
Shivalakha	716	00	15	66	21				
	712	00	15	12	17				
	707/3	00	07	38	08				
	711/2	00	03	15	24				
	711/1	00	08	28	64				
	699/1	00	13	50	61				

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
बिबीड- (जारी)	627/1	00	18	00		967 पैकी	00	12	96
	636	00	05	76		1222	00	05	64
	626	00	27	00		1223/2	00	11	52
	627/2	00	23	22					
	591	00	14	94	छोटापर	92/3	00	11	70
	601	00	14	94		94	00	02	32
	602	00	26	64		89	00	02	16
सई	114/3	00	36	72	बैकरी	65/1	00	23	04
	429/3	00	13	77		63 पैकी	00	58	86
	354	00	02	52		95/1	00	16	56
	358/2	00	02	70		94	00	36	00
	345/1	00	08	10					
	184	00	03	06	बैसापर	959	00	02	89
	183	00	06	30		954/2	00	12	24
	162	00	44	64		888/1	00	07	20
	163	00	50	49		887/3	00	08	64
बादलपूर	484	00	16	20		2171/3	00	21	6
छेहरा	159/2	00	23	94		2173/2 पैकी	00	12	60
	144 पैकी	00	19	44		2160/2 पैकी	00	09	54
	122/3	00	16	20		2085/1	00	10	35
	99	00	34	20		2082/2	00	09	00
	100/1	00	26	10		2082/2	00	12	15
	83/1	00	27	00		2078/2	00	14	22
	153/1	00	07	74		2076/1	00	21	60
	152/1	00	28	62		2074/5	00	15	12
	151	00	12	42		2073/5	00	17	61
	146/1	00	01	80		2070/6	00	13	95
किरियातगर	1223/1	00	08	84		960/1	00	03	06
	586 पैकी	00	07	40		960/2	00	17	21
	582/1	00	02	70		891/2	00	14	04
	583/3	00	08	16		888/4	00	23	22
	702/1	00	17	82		887/1	00	01	26
	702/2	00	09	90		882/3	00	16	02
	696/1	00	25	38		880	00	13	50
	742/1	00	12	60		871/4	00	02	79
	744/1	00	01	26		870	00	01	80
	808/1	00	03	96		865	00	19	26
	809	00	08	25		864/3	00	05	91
	806	00	02	51		863/3	00	04	77
	815	00	28	08		862/1	00	02	52
	812/2	00	27	00		2179/3	00	07	48
	594/2	00	04	50		2179/2	00	22	77
	592/2	00	32	04		2172/4	00	07	74
	592/1	00	24	12		2170/1	00	06	66
	591/5	00	10	98		2158/3	00	03	60
	589/3	00	14	10		2154/1	00	00	30
	595/1	00	16	20		2142/3	00	17	73
	698/2	00	01	62		2142/2	07	07	74
	814	00	06	66		2132/2	00	07	38
	817/1	00	18	90		2121	00	16	92
	948 पैकी	00	27	00		2123/1	00	10	26
	1229/3	00	01	44		2093/1	00	05	04
	1220/1	00	18	54		2097/2	00	01	62
	943	00	04	32					

1	2	3	4	5-
भीमसर (नारी)	2097/1	00	02	52
	2098/2	00	15	12
	2085/3	00	12	24
	2083/1	00	02	34
	2081/3	00	00	81
	2081/4	00	15	9
	2077/5	00	01	80
	2069/5	00	11	34
	888/2	00	09	36
	2084 पैकी	00	14	67
	2070/1	00	14	31
	2067/1	00	17	37
	2066	00	09	18
लाखागढ़	149/1	00	18	36
	175	00	46	62
	74 पैकी	00	19	80
	74 पैकी	00	28	98
	134	00	05	94
	163/3	00	01	80
	162	00	05	40
	164/3	00	03	78
	172/1	00	38	84
	76/1	00	19	80
	45	00	09	00
आडेमर	557	00	32	40
	563/2	00	30	42
	597/1	00	25	20
	555	00	04	14
वामणमरा	493	00	07	56
	88/2	00	05	40
	81 पैकी	00	28	80
	81 पैकी	00	32	40
	113 जुता	00	10	80
	116 जुता	00	23	58

[सं. अर.-31015/39/93-अं. आर-I (पार्ट-I)]

के.सी. कटोच, अधर मन्त्रि

New Delhi, the 8th August, 1996

S.O. 2467:—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 1353 dated 20th May, 1995 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th May, 1996;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Rapar	District : Kachchh	State : Gujarat		
Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectar	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chitrod	546/2	00	21	24
	589/2	00	17	64
	594	00	08	64
	627/1	00	18	00
	636	00	05	76
	626	00	27	00
	627/2	00	23	22
	591	00	14	94
	601	00	14	94
	602	00	26	64
Sai	114/3	00	36	72
	429/3	00	13	77
	354	00	02	52
	358/2	00	02	70
	345/1	00	08	10
	184	00	03	06
	183	00	06	30
	162	00	44	64
	163	00	50	49
	484	00	16	20
Badalpar	159/2	00	23	94
	144 Paiki	00	19	44
	122/3	00	16	20
	99	00	34	20
	100/1	00	26	10
	83/1	00	27	00
	153/1	00	07	74
	152/1	00	28	62
	151	00	12	42
	146/1	00	01	80
Kidiyanagar	1223/1	00	08	84
	586 Paiki	00	07	40
	582/1	00	02	70
	583/3	00	08	46
	702/1	00	17	82
	702/2	00	09	90
	696/1	00	25	38
	742/1	00	12	60
	744/1	00	01	26
	808/1	00	03	96
	809	00	08	25

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Kidiyanagar (Contd.)	806	00	02	52		2093/1	00	05	04
	815	00	28	08		2097/2	00	01	62
	812/2	00	27	00		2097/1	00	02	52
	594/2	00	04	50		2098/2	00	15	12
	592/2	00	32	04		2085/3	00	12	24
	592/1	00	24	12		2083/1	00	02	34
	591/5	00	10	98		2081/3	00	00	81
	589/3	00	14	40		2081/4	00	15	93
	595/1	00	6	20		2077/5	00	01	80
	698/2	00	01	62		2069/5	00	11	34
	814	00	06	66		888/2	00	09	36
	817/1	00	18	90		2084 PAIKI	00	14	67
	948 PAIKI	00	27	00		2070/1	00	14	31
	1229/3	00	01	44		2067/1	00	17	37
	1220/1	00	18	54		2066	00	09	18
	943	00	04	32	Lakhagadh	149/1	00	18	36
	967 PAIKI	00	12	96		175	00	46	62
	1222	00	05	64		74 PAIKI	00	19	80
	1223/2	00	11	52		74 PAIKI	00	28	98
Chhotapar	92/3	00	11	70		134	00	05	94
	94	00	02	32		163/3	00	01	80
	89	00	02	16		162	00	05	40
Vekra	65/1	00	23	04		164/3	00	03	78
	63 PAIKI	0	58	86		172/1	00	38	88
	95/1	00	16	56		76/1	00	19	80
	94	00	36	00		45	00	09	00
Bhimasar	959	00	02	88	Adesar	557	00	32	40
	954/2	00	12	24		563/2	00	30	42
	888/1	00	07	20		597/1	00	25	20
	887/3	00	08	64		555	00	04	14
	2174/3	00	21	60		493	00	07	56
	2173/2 PAIKI	00	12	60	Bambhansar	88/2	00	05	40
	2160/2	00	09	54		81 PAIKI	00	28	80
	2085/1	00	10	35		81 PAIKI	00	32	40
	2082/1	00	09	00		113 JUNA	00	10	80
	2082/2	00	12	15		116 JUNA	00	23	58
	2078/2	00	14	22					
	2076/1	00	21	60					
	2074/5	00	15	12					
	2073/5	00	17	64					
	2070/6	00	13	95					
	960/1	00	03	06					
	960/2	00	17	24					
	894/2	00	14	04					
	888/4	00	23	22					
	887/1	00	01	26					
	882/3	00	16	02					
	880	00	13	50					
	871/4	00	02	79					
	870	00	01	80					
	865	00	19	26					
	864/3	00	05	94					
	863/3	00	04	77					
	862/1	00	02	52					
	2179/3	00	07	38					
	2179/2	00	22	77					
	2172/4	00	07	74					
	2170/1	00	06	66					
	2158/3	00	03	60					
	2154/1	00	00	30					
	2142/3	00	17	73					
	2142/2	00	07	74					
	2132/2	00	07	38					
	2124	00	16	92					
	2123/1	00	10	26					

[No. R-31015/39/93-OR-I (Pt.-I)]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1996

का. घा. 2468.—केंद्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. घा. 1354, तारीख 20 मई, 1995, द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पड़ोस-पड़ोस विज्ञान के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आणविक की घोषणा की थी।

राजपट्टन अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 मई 1995 को उपलब्ध करा दी गई थी।

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में मंत्रालय प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

केंद्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हुआ गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाए सभी विलम्बों से रहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : सांवलपुर जिला : बनारसकाठा राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे सख्या	क्षेत्र		
		हेक्टेयर	आरे	सेंटीआरे
1	2	3	4	5
पापनगवा	1523	00	20	88
	785	00	15	30
	834	00	15	30
	835	00	17	64
	857	00	27	00
	887	00	29	34
	917	00	37	80
	919	00	37	80
	922	00	10	80
	862	00	20	52
	864	00	27	39
गरामडी	408	00	12	60
	376	00	16	38
	364	00	04	05
	347	00	21	24
	318	00	18	36
	356	00	18	00
	358	00	09	72
	360	00	12	96
सांवलपुर	665	00	06	48
	661	00	09	00
	657	00	21	60
	655	00	27	90
	498	00	16	20
	437	00	03	24
पूर	736	00	21	60
गजुसरा	184	00	05	40
	237	00	04	80
	238	00	00	20
वाधपुरा	49	00	32	04
मानपुरा	158	00	07	98
	157	00	03	36
कमालपुरा	118	00	11	88
	128 पैकी	00	17	46
	127 पैकी	00	11	34
वागही	513	00	02	92.50
	223/1	00	07	22
लखापुरा	121	00	08	64
	130	00	11	34
	132	00	24	60
	139	00	33	84

1	2	3	4	5
	140	00	26	10
	147	00	06	22
सावपुरा	257	00	04	59

[स. आर-31015/39/93-ओ.आर.-I (पार्ट-1)]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 1996

S.O. 2468.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1354, dated 20th May, 1995 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24th May, 1995;

And whereas the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

SCHEDULE

Tehsil : Santalpur District : Banaskantha State : Gujarat

Name of Village	Area			
	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Piprala	1523	00	20	88
	785	00	15	30
	834	00	15	30
	835	00	17	64
	857	00	27	00
	887	03	29	34
	917	00	37	80
	919	00	37	90
	922	00	10	0
	862	00	20	52
	864	00	27	39

1	2	3	4	5
Garambdi	408	00	12	60
	376	00	16	38
	364	0	04	05
	347	00	21	
	348	00	18	36
	356	00	18	00
	358	00	09	72
	360	00	12	96
Santalpur	665	00	06	48
	661	00	09	00
	657	00	21	60
	655	00	27	90
	498	00	16	20
	437	00	03	24
Pur	736	00	21	60
Rajusara	184	00	05	40
	237	0	04	80
	238	00	00	20
Vaghpura	49	00	32	04
Manpura	158	00	07	98
	157	00	03	36
Kamalपुरा	118	00	11	88
	128 PAIKI	00	17	46
	127 PAIKI	00	11	34
Varahi	513	00	02	92.50
	223/1	00	07	22
Lakhapura	121	00	08	64
	130	00	11	34
	132	00	21	60
	139	00	33	84
	140	00	26	10
	147	00	06	22
Sacpura	257	00	04	59

[No. R—31015/39/93-OR-I (Pt.-I)]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1996

का. प्रा. 2469.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्या 707 से 722 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. प्रा. 588 तारीख 02 मार्च 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में कुछ गलतियाँ हो गई हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित रूप में संशोधन करता है अर्थात्—
पृष्ठ संख्या 707

- (i) अनुसूची वाले भाग में "पश्चिमी-खजुरा" के स्थान पर "पुलिस थाना-खजुरा" पढ़ें।

(ii) गांव धोरादाहा के स्तम्भ सं. 3 में प्लॉट सं. 2225 के स्थान पर 2275 पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 712

(i) गांव रामनगर के स्तम्भ सं. 3 में प्लॉट सं. 069 के स्थान पर "609" पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 713

(i) गांव रामनगर के प्लॉट सं. 226 के सामने स्तम्भ 4 में "0" पढ़ें।

(ii) प्लॉट सं. 223 के सामने स्तम्भ 4 में "0" स्तम्भ 5 में "11" और स्तम्भ 6 में "58" पढ़ें।

(iii) प्लॉट सं. 218 के सामने स्तम्भ 4 में "0", स्तम्भ 5 में "5" और स्तम्भ 6 में "56" पढ़ें।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, जिसबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के इक्कीस दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार उक्त संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर के किसी अधिकार के अर्जित किए जाने के संबंध में या उस पर के किसी अधिकार के अर्जित किए जाने के संबंध में आशेष श्री विश्वनाथ बोस, मध्य प्राधिकारी, इंडियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया-बरीली, क्रूड पाइपलाइन परियोजना, पोस्ट आफिस हल्दिया रिफाईनरी, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार, इक्कीस दिन की उक्त अवधि, केवल इस अधिसूचना के माध्यम से संशोधित भूमियों के प्लॉट सं. और क्षेत्रों की बाबत, उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[सं. आर-31015/1/96—ओ. आर. —1]

के. सी. कटोच, अधर सचिव

New Delhi, the 12th August, 1996

S.O. 2469.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 588, dated the 2nd March, 1996 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), appearing at pages 722 to 734, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (acquisition of Right of User in Land) act, 1962 (50 of 1962), wherein the Central Government gave notice to its intention to acquire the Land specified in the schedule appended to the Notification;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the schedule appended to the said notification, namely :—

In the said notification at page no. 732 entry relating to village,—

(i) Valia in column 3, before Plot No. 554, for plot no. "647" read "649";

(ii) Kasigore in column 3 for plot no. "289" read "287".

Any person interested in any land in respect of which the above amendment has been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right in or over such land in terms of sub-section (1) of Section 5 of the said Act, to Shri Biswanath Bose, Competent Authority, Indian

Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Crude Pipeline Project, Haldia, Midnapur, West Bengal.

अनुसूची

Explanation: In respect of the lands plot nos. and areas amended through this notification only, the said period of Twenty one days in terms of sub-section (1) of Section 5 of the said Act, starts running from the date of notification is made available to the public.

[No. R-31015/1/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1996

का. आ. 2470.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी. एच. राविया, मामलातदार, राजकोट और श्री एस. के. ब्रह्मभट्ट, मामलातदार, रोधरा भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, मेन्ट्रुल इंडिया रिफाइनरी परियोजना को गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन नम्रम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-31015/21/95-ओ. आर. II]

के. सी. कटोच, सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 13th August, 1996

S.O. 2470.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises Shri D. H. Raviya, Mamlatdar, Rajkot, and Shri S. K. Brahmabhatt, Mamlatdar Ghodra, in respect of Central India Refinery Project of Bharat Oman Refineries Limited, to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, within the territory of the State of Gujarat.

[File No. R-31015/21/95-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1996

का. आ. 2471.—केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्य प्रदेश राज्य में बीना तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भारत ओमान रिफाइनरी लि. द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाए।

और कि ऐसी पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अन्वये अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अग्रगण्य घोषित करती है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिनियम की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में प्राप्ति विहित साधनमय प्राधिकारी, भारत ओमान रिफाइनरी लि., बी-5, हिरक सेंटर, नेहरू पार्क, वास्तपुर अहमदाबाद गुजरात-380015 को हर गेटा।

ता.सू.—बीमरी	जिला—मुरेदनगर	राज्य—	गुजरात	
गांव का नाम	सर्वेक्षण मंख्या	हेक्टर	क्षेत्र आर.	सेक्टर
1	2	3	4	5
जनशाली	86	0	3	90
	87	0	4	45
	105	0	22	20
	104	0	01	24
	107	0	0	51
	106	0	73	59
	110	1	3	50
	112	0	63	00
	114	0	31	80
	118	0	53	55
	122	0	39	60
	127	0	30	80
	126	0	3	65
	128	0	28	95
	129	0	07	92
	50	0	18	41
	49	0	10	80
	48	0	52	35
	53	0	18	90
45/वी सरकारी		0	61	50
जमीन				
कांठवा, अहमदाबाद		0	14	90
मार्ग,				
601 वैतगाड़ी, मार्ग		0	3	30
सरकारी जमीन		1	53	95

[फा. सं. आर-31015/20/96-ओ आर II]

के. सी. कटोच, सचिव

New Delhi, the 13th August, 1996

S.O. 2471.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by the Bharat Oman Refineries Limited.

And whereas that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of users in the lands described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may within twentyone days from the date on which the copies of the notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Bharat Oman Refineries Limited, B-5, Hirak Centre, Nehru Park, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat-380015.

S SCHEDULE

अनुसूची

Tehsil : LIMDI District : SURENDRANAGAR State : GUJARAT

Name of village	Survey No.	Area		
		Hectare	are	Centiare
1	2	3	4	5
Jansali	86	0	3	90
	87	9	4	45
	105	0	22	20
	104	0	01	24
	107	0	0	51
	106	0	73	50
	110	1	3	50
	112	0	63	00
	114	0	31	80
	118	0	53	55
	122	0	39	60
	127	0	30	80
	126	0	3	65
	128	0	28	95
	129	0	07	92
	50	0	18	41
	49	0	10	80
	48	0	52	35
	53	0	18	90
	45/P	0	64	50
Government Land				
Kandla-Ahmedabad Road		0	14	90
601 Cart Track		0	3	30
Government Land		1	53	95

[File No. R-31015/20/96-OR. II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

तई दिवसी, 13 अगस्त, 1996

का. आ. 2472—केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्य प्रदेश राज्य में बीना तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाईपलाइन भारत ओमान रिफाइनरी लि. द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और कि ऐसे पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः इस केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, उनमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अर्जा आशय घोषित करता है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां माध्याह्न जलता को उपपद्धकरी दिए जाने की तारीख से 21 दिन के भीतर, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि में पाईपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में आपत्ति निश्चित रूप से मन्त्र प्रार्थिका, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, बी-5 हाईक मेंटर, नेहरूपार्क, बम्बामपुर अहमदाबाद, गुजरात-380015 को कर सकेगा।

तालिका—श्रीलंका	जिला—अहमदाबाद	राज्य—गुजरात		
गांव का नाम	मन्त्र प्रार्थिका	क्षेत्र	क्षेत्र	क्षेत्र
	हेक्टेयर	आर.ए.	मैट्रिक	
1	2	3	4	5
बगोदरा	693	2	79	00
	726	0	71	40
	727	0	48	00
	722	0	23	50
	728/1	}	0	61
	728/2			
	721	0	3	68
	731	0	23	79
	720	0	20	25
	719	0	61	50
	738	0	78	60
	742/1	}	0	00
	742/2			
	747	0	11	20
	741	0	41	10
	753	0	41	10
	752	0	21	75
	755	0	18	90
	805	0	36	60
	802/1	}	0	64
	802/2			
	799	0	58	50
	854	0	03	00
	860	0	60	00
	866/1	0	70	65
	865	0	42	00
	864	0	35	05
	870	0	09	25
	825	0	35	10
	923	0	28	50
	922/1	}	0	85
	922/2			
	922/3			
	922/4			
	922/5			
	922/6	}	0	8
	391			
	913/1	}	0	75
	913/2			
	908	0	43	50
	905	0	45	50
	906	0	51	90
	31	0	72	00
	35/1	}	0	93
	35/2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156/1	}					99/1			
156/2						99/2		0	21
156/10						99/3			54
156/3						बेलगाड़ी मार्ग,		0	2
156/4						बगोदरा, भोवनगर मार्ग		0	8
156/5		1	00	50		बेलगाड़ी मार्ग		0	2
156/6						बेलगाड़ी मार्ग		0	4
156/7						बेलगाड़ी मार्ग		0	05
156/8						बेलगाड़ी मार्ग		0	11
156/9						नहर		0	17
93/1	}				मंडापुर	290		0	25
93/2						278		0	34
93/3						277		0	23
93/4						276		0	40
93/5						275		0	21
93/6						402		0	7
93/7						273		0	36
93/8						270		0	1
93/9						271		0	12
93/10						398		0	32
93/11						269		0	27
93/12						79		0	17
93/13						80		0	85
93/14						82		0	5
93/14/1						88		0	72
93/14/2								0	0
93/14/3						83		0	7
93/14/4		1	41	00				0	48
93/14/5						87		0	31
93/14/6						86		0	56
93/14/7						94		0	8
93/14/8						93		0	11
93/14/9						95		0	55
93/14/10						99		0	42
93/15						114		0	56
93/16						113		0	25
93/18						1033		0	41
93/19						119		0	18
93/21						111		0	16
93/22						120		0	27
93/23						108		0	31
93/24						107		0	43
+ 99/3						106		0	39
93/25						126		0	26
93/26						284 सरकारी जमीन		1	25
93/27						बेलगाड़ी मार्ग		0	04
93/28						मंडापुर मार्ग		0	06
93/29						620/वा. सरकारी जमीन		3	56
93/30						बेलगाड़ी मार्ग		0	2
123/1	}					बेलगाड़ी मार्ग		0	4
123/2									03
122		0	20	10					
120		0	52	50					
102/1	}								
102/2		0	8	36					
101/1	}								
101/2		0	5	00					
100		0	40	50					
98/1	}								
98/2		0	33	60					

[फाईल नं. अ.प्र. 31015/19/96 अथवा अ.प्र.--II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 1996

S.O. 2472.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by the Bharat Oman Refineries Limited.

And whereas that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of users in the lands described in the schedule annexed to this notification:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may within twentyone days from the date on which the copies of the notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Bharat Oman Refineries Limited, B-5, Hirak Centre, Nehru Park, Vastrapur, Ahmedabad (Gujarat)-380015.

SCHEDULE

Taluk : Dholka District : Ahmedabad State : Gujarat

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hec-tare	Acre	Cent-tare
1	2	3	4	5
Bagodara	693	2	79	00
	726	0	71	49
	727	0	48	00
	722	0	23	50
	728/1			
	728/2	0	61	37
	721	0	3	68
	731	0	23	79
	720	0	20	25
	719	0	61	50
	738	0	78	60
	742/1			
	742/2	0	0	80
	747	0	44	20
	741	0	41	10
	753	0	44	10
	752	0	21	75
	755	0	18	90
	805	0	36	60
	802/1			
	802/2	0	64	80
	799	0	58	50
	854	0	03	00
	860	0	60	00
	866/1	0	70	65
	865	0	42	00
	864	0	35	05
	870	0	09	25
	825	0	35	10
	923	0	23	50
	922/1			
	922/2			
	922/3	0	85	20
	922/4			
	922/5			
	922/6			

1	2	3		
391		0	8	70
913/1				
913/2		0	75	00
908		0	43	50
905		0	46	50
906		0	51	90
31		0	72	00
35/1		0	95	55
35/2				
156/1				
156/2				
156/10				
156/3				
156/4				
156/5		1	00	50
146/6				
156/7				
156/8				
156/9				
93/1				
93/2				
93/3				
94/4				
93/5				
93/6				
93/7				
93/8				
93/9				
93/10				
93/11		1	41	00
93/12				
93/13				
93/14				
93/14/1				
93/14/2				
93/14/3				
93/14/4				
93/14/5				
93/14/6				
93/14/7				
93/14/8				
92/14/9				
94/14/10				
93/15				
93/16				
93/18				
93/19				
93/21				
93/22				
93/23				
93/24				
99/3				
93/25				
93/26				
92/27				
93/28				
93/29				
93/30				
123/1		0	35	10
123/2				
122		0	20	40
120		0	52	50
102/1				
102/2		0	8	36

1	2	3	4	
Bagodara—contd.	101/1	0	45	00
	101/2			
	100	0	40	50
	981	0	33	60
	98/2			
	99/1			
	99/2	0	21	54
	99/3			
	Cart Track	0	2	80
	Bagodara, Bhavnagar Road	0	9	90
	Cart Track	0	2	10
	Cart Track	0	4	70
	Cart Track	0	05	85
	Canal	0	11	85
Mithapur	290	0	17	19
	278	0	25	20
	277	0	34	74
	276	0	23	25
	275	0	40	50
	402	0	21	83
	272	0	7	75
	270	0	36	69
	271	0	1	66
	398	0	12	45
	269	0	32	75
	79	0	27	30
	80	0	17	70
	82	0	85	47
	88	0	5	99
		+0	0	72
	83	0	7	22
		+0	0	48
	87	0	31	42
	86	0	56	29
	94	0	8	40
	93	0	11	60
	95	0	55	96
	99	0	42	99
	114	0	56	25
	113	0	25	80
	1033	0	41	25
	119	0	18	00
	111	0	16	34
	120	0	27	32
	108	0	31	33
	107	0	43	80
	106	0	39	60
	126	0	26	62
284	Government Land	1	25	40
	Cart Track	0	04	02
	Mithapur Road	0	06	00
	620/P	3	56	70
	Government Land			
	Cart Track	0	2	10
	Cart Track	0	4	03

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

का.आ. 2473.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, महाराष्ट्र, राज्य के भीतर, उक्त अधिनियम के अधीन, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1148 तारीख 29 मई, 1993 द्वारा प्राधिकृत श्री ए.एन. देशपांडे के स्थान पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई-मनमाड पाइपलाइन परियोजना के उप-कलेक्टर, नासिक श्री टी.के. बागूल को सक्षम प्राधिकारों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा सं. आर-25027/12/92-ओ आर II]

के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 1996

S.O. 2473.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises Shri T. K. Bagul, Deputy Collector, Nasik, Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai-Manmad Pipeline Project to perform the functions of the competent authority under the said Act within the territory of the state of Maharashtra in place of Shri A. N. Deshpande authorised vide notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, number S.O. 1148 dated, the 29th May, 1993.

[File No. R-25027/12/92-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1996

का.आ. 2474—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि हरियाणा राज्य में करनाल स्थित पानीपत रिफाइनरी से लिक्स्फाईड पेट्रोलियम गैसोज बोटलिंग प्लांट के बीच पेट्रोलियम के परिवहण के लिये इंडियन आयन कारपोरेशन द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाये;

और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है;

अतः, अथ, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, करते हुए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

[File No. R-31015/19/96-OR.II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इसकीस दिन के भीतर, भूमि के बोचो पार्सपलाईन बिछाने के संबंध में उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने सम्बन्धी लिखित में आधेप, श्री जे.के. झा, सक्षम प्राधिकारी, कोठी नंबर 1141, सैक्टर-13, अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा को कर सकेगा।

अनुसूची

तहसील : धरौडा जिला : करनाल राज्य : हरियाणा

गांव का हदबर्त मुस्ततिल सं. 0/ क्षेत्र

नाम सं. किला सं.

हैक्टयर आरे सेंटीमारे

1	2	3	4	5	6
गुडा	23	94			
		16	0	24	53
		17	0	08	85
		18	0	00	25
		21	0	09	36
		22	0	12	65
		23	0	12	64
		24	0	04	05
		95			
		25	0	00	51
		97			
		16/1	0	02	53
		16/2	0	10	12
		17	0	13	15
		23	0	00	51
		24	0	00	25
		98			
		6	0	11	13
		7	0	03	53
		11	0	03	54
		12	0	12	39
		13	0	12	90
		14/1	0	03	04
		14/2	0	07	08
		15	0	01	01
		19/2	0	00	05
		19/3	0	00	51
		20/1	0	07	58
		20/2	0	01	77
		99			

1	2	3	4	5	6
		2	0	01	77
		3	0	10	88
		4	0	12	90
		5	0	11	63
		8	0	01	77
		9	0	10	62
		10	0	12	63
		100			
		1	0	03	04
		129/21	0	00	51
		129/22	0	00	51
		129/23	0	00	51
बेगमपुर	24	1052	0	00	51
		1055	0	10	12
		1056	0	10	88
		1057	0	01	77
		1087	0	04	55
		1096	0	03	79
		1097	0	08	85
		1098	0	10	88
		1105	0	10	88
		1106	0	10	88
		1672/1	0	01	26
		1672/2	0	09	86
		1674	0	11	13
		1676	0	10	88
		1677	0	10	88
		1707	0	11	13
		1708	0	10	88
		1709	0	10	88
		1711	0	10	61
		1713	0	00	51
		1717	0	03	28
		1718	0	06	82
		1719	0	04	30
		1720	0	07	59
		1725	0	00	76
		1726	0	07	59
		1729	0	00	76
		1733	0	10	88
		1734	0	11	13
		1735	0	10	88
		1740	0	01	77
		1822	0	01	26
		1909	0	05	81
		1910	0	00	51
		1927	0	02	53

1	2	3	4	5	6
बेगम पुर—जारी	1942	0	00	15	
	1943	0	12	65	
	1944	0	06	32	
	1946	0	12	14	
	1947	0	06	32	
	1956	0	02	53	
	1957	0	10	12	
	1958	0	10	88	
	1959	0	00	76	
	1963	0	08	35	
	1964/1	0	05	56	
	1964/2	0	06	32	
	1965	0	01	77	
	1970	0	04	30	
	1971	0	08	35	
ढदलाना 25	92				
	24	0	01	01	
	25	0	12	90	
	93				
	13	0	10	62	
	14	0	05	06	
	18	0	04	05	
	19	0	14	42	
	20	0	03	04	
	21	0	10	88	
	22	0	00	10	
	98				
	2/2	0	00	05	
	3/1	0	03	29	
	3/2	0	07	33	
	4/1	0	06	32	
	4/2	0	04	05	
	5/1	0	01	01	
	8	0	03	29	
	9/1	0	01	01	
	9/2	0	12	65	
	10	0	06	32	
	11	0	08	85	
	99				
	15/1	0	08	09	
	15/2	0	01	01	
	15/3	0	01	01	
	16	0	05	31	
	17	0	14	42	
	18/1	0	00	10	
	18/2	0	00	25	
	23	0	17	96	
	24/1	0	01	01	

1	2	3	4	5	6
ढदलाना—जारी	24/2		0	04	81
	149		0	02	53

[का.सं. अर-31015/7/96-ओ अर.-1]

के.सी. कटोच, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 20th August, 1995

S.O. 2474.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum from Panipat Refinery to Liquified Petroleum Gases Bottling Plant at Karnal in the State of Haryana, pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein of laying of the pipeline under the land to Shri J.K. Jha, Competent Authority, Kothi No. 1141, Sector-13, Urban Estate, Karnal (Haryana).

SCHEDULE

Tehsil : Gharaunda District : Karnal State : Haryana

Name of village	Hadbast No.	Mustafeel/Killa No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Gudha	23	94			
		16	0	24	53
		17	0	08	85
		18	0	00	25
		21	0	09	36
		22	0	12	65
		23	0	12	64
		24	0	04	05
		95			
		25	0	00	51
		97			
		16/1	0	02	53
		16/2	0	10	12
		17	0	13	15
		23	0	00	51
		24	0	00	25
		98			
		6	0	11	13
		7	0	02	53
		11	0	03	54
		12	0	12	39
		13	0	12	90

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Gudhu—Contd.—						Begum Pur—Contd.—1942					
	14/1		0	03	04				0	00	15
	14/2		0	07	08				0	12	65
	15		0	01	01				0	06	32
	19/2		0	00	05				0	12	14
	19/3		0	00	51				0	05	12
	20/1		0	07	58				0	02	53
	20/2		0	01	77				0	10	12
	99								0	10	88
	2		0	01	77				0	00	76
	3		0	10	88				0	08	35
	4		0	12	90				0	05	56
	5		0	11	63				0	06	32
	8		0	01	77				0	01	77
	9		0	10	62				0	04	30
	10		0	12	63				0	08	35
	100										
	1		0	03	04	Dadlana 25 92					
	129/21		0	00	51				0	01	01
	129/22		0	00	51				0	12	90
	129/23		0	00	51						
Begam Pur 24											
	1052		0	00	51				0	10	62
	1055		0	10	12				0	05	06
	1056		0	10	88				0	04	05
	1057		0	01	77				0	14	42
	1087		0	04	55				0	03	04
	1096		0	03	79				0	10	88
	1097		0	08	85				0	00	10
	1098		0	10	88						
	1105		0	10	88				0	00	05
	1106		0	10	88				0	03	29
	1672/1		0	01	26				0	07	33
	1672/2		0	09	86				0	06	32
	1674		0	11	13				0	04	05
	1676		0	10	88				0	01	01
	1677		0	10	88				0	03	29
	1707		0	11	13				0	01	01
	1708		0	10	88				0	12	65
	1709		0	10	88				0	06	32
	1711		0	10	61				0	08	85
	1713		0	00	51						
	1717		0	03	28						
	1718		0	06	82				0	08	09
	1719		0	04	30				0	01	01
	1720		0	07	59				0	01	01
	1725		0	00	76				0	05	31
	1726		0	07	59				0	14	42
	1729		0	00	76				0	00	10
	1733		0	10	88				0	00	25
	1734		0	11	13				0	17	96
	1735		0	10	88				0	01	01
	1740		0	01	77				0	04	81
	1822		0	01	26				0	02	53
	1909		0	05	81						
	1910		0	00	51						
	1927		0	02	53						

[File No. R-31015/7/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1996

का.भा. 2475—केन्द्रीय सरकार, होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त द्वितीय अनुसूची में, “राजस्थान” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 13 धध तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
13 धधक	राजस्थान विश्वविद्यालय	(क) डाक्टर आफ मेडिसन इन होम्योपैथी मेटैरिया मेडिका (ख) डाक्टर आफ मेडिसन इन होम्योपैथी होम्योपैथिक फिलासफी (ग) डाक्टर आफ मेडिसन इन होम्योपैथी रेपरटोरी	एम.डी. (होम्यो) (मेटैरिया मेडिका) एम.डी. (होम्यो) (होम्यो) फिलासफी एम.डी. (होम्यो) (रेपरटोरी)	1994 से 1994 से 1994 से

[फा.सं. बी-27021/30/95-होम्यो.]

कमल दास, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना 20 दिसम्बर, 1973 का.भा. संख्या 76 के तहत भारत सरकार के राजपत्र के भाग 2 खंड 1 में अधिसूचित किया गया और तत्काल इसे संशोधित किया गया।

का.भा. 3325 दिनांक 04-11-1978

का.भा. 1517 दिनांक 26-02-1983

का.भा. 1418 दिनांक 12-03-1983

का.भा. 3099 दिनांक 21-06-1985

का.भा. 2048 दिनांक 24-03-1986

का.भा. 2270 दिनांक 24-05-1986

का.भा. 2449 दिनांक 01-08-1990

का.भा. 2501 दिनांक 01-08-1990

का.भा. 2002 दिनांक 21-08-1990

का.भा. 1182 दिनांक 21-08-1990

का.भा. 710 दिनांक 20-02-1992

का.भा. 891 दिनांक 05-03-1992

का.भा. 1210 दिनांक 23-04-1992

का.भा. 2669 दिनांक 24-09-1992

का.भा. 978 दिनांक 28-04-1993

का.भा. 1859 दिनांक 17-05-1993

का.भा. 1225 दिनांक 17-05-1994

का.भा. 2363 दिनांक 24-10-1994

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th May, 1996

S.O. 2475—In exercise the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Second Schedule under the heading 'RAJASTHAN' after the serial number 13DD and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely :—

1	2	3	4
13 DDA	University of Rajasthan	(a) Doctor of Medicine in Homoeopathy-Materia Medica	M.D. (Nom) (Mat red) From 1994 onwards
		(b) Doctor of Medicine in Homoeopathy Homoeopathic Philosophy	M.D. (Hom) (Hom Phil) From 1994 onwards
		(c) Doctor of Medicine in Homoeopathy Repertory	M.D. (Hom) (Rep) From 1994 onwards

[F.No. V. 27021/30/95- Homoeo]

KANWAL DASS, Under Secy.

Note :—The Principal Notification was notified in the Gazette of India Part 2, Section 1, vide S.O. No. 76 dated the 20th December, 1973 and subsequently amended by.

S.O. 3325 dated 04-11-1978

S.O. 1517 dated 26-02-1983

S.O. 1418 dated 12-03-1983

S.O. 3099 dated 21-06-1985

S.O. 2048 dated 24-03-1986

S.O. 2270 dated 24-05-1986

S.O. 2449 dated 01-08-1990

S.O. 2501 dated 01-08-1990

S.O. 2002 dated 21-08-1990

S.O. 1182 dated 21-08-1990

S.O. 710 dated 20-02-1992

S.O. 891 dated 05-03-1992

S.O. 1210 dated 23-04-1992

S.O. 2669 dated 24-09-1992

S.O. 978 dated 28-04-1993

S.O. 1859 dated 17-08-1993

S.O. 1225 dated 17-05-1994

S.O. 2363 dated 24-10-1994

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1996

का.आ. 2476:—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोर्वाणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना-2001 में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 की धारा 44 (1957 का 61) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 18-3-95 के नोटिस संख्या एफ.-9(5)/92-एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई आपत्तियाँ, और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—“उप जोन-1 (नरेला) में आने वाले 1.62 हेक्टेयर (4 एकड़), क्षेत्र जो उत्तर पृथ्वी दिक्ष में डी.एस. आई डी सी औद्योगिक सम्पदा से और पश्चिम में विद्यमान वि.नि.न. प्राथमिक विद्यालय और अलीपुर रोड से घिरा हुआ है के भूमि उपयोग को “विनिर्माण से सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं (विद्यालय) में बदला जाता है।

[सं. के-13011/18/94-डी डी-1 बी]

आर. विश्वनाथन, अवर सचिव

Whereas no objections/suggestions were received from the public with regard to the said proposed modifications.

And whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

“The land use of an area measuring 1.62 ha. (4 acres) falling in Sub-zone 1 (Narela) bounded by DSIDC Industrial Estate in the North, East & South and existing MCD Primary School and Alipur Road in the West, is changed from ‘Manufacturing’ to Public and Semi-public Facilities (School).”

[No. K-13011/18/94-DDIB]

R. VISHWANATHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का.आ. 2477:—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधोर्वाणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 की धारा 44 (1957 का 61) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 8.7.95 के नोटिस संख्या एफ.-3(27)/87-एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किये गये थे।

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यतः मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली/क्षेत्रीय विकास योजना हेतु बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त बृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :—“पूर्व में प्रोविन रोड, पश्चिम में अखिल भारतीय प्रसारण केन्द्र, वक्षिण में स्वच्छित पोषित डी.डी. ए. फ्लैट और उत्तर में रिहायशी क्षेत्र से घिरा प्लानिंग डिविजन “सी” (सिविल लाइन्स क्षेत्र) में पड़ने वाला लगभग 6836 वर्ग मी. क्षेत्र का भू-उपयोग “रिहायशी” से (सरकारी कार्यालय, ए.आई.आर.) के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

[सं. के-13011/6/95-डी.डी. 1 बी.]

आर विश्वनाथन, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

(Delhi Division)

New Delhi, the 25th July, 1996

S.O. 2476.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 were published with Notice No. F. 9(5)92-MP dated 18-3-95 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

New Delhi, the 5th August, 1996

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 11th July, 1996

S.O. 2477.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published with Notice No. F. 3(27)/87-MP dated 8-7-95 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

And, whereas no objections/suggestions were received from the public with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 6836 sq.mt. falling in Planning Division 'C' (Civil Lines area) bounded by Probyan Road in the East, All India Transmitting Station in the West, DDA SFS Flats in the South and residential area in the North is changed from 'residential' to 'Government Offices' (AIR)."

[No. K-13011/6/95-DDPB]

R. VISWANATHAN, Under Secy.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1996

का.आ. 2478:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी बुन्द ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

1. पवन हंस लिमिटेड, कावराती बेस कार्यालय, लखनौ।
2. इंडियन एयरलाइंस, लिमिटेड, राजकोट स्टेशन पश्चिमी क्षेत्र।

[संख्या ई 11011/8/95-हिन्दी]

रघुनाथ सहाय, निदेशक (राजभाषा)

S.O. 2478.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of Ministry of Civil Aviation and Tourism (Department of Civil Aviation) the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi :

- I. Pawan Hans Limited, Kavarati Base Office, Lakhadweep.
- II. Indian Airlines Ltd., Rajkot Station, Western Region.

[No. E. 11011/8/95-Hindi]

RAGHUNATH SAHAI, Director (O.L.)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1996

का.आ. 2479:—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि राज्य सभा में, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) बाबदांश (ग) के अनुसरण में श्रीमति रेणुका चौधरी, सदस्य, राज्य सभा का विधिवत चुनाव अधिनियम के उपबंधों के अध्वधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है।

[का.सं. 25012 (4)/91-रेशम]

एस. के. केशव, निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 7th August, 1996

S.O. 2479.—The Central Government hereby notify that the Rajya Sabha has, in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), duly elected Smt. Renuka Chowdhury, Member of Rajya Sabha, on 24th July, 1996 to serve as a member of the Central Silk Board for a period of three years subject to the provisions of the Act.

[F. No. 25012/4/91-Silk]

S. K. KESHA, Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1996

का.प्र. 2480.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/225/86-प्रार्थनार बी-आई]

पी. जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th July, 1996

S.O. 2480.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 10-7-96.

[No. L-12012/225/86-IRBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI
PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute 130 of 1986

In the matter of dispute between:

Anil Kumar & Har Prasad

203/33, Premganj, Cipari Bazar, Jhansi.

AND

Regional Manager,
State Bank of India,
Region IV The Mall,
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide reference order dt. 27-11-87 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

"Whether the action of the State Bank of India in terminating the services of S/Sri Anil Kumar and Har Prasad Ex-peon at their Chauk Jhansi Branch with effect from 1-3-85 is fair and justified. If not to what relief the workmen concerned are entitled."

2. In this reference there two workmen viz. Anil Kumar and Har Prasad. It is alleged that Anil Kumar worked from 27-1-81 to 28-2-85 in the Manik Chand Chowk Branch in Jhansi as peon whereas Har Prasad worked from 17-8-83 to 28-2-83 in the above mentioned branch as peon. It is further alleged that the two workmen actually performed duty but payment was made through fictitious names like Chhotey Lal Ram Din and Hiralal. Later on their services were brought to an end without compliance of section 25F, G and H of I.D. Act. Hence termination is bad in law.

3. The opposite part has filed reply in which it is alleged that Anil Kumar had worked from 27-1-81 to 24-4-81 for 89 days whereas Har Prasad had worked from 17-8-83 to 1-12-83 for 61 days. In this way they had not completed 240 day in 12 months. These appointments were made because of sudden absence of permanent staff. Section 25G and H are interlinked with section 25H of I.D. Act. As the appointment of the concerned workmen was for a fixed period it came to an end by efflux of time. Hence it is not a case of retrenchment as envisaged by section 2(c)(bb) of I.D. Act. By way of amendment it has been alleged that there is over-1959 GI/96—8

staffing in the bank. Further there had taken place settlement in 1987, 1988 and 1991 by virtue of it, the workers who had completed a particular number of days were entitled for appearing in examination and on the basis of which they were entitled for entry in service. The concerned workmen did not avail of this facility.

4. The concerned workmen have filed rejoinder and have also filed additional rejoinder to amended written statement.

5. In support of their case, the management have filed Ext. M-1 to M-9 which has been proved by their manager Vishal Chand Gupta by filing affidavit on 15-12-89. Further the evidence of another officer of the bank have been adduced. On the other hand the concerned workmen have given their affidavit.

6. Although Hari Prasad and Anil Kumar have stated that they were doing the work of permanent nature and further they had not performed duty in leave vacancies of any member of staff. Although on behalf of management Vishal Chand Gupta and V. K. Vareth had entered into witness box but they had not said anything regarding this point. Further if the concerned workmen would worked in leave vacancies certainly orders to that effect would have been passed. There would have been application for leave of the permanent member of staff and orders thereon passed by the competent authority appointing the concerned workmen in their place. Had those papers been filed it would have cleared the dust and controversy would have been resolved. Thus in the absence of these papers and because of evidence of concerned workmen is un rebutted, it is held that the concerned workmen had not worked in any leave vacancies or due to exigency of work. Instead they had worked on permanent nature of work.

7. Next question calls for determination is the consequence of settlement dt. 17-11-87, 27-10-88 and 9-1-91 copy of which are Ext. M-1, M-5 and M-6 respectively. Remaining papers relate to advertisement and appointment of certain candidates in pursuance of holding of test. According to this settlement the ex-employees of bank were to be given opportunity for appearing in test. It supported on behalf of the bank that two concerned workmen did not appear in test hence they have not right whatsoever. It will at once be noticed that all the three settlement are for the period subsequent to raising of instant industrial dispute. The concerned workmen are not the signatory to these settlements. It has been held in the case of Hari Fertilisers Sahupuri Vs. State of U. P. 1992 Lab. I. C. 1877 that when any settlement is arrived at between the Union and the management during the pendency of industrial dispute the concerned workman will not be bound by the same if his rights are adversely affected unless he is a signatory to it. Admittedly the concerned workmen are not signatory either of the three settlement. Hence the concerned workmen will be not bound by these settlement and consequently he was not obliged to appear in the test and further his case will not be adversely affected by holding of such test and subsequent appointment.

8. Both the concerned workman namely Anil Kumar and Har Prasad in their respective claim statement have stated that they have worked for the period as mentioned in the claim statement but their wages paid in different names. Anil Kumar in his cross-examination has stated that in the year 1981 he has worked for 89 to 90 days. He has further admitted that earlier had worked for 89 days. However he had has't to add that actually he had worked subsequently upto 1985 but wages were paid in different names. Ganga Ram has denied that he has worked upto 15-11-83. He has further stated that he had actually worked but his wages were paid in different names.

9. In rebuttal there is evidence of officer of the bank A. K. Bariva M.W. 1. He has denied that the concerned workman had beyond period as specified in the written statement. In his cross-examination he had admitted that he had no personal knowledge about the facts of the case. His evidence is based on the file relating to these two workmen but he has not filed any document. It further appears from the record that the concerned workmen had repeatedly requested the opposite party to file papers but the same could not be filed. I am not inclined to accept period for which the concerned workmen are said to have claimed the wages under the names of others. If that period is accepted it will be evident that the concer-

workmen had not completed 240 days in any calendar year. As such provisions of section 25F I.D. Act are not attracted.

10. Still it is admitted to both the parties that the two concerned workmen had actually worked with the opposite party as peon. In the case of Management of State Bank of Bikaner & Jaipur versus Their workman Civil Appeal No. 7029 of 1994 decided on 8-2-96, it has been held by Hon'ble Supreme Court that section 25G & H are independent of section 25F of I.D. Act. Further termination of services of those workmen who have worked for 89 days or more will be covered by the definition of retrenchment and section 2(b)(oo) of I.D. Act could not save it. In view of this authority I overrule the objection of authorised representative that section 25G and H of I.D. Act are interlinked with section 25F of I.D. Act. In the above mentioned authority the workers who had worked for 89 to 90 days were held to be entitled for protection of section 25 G and 25H of I.D. Act. In the instant case both the concerned workmen have alleged that after their termination Ashok Kumar was engaged but they were not given opportunities. There is no evidence that juniors to the concerned workmen were retained in service after the termination of their services. Hence the case of these workers under section 25H of I. D. Act is proved. It may be mentioned that in the above mentioned case Hon'ble Supreme Court has further held that peons are not covered by the examination conducted through Banking Recruitment Board, hence that cannot be a bar to the giving of relief under sec. 25H of I.D. Act.

11. Thus having been held that there has been breach of section 25H of I.D. Act, the termination of the two workmen is bad in law. There is no delay in seeking reference, hence they will be entitled for reinstatement. I have gone through the proceedings of the case and found that delay decision of the case has been caused because of lengthy procedure adopted by the concerned workmen. Hence, they should not be entitled for entire back wages. Instead ends of justice would be met if they are awarded back wages at rate at which they were lastly paid for the last five years from the date of publication of the award. They will get costs of the case Rs. 100/- each from the management.

12. Reference is answered accordingly.

Dated : 28-6-96.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

का.आ. 2481 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध तंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वय में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-96 को प्राप्त हुआ।

[संख्या एल-12012/334/94/आई.आर.बी. 2]
पी.जे. माइकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th July, 1996

S.O. 2481.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 25-7-1996.

[No. L-12012/334 '94-IR (B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri D. K. Nayak, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 39 of 1995

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Advocate

On behalf of the employers—Shri L. K. N. Bhagania, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 17th July, 1996

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012/334 '94-IR (B-II) dated the 2nd March, 1995.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Association of Punjab National Bank Employees, Patna on the management of Punjab National Bank, Patna for regularisation of services of Shri R. S. Singh as full-time Peon w.e.f. 28-12-1985 with consequential benefits is legal and justified? If so, what relief is the said workman entitled to?"

2. This is a very short reference and various facts are admitted. However, let me state the facts stated in the respective W.S.-cum-rejoinder of the parties. Here the management is Punjab National Bank and the workman belongs to the Association of the Punjab National Bank, Patna. The claim is for regularisation of the services of Shri R. S. Singh as Full time Peon with effect from 28-12-95 with other reliefs.

3. The case of the workmen as stated in the W.S. is that Shri R. S. Singh initially was appointed in a permanent vacancy but as temporary Safai Mazdoor at consolidated monthly salary of Rs. 100 and he was designated as temporary Safai Mazdoor being appointed on and from 28-9-1985. He was elevated to the confirmed Safai Mazdoor with effect from 11-12-86 on the basis of monthly payment. He used to work as full time worker and also as full time Peon against permanent vacancy continuously since 28-12-85 and thereby he put more than 240 days attendance in a calendar year to the satisfaction of all concern.

4. The concerned workman repeatedly requested and represented before the management for his regularisation as full time Peon with effect from 28-12-95 but to no effect and finding no other alternative a dispute was raised before the ALC (C) Patna with a demand for regularisation as full time Peon through the sponsoring union and there it was specifically mentioned that he used to perform the work of taking out ledger, cleaning table and counter, carrying register from one counter to another counter, and from one table to another table, stitching voucher, cash etc. opening and closing of cash, bringing postal tickets from post office job of despatch, distribution of dak, through peon book encashing N.S.C. from Post Office, doing the job of return in counter including other works which are scheduled for performing by the Peon including the work of purchase of stationery from the local market. In course of proceeding before the ALC (C) a committee was constituted for submission of Joint Inspection Report on the basis of the document and after Joint Inspection the said report was submitted to the ALC (C) and that revealed that the claim of the con-

cerned workman is justified but due to the adamant attitude of the management no fruitful result was obtained. So the present reference arose.

5. The management in their W.S. has raised the preliminary objection to the effect that the case is not an Industrial Dispute within the terms of Section 2(k) of the I. D. Act, 1947.

6. So far the merits are concerned it is stated that the Bank has entered into a conciliation settlement on 7-5-84 with the representative of the Punjab National Bank Employees Association regarding the fixation of pay of Part time sweepers for other issues related to them and the said settlement will reveal that Part time Sweeper shall be eligible for 1/3rd, then 1/2, then 3/4th and thereafter the full time scale of wages depending upon the number of hours and the area he is required to work in the bank. The said settlement will speak for itself which has been filed.

7. It is stated further that the said R. S. Singh was engaged as Part time sweeper at a consolidated salary of Rs. 100 with effect from 28-12-85 at Budha Colony branch office and his wage was enhanced to 1/2 scale of pay with effect from 11-6-86 and on completion of probationary period he was confirmed on and from 11-12-86.

8. It is admitted in their W.S. that on few occasions due to shortage of staff and considering the presence of customer's service aspect his service was taken as a Peon which was voluntary one and that does not create any right nor he can be regularised as full time Peon and all other statement to that effect are denied.

9. It is also stated that 25% of the vacancies should be earmarked for full time, Sweeper working in the region by making fresh recruitment of sub-staff. Therefore, it is difficult on the part of the management to bear the responsibilities of regularising him inspite of his drawing wages as Full Time Sweeper and his claim is unjustified.

10. In the instant case both the parties have filed their respective documents and the ALC (C)'s file was brought in this Court to reveal the initial stage of dispute between the parties.

11. The Bank management as well as the workman have also examined witnesses.

12. MW-1 Shri Birendra Kumar Sinha who is an employee of the Bank has admitted that the present workman initially was appointed as Part time Sweeper having consolidated wage of Rs. 100 per month at Budha Colony branch of Punjab National Bank and he was confirmed on 11-12-1986 and his wages was enhanced to the 1/2 of the wage scale. Thereafter he got 3/4th of the Wages Scale and from 25-1-1995 with effect from 1st September, 1994 but it is denied that the job of full time Peon was taken from him. It is stated that only the full time Sweeper can be appointed as subordinate cadre as per Banking Rules, and 25% of the vacancies are to be filled up from full time Sweeper. He has further stated that a part time sweeper is to be converted to as Full Time Sweeper then he can be absorbed as Full Time sweeper. In cross-examination he has admitted that the concerned workman gave some voluntarily services but at the same time he could not deny that no person can render any voluntary service without the authority either verbally or in writing. It is admitted that joint inspection took place between the management and the sponsoring union people and a report to this effect was submitted after joint inspection and that reflects the correct state of affairs. Inspite of that he has deposed that the concerned workman never worked as Full time Peon on and from December, 1985.

13. The concerned workman Shri R. S. Singh had deposed in the same tune as it has been deposed by MW-1 about the work of Sweeper but he has added that he also worked as Peon in the said Bank and that will appear from the Joint Inspection Report when the ALC (C), Patna had asked to conduct the joint inspection by the person of the management as well as the sponsoring union. It is also in his statement that he is continuously performing 240 days in a calendar year as Peon which entitled him to be regularised as Peon with consequential benefits. It is admitted by him that he filed the case before the Labour Court on 13-1-94.

14. In the instant case some facts are admitted which can be summarised in the following manner.

15. The concerned workman was initially appointed as Sweeper at a salary of Rs. 100 per month in the form of consolidated nature on 28-9-85 and thereafter from time to time he was elevated and now he is holding the position as Sweeper entitling him to get wages to the extent of 3/4th of the scale of the Full Time Sweeper. It is also not disputed that sometimes he used to perform the job of Peon but this was his voluntary act.

16. I cannot but comment that the witnesses may tell lie but the documents and the circumstances cannot.

17. In this case the vital and most important document is the Joint Inspection report which was performed being agreed by both the parties while the matter was pending before the ALC (C) and that was signed by all concern and that has been exhibited in the instant case which is marked Ext. W-1.

18. No doubt the management has also exhibited certain documents for the establishment how the settlement took place for service scheme of Sweeper.

19. At the very outset I cannot but comment if this workman to be considered as a Sweeper obviously he is guided as per settlement filed by the management took place between the management and the workmen but if it is found that from any point of time he started working as Peon and he completed 240 days work in a calendar year as per rules his claim cannot be denied.

20. It is not the case of the management that the Joint Inspection Report is an outcome of partiality or out of record but it is admitted that the same was done and being accepted by the representative of the management as well as the representative of the sponsoring union signed it and the same was filed before the ALC (C). From the said Joint Inspection Report marked Ext. W-1 it clearly goes to show that on perusal of the relevant records maintained in the Bank office it appears that the concerned workman performed the job of the Peon between 1990, 1991 and 1992 and 1993 by way of taking out ledger, clearance works, mail works and other works which are scheduled to be performed by the Peon for a number of days in a month which exceeds 240 days in every calendar month. If that be so I fail to understand why the claim of the said person be denied by the management inspite of taking services of a Peon though he is a sweeper according to them and as per record.

21. We cannot ignore the fact that in course of hearing of the dispute between the Bank management and the workman it has come to the notice of this Tribunal very glaringly that the management Bank mostly are in the habit of taking jobs from the oppressed class of employees though they do not forego of making agitation for their claim inspite of the fact that the said poor employees are even forced to perform the job which are not within the ambit of his job and as and when after lapse of time raises their voice the management rushes to throttle their claim and by spending a lot of money opposes out the case of their utmost ability to deprive the legitimate claim of a workman.

22. In this case I cannot but comment that inspite of the Joint Inspection Report and inspite of the reflection that this workman performed the work of Peon as Sub-staff from 1990 to 1993 and without challenging the said report they did not settle the matter before the ALC (C) and their adamant attitude rather forced to the workman and his union to raise this dispute through the Ministry in the form of reference and again here inspite of existence of such report they are fighting even from the stage of appointment and till now this goes to show that there is a group of officers or an officer who for the reasons best known to him or them get pleasure by way of depriving the sub-staff who are much lower in category with comparison to the status of other high officials of the management.

23. I think that inspite of existence of Joint Inspection report showing that the concerned workman worked as Peon for a pretty long time when the management is eager to fight out the case. It is desirable that the person for whom this case is being dragged he should be saddled with cost

2. श्रमिक युनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह बताया गया है कि श्रमिक का चयन विपक्षी द्रैफ में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार किया गया था व नियोक्ता द्वारा 8-3-86 को एक प्रोत्साहक पत्र श्रमिक के खिलाफ जारी किया जाकर विभागीय जांच की गई व विभागीय जांच के पश्चात् श्रमिक को दिनांक 30-5-89 के आदेश से सेवाभक्त किया गया। इस सेवाभक्ति के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विभागीय जांच श्रमिक के खिलाफ नियमानुसार व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं की गई, उपलब्ध साक्ष्य से श्रमिक के खिलाफ कथित दुराचरण का आरोप प्रमाणित नहीं होता व यदि

आरोप को प्रमाणित माना जाये तब भी उसकी प्रकृति को देखते हुए जो दण्डादेश श्रमिक के खिलाफ पारित किया गया है वह अत्यधिक व अन्यायपूर्ण है। अनुसूची यह सांगता करता है कि श्रमिक को विद्युत सम्पूर्ण वेतन सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाये।

3. नियोजक ने इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि श्रमिकों को बैंक में नियमित रूप से बैंक का पत्र पर निवेदन किया गया था, 9-4-86 को एक दोपहरीय पत्र श्रमिक को इस आधार पर जारी किया गया कि उसके पूर्व में जहां नौकरी की थी, उसके विवरण जानबूझकर सेवा में आते समय प्रार्थना पत्र में उल्लिखित नहीं किये जाँ कि बैंक के रेगुलेशन के तहत दुराचरण की परिभाषा में आता है। यह भी स्वीकार किया गया है कि श्रमिक के खिलाफ जांच निष्पत्ति के बाद भी प्रक्रिया से कोई भी व श्रमिक को अपनी प्रतिष्ठा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर श्रमिक के खिलाफ दुराचरण के आरोप को साबित माना गया व इसी आधार पर बैंक के सर्विस कोड के नियम 10 के अनुसार श्रमिक की सेवाएं आरोपित आदेश से समाप्त की गई। श्रमिक ने अपने क्लेम में सेवा मुक्ति का आदेश दिनांक 30-5-89 को पारित होना बताया है कि जबकि नियोजक के जवाब के अनुसार यह आदेश 30-5-87 को जारी किया गया था। जो साक्ष्य व प्रलेख प्रस्तुत हुए हैं उनके देखते हुए नियोजक का यह कथन सही है। विवेक विवरण में नियोजक द्वारा यह आपत्ति की गई है कि यदि विभागीय जांच को अनुचित व अर्थहीन माना जाये तो नियोजक को दुराचरण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये। श्रमिक का ओर से नियोजक के जवाब का प्रत्यक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। नियोजक द्वारा संबंधित जांच का सम्पूर्ण प्रलेख न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों की बहस प्रारंभ में विभागीय जांच की गूढ़ता व औचित्यता के संबंध में सुनी गई। दिनांक 17-1-95 के आदेश से यह अतिनिर्धारित किया गया कि श्रमिक के खिलाफ की गई उक्त जांच निष्पत्ति के अनुसार व नैतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। इस आदेश को श्रमिक द्वारा अपील के जरिये चुनौती नहीं दी गई है अतः यह आदेश अतिरिक्त ही चुका है।

4. धारा 11-ए के तहत सेवा स्थिति के आदेश में संशोधन या कमी करने के संबंध में दोनों पक्षों की प्रस्तुत बहस सुनी गई व पचासवीं पर उपलब्ध सामग्री व दोनों पक्षों को ओर से प्रस्तुत निर्णयों का अध्ययन किया गया। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी बहस में यह बताया है कि आरोप जिस रूप में श्रमिक के खिलाफ प्रमाणित माना गया है वह तथ्य सम्पूर्ण अभिलेख को देखते हुए सही नहीं है व इसके अलावा भी यदि आरोप को इसी रूप में प्रमाणित माना जाये तब भी अन्य सम्बन्ध परिस्थितियों को व श्रमिक के सेवा अभिलेख को देखते हुए सेवा स्थिति के आदेश को न्यायोचित व सन्तुष्ट नहीं माना जा सकता। श्रमिक के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी किया गया था उसका मार तड़क कि प्रस्तुत

अर्थ परीक्षा में शामिल होने के लिए जो निर्धारित प्रश्न-उत्तर प्रस्तुत किया था उसमें पूर्ण नियोजक के संबंध में जानकारी अन्य के रूप में प्रस्तुत की थी जहाँ नोट की जांच में यह पाया गया कि श्रमिक ने माननीय मैन्स कोऑपरेटिव स्टोर्स में नौकरी की थी व उस नौकरी के दौरान उसे 18-6-79 को किसी जांच कार्यवाही में सेवा में निर्वासित किया गया था। व बाद में 27-5-80 के आदेश से उसे सेवा स्थान किया गया। आरोप पत्र के अनुसार श्रमिक ने उक्त सूचना बैंक में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने समय जानबूझकर व परोक्ष उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं की थी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर व प्रलेख के आधार पर जांच अधिकारी ने इस आरोप को साबित माना है व इसी के अनुसार श्रमिक के खिलाफ सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया गया था। जो मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है उसे देखते हुए जांच अधिकारी के निर्णय को आधारहीन या अनुचित नहीं कहा जा सकता। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने इस बिन्दु को बहस में प्रस्तुत नहीं किया है। श्रमिक ने आरोप पत्र के निखित जवाब में यह स्पष्टीकरण दिया था कि नारंगील उपभोक्ता भंडार में उसकी सेवा अस्थायी थी, उसका संबंध बैंक की सेवा में नहीं है तथा निलम्बन से पूर्व श्रमिक ने अपना त्याग पत्र वहां प्रस्तुत कर दिया था इसलिए सम्भावनापूर्वक पूर्व नियोजक के तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये व उसमें कोई भी परोक्ष उद्देश्य नहीं था। श्रमिक का यह भी कथन है कि उसके खिलाफ जो जांच नारंगील उपभोक्ता भंडार द्वारा की गई थी उसमें उसके खिलाफ गवत का या विनीत अनिर्णयता का कोई भी आरोप नहीं था। जवाब के साथ श्रमिक ने दो प्रलेख भी प्रस्तुत किये थे जो प्रार्थना डी-1 व डी-2 है। दोनों प्रलेख नारंगील उपभोक्ता भंडार के नियोजक के संबंध में हैं। इनमें यह प्रकट होता है कि जांच में श्रमिक के खिलाफ भण्डार की जांच का गवत करने का या उसका दुरुपयोग करने का कोई भी मामला नहीं पाया गया। इसके अलावा भी जो प्रलेख पचासवीं पर उपलब्ध है उसमें भी यह प्रकट होता है कि बैंक द्वारा श्रमिक के खिलाफ कोई दारिद्र्यक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी। श्रमिक ने उपभोक्ता भंडार के संबंध में जांच कार्यवाही में यह प्रतिश्रुति की थी कि किसी अन्य धर्मास्त की गलती से वह स्टॉक ब्रुक नहीं रूप में बैंक नहीं करने में सामान में कमी हुई थी। श्रमिक के खिलाफ भंडार द्वारा नियम 32 के तहत सेवा मुक्ति (टर्मिनेट) करने का आदेश 9-3-83 को जारी किया गया था। बैंक में परीक्षा हेतु जो फार्म श्रमिक ने प्रस्तुत किया था उसके क्लेम सं. 13 में पूर्व नियोजक के विवरण की जगह श्रमिक द्वारा "नोट" शब्द का उल्लेख किया हुआ है। इसी प्रकार सेवा में प्रवेश के समय जो द्वारा फार्म श्रमिक में भरवाया गया उसमें भी पूर्व नियोजक के कोई विवरण अंकित किये हुए नहीं हैं। विभागीय जांच में उपलब्ध साक्ष्य व प्रलेख में जो निष्कर्ष निकलते हैं वे इस प्रकार हैं कि श्रमिक ने सेवा में आने के लिए परीक्षा हेतु जो फार्म प्रस्तुत किया उसमें पूर्व नियोजक के विवरण नहीं भरे थे, परिस्थितियों में यह मानने का भी आधार है कि यह सूचना उसे जानबूझकर बैंक की प्रेषित नहीं की थी, यह प्रमाणित होता है कि पूर्व

नियोजन में श्रमिक के खिलाफ गबन का या भण्डार की राशि के दुरुपयोग का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ था, बैंक के सेवा नियमों के अनुसार उक्त सूचना बैंक की प्रेषित नहीं करना गंभीर दुराचरण की परिभाषा में आता है इसलिए जांच अधिकारी द्वारा आरोप को जिम रूप में प्रमाणित माना गया है यह विनिश्चय उचित एवं नहीं है। भण्डार द्वारा श्रमिक को हटाने का मामला डिमिसल का नहीं है इसलिए श्रमिक किसी अन्य नियोजन के लिए इसी आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकता व इस प्रकार की बहम नियोजक की ओर से भी नहीं की गई है। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि जिस प्रकार की सूचना श्रमिक द्वारा बैंक में छुपाई गई थी उसे देखते हुए अपेक्षित वण्टादेश न्यायोचित है। उन्होंने इस संबंध में के०एन० गोपालन बनाम स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावनकोर 1980 (1) आई०एल०आर० (केरल) 81 के निर्णय को संदर्भित किया है। उस मामले में श्रमिक द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्रमिक की सेवा मुक्ति के आदेश को इस आधार पर उचित माना गया कि उसने जानबूझकर बैंक की नौकरी में प्रवेश के समय यह घोषणा की थी कि उसने पूर्व में कहीं भी नौकरी नहीं की थी। उस मामले को प्रस्तुत प्रकरण से इस रूप में प्रभेदित किया जा सकता है कि श्रमिक ने निश्चित रूप से फार्म में यह उल्लेख नहीं किया है कि उसने पूर्व में कहीं भी नौकरी नहीं की थी बल्कि पूर्व नियोजन की सूचना को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित नहीं किया है। इसके अलावा बहम के समय नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह पूछा गया कि यदि श्रमिक के पूर्व नियोजन को जानकारी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत की जाती तो क्या वह उस आधार पर बैंक में सेवा के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाता व उस संबंध में नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने ऐसा कोई भी नियम या निर्णय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने मुख्य रूप से बहस में इस बात पर जोर दिया है कि बैंक सेवा में इमानदारी व सही आचरण का अधिक महत्व है इसलिए श्रमिक के खिलाफ जो आरोप प्रमाणित हैं उसे देखते हुए उसे सेवा में रखना बैंक के हित में नहीं है।

5. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने धारा 11-ए के तहत यह तर्क दिया है कि श्रमिक के खिलाफ आरोप के संबंध में जो भी परिस्थितियाँ अभिलेख पर आई हैं उन्हें व बैंक की सेवा में उसके खिलाफ अन्य कोई शिकायत नहीं होने के तथ्य को देखते हुए सेवा मुक्ति का आदेश तथ्यात्मक रूप से अन्यायिक है तथा उससे श्रमिक का पारिवारिक व सामाजिक जीवन बरबाद होने की संभावना है। उनका यह भी कथन है कि वर्तमान में श्रमिक करीब 9 वर्ष से नियोजन से बाहर है व इस कारण वह आर्थिक व मानसिक रूप से काफी दण्ड प्राप्त कर चुका है। उनका यह भी तर्क है कि नार्मल उपभोक्ता भण्डार के मामले में जांच से जो तथ्य आये हैं उनको देखते हुए श्रमिक की वैधमानी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है व जो भी रंगार में कमी हुई थी यह अधिकतम उसकी लापरवाही का प्रतीक हो सकता है।

उनका तर्क है कि मामले को सम्पूर्ण परिस्थितियों व श्रमिक के आर्थिक व सामाजिक परिवेश को देखते हुए सेवा मुक्ति के स्थान पर अन्य किसी दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय हित में उचित होगा। अपने तर्क के संबंध में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय मानादीन गर्ग बनाम राजस्थान राज्य भिविल ग्रीन सं० 2719/91 प्रस्तुत किया है व इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय आर०एम०आर०टी०सी० बनाम श्रीगम यादव इन्ड्यू०एल०सी० (राज०) 1995 पेज 16 का अवलम्ब भी लिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के तथ्य राजस्थान उच्च न्यायालय सेवा के अधिकारी से संबंधित है जिसने साक्षात्कार के लिए प्रार्थना पत्र में यह सूचना नहीं दी थी कि उनके खिलाफ कोई दण्डित मामला न्यायालय में विचारधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री मानादीन गर्ग को इस आधार पर सेवा में लेने का आदेश दिया है कि उनके खिलाफ विचारधीन मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तकनीकी आधारों पर संस्थित किया गया था व इस कारण प्रार्थना पत्र में इस सूचना को छुपाने का दुराचरण नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय में धारा 11-ए की शक्तियों के उपयोग के वास्तविक विवेचन करते हुए परिवहन निगम के उस परिचालक को सेवा में लेने का आदेश दिया गया था जिसने खिलाफ पैसे लेकर बिना टिकट बस में यात्रियों को ले जाने का आरोप था। दोनों निर्णयों में प्रतिपादित विधि मिष्ठान्तों व उनके तथ्यों व परिस्थितियों तथा इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है कि श्रमिक के खिलाफ पारित सेवा मुक्ति का आदेश अनुचित व अन्यायिक है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994(1) एम०सी०सी० 573 आर०एल०आर०टी०सी० बनाम भागयो-मल व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां श्रमिक के खिलाफ दुराचरण का आरोप प्रमाणित हो उस स्थिति में श्रमिक को सेवा में बहाल करने समय बकाया वेतन स्वीकृत करने के आदेश दिए नहीं हो सकते। इन विधि मिष्ठान्तों को देखते हुए श्रमिक सेवा में पुनः आने की स्थिति में कोई भी बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। श्रमिक के खिलाफ जो आरोप प्रमाणित माना गया है उसे व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सेवा मुक्ति के आदेश के स्थान पर श्रमिक को सचदी प्रभाव से चार वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रकट होता है।

7. निर्देशित विवाद का अधिनियम इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक राम रतन के खिलाफ नियोजक केनरा बैंक द्वारा दिनांक 30-5-87 को जो सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया गया है वह तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित नहीं है व इस कारण सेवा मुक्ति के आदेश को अपास्त किया जाकर श्रमिक को सचदी प्रभाव से चार

वर्षिक वेतन बढ़ियाँ रोकने के दण्ड में दण्डित किया जाता है तथा सेवा भत्ता की तिथि से पुनः सेवा में आने की तिथि तक का वकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

४. अवार्ड आज दिनांक 2-4-96 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के. एन. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

का.आ. 2483—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्बंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/106/95/आई.आर.बी. 2]

पी. जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th July, 1996

S.O. 2483.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 25-7-96.

[L-12012/106/95-IR(B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अन्तर्बंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 56/98

रेफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के
आदेश संख्या एल-12012/106/95 दिनांक
25-8-95

महामंचिव, सेंट्रल बैंक कर्मचारी यूनियन
(राज.) सी/ओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
संसार चन्द्र रोड, जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश, श्री के. एन. व्यास,
आर. एच. जे. एस.
प्रार्थी की ओर से: श्री बी. के. छावड़ा
अप्रार्थी की ओर से: श्री जी. एस. दुवे

अवार्ड दिनांक: 2-2-96

अवार्ड

श्रमिक स्वयं व उसके प्रतिनिधि श्री बी. के. छावड़ा तथा नियोजक की ओर से श्री जी. एस. दुवे उपस्थित। दोनों पक्षों ने उनके द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा लिखित में पेश किया जिस पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। राजीनामा दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है। अतः प्रस्तुत राजीनामों को अभिप्रमाणित किया गया। राजीनामों की शर्तों के अनुसार विवाद में अधिनिर्णय पारित करने के आदेश दिये जाते हैं जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जावे। समझौते का एक प्रतिलिपि अधिनिर्णय के साथ संलग्न की जावे जो अधिनिर्णय का भाग होगा।

के. एन. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

का.आ. 2484—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक श्री गंगा नगर के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अन्तर्बंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-96 को प्राप्त हुआ।

[सं. एल-12012/755/87/डी-2(ए)/आई.आर.बी.-2]

पी. जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th July, 1996

S.O. 2484.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank Staff Shri Ganga Nagar and their workmen which was received by the Central Government on 25-7-1996.

[No. L-12012/755/87-DII(A) IR(B-II)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अन्तर्बंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 63/1988

रेफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश

सं. एन-12012/755/87-बी-II (ए) दि. 22-9-88
महासचिव, अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज
एगोसिपेशन, 898, नई सड़क, चांदनी चौक, नई दिल्ली
एवं

पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज एगोसिपेशन, किशनपोर
बाजार, जयपुर प्राप्ति

बनाम

रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, गौशाला रोड,
श्रीगंगानगर —अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एन. व्यास, आर.एच.जे.एम.

अप्रार्थी की ओर से: श्री सी.एन. भारद्वाज

अप्रार्थी की ओर से: श्री त्रिवोक्त सिंह

दिनांक: 28-11-1995

अर्थात्

केन्द्र सरकार ने निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु निर्देशित
किया है:

“क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र की श्री मावो
राम शर्मा को 1-4-79 से सेवा समाप्त करने और
प्रबंधतन्त्र द्वारा 1-4-79 से 13-10-79 तक की
खाती रहने की अवधि को लगातार सेवा के रूप में
नियमित करने से इंकार करने तथा इस अवधि के
लिए मजदूरी के भुगतान तथा उसकी नियुक्ति की
तारीख को 3-4-78 मानते हुए वेतन वृद्धि के साथ
साथ अन्य लाभ देने से इंकार करने की कार्यवाही
न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मचारि किस अनुतोष
का हकदार है?”

2. श्रमिक यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह अभिकथन
किया गया है कि श्रमिक ने अस्थाई रूप से स्थाई कर्मचारियों
के अवकाश पर रकने की स्थिति में सीकर जिले में विपक्षी बैंक
की विभिन्न शाखाओं में 3-4-78 से 31-3-79 के बीच
249 दिन कार्य किया था। उसके पश्चात् उनकी सेवाओं
द्वारा 25-7-78 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे
वाद में अधिनियम संशोधित किया जाएगा) के प्रावधान को
पालना के दिना समाप्त की गई। श्रमिक को बैंक सेवा में
स्थाई नियुक्ति 8-10-97 को दी गई व उसे विपक्षी शाखा
की बिमाऊ शाखा में 14-10-79 को ड्यूटी जोड़न की।
श्रमिक का कथन है कि 1-8-77 को सम्पादित हुए विपक्षीय
समझौते के खण्ड-6 के अनुसार अस्थाई नियुक्ति उन्होंने
को दिये जाने का प्रावधान है जिन्होंने पूर्व में 240 दिन कार्य
कर लिया हो व ऐसे प्रत्यागी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति
में अन्य व्यक्तियों को निर्देशित किया जा सकता है। श्रमिक
का यह भी कथन है कि जिन शाखाओं में उसे नियुक्त
किया गया वहां से वापस में स्थाई पद खाली थे किन्तु
नियोजक ने अनुचित श्रम नीति के परिणामस्वरूप उसे अल्प-
वधि के लिए नियुक्तियां दी थीं। बैंक के परिपत्र क्र० 436

दि० 9-5-79 के प्रावधान के अनुसार श्रमिक ने यह अभि-
कथित किया है कि जिन व्यक्तियों ने अस्थाई रूप से 240 दिन
में अधिक कार्य कर लिया हो उन्हें एक व उसमें अधिक वेतन
वृद्धि देने का प्रावधान है व उपर्युक्त के प्रावधानों को पालना
श्रमिक के मामले में नहीं की गई। अनुतोष यह मांगा गया
है कि दिनांक 1-4-79 से श्रमिक की सेवाएं समाप्त करने
की कार्यवाही को अनुचित व अवैध माना जावे एवं उस अवधि
का वेतन उसे दिलाया जावे व 3-4-78 प्रथम नियुक्ति तिथि
मानते हुए उसे वेतन वृद्धियां व अन्य सुविधाएं लाभ स्वीकृत
किये जावें।

3. विपक्षी बैंक की ओर से अपने जवाब में यह विधित
प्रतिरक्षा ली गई है कि श्रमिक को सेवा मुक्त करने की कार्य-
वाही द्वारा 2(OO) (बीडी) के प्रावधान के अनुसार छुट्टी
की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए इस संबंध में कोई भी
अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी श्रमिक नहीं है। तथ्यों
के संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि श्रमिक ने 3-4-78
से 1-4-79 के बीच सीकर जिले में विभिन्न शाखाओं में
स्थाई कर्मचारियों के अवकाश के बदले हुए रिक्त जाग
पर कार्य किया था, यह नियुक्ति समय समय पर निषिद्ध
अवधि के लिए दी गई थी जो उस अवधि को समाप्ति के
पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाती थी। इस प्रकार की नियुक्ति
विपक्षीय समझौते की धारा 20.7 व 20.8 के तहत करना
जनाया गया है। नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप
के पश्चात् 8-10-79 को श्रमिक को नियुक्त करना स्वीकार
किया गया है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि
दिनांक 1-8-77 के परिपत्र के प्रावधान श्रमिक के मामले में
इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि उसकी नियमित नियुक्ति
बैंक में 5-5-79 के पश्चात् हुई थी। इन आधारों पर क्लेम
को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

4. मौखिक माध्यमों में श्रमिक यूनियन की ओर से स्वयं
श्रमिक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व निर्देश की
ओर से दो गवाहान सर्वश्री एम० आर० शर्मा व एम० एन०
मोहंदा के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए हैं। संबंधित समझौतों
व परिपत्र की फोटो प्रतियां दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत
की गई हैं। श्रमिक यूनियन की ओर से निर्देश बहम भी
प्रस्तुत की गई है। दोनों पक्षों की बहम सुनी गई व उल्लेख
माध्यम एवं संबंधित परिपत्रों व प्रस्तुत निर्णयों पर विचार
किया गया।

5. दोनों पक्षों के अभिकथनों में यह स्थिति साम्य है
कि श्रमिक ने विपक्षी बैंक को सीकर जिले की विभिन्न शाखाओं
में 3-4-78 से 31-3-79 तक 249 दिन कार्य किया था।
नियोजक ने अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है
कि इसके आगे विवाद यह है कि श्रमिक यूनियन का कथन
है कि उसको नियुक्ति स्थाई पद के विरुद्ध दी गई थी जबकि
नियोजक का कथन है कि विभिन्न शाखाओं में अवकाश के
कारण रिक्त पदों पर श्रमिक को अस्थाई नियुक्ति दी गई थी
व इस हेतु औद्योगिक प्रबन्धक कार्यालय द्वारा श्रमिक को वेतन

में शामिल किया हुआ था। अतः उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से यह विनिश्चय किया जाना है कि क्या श्रमिक ने स्थाई खाली पद के विरुद्ध काम किया अथवा अवकाश के कारण हुए खाली पद पर उसने अस्थायी रूप से कार्य किया था। श्रमिक ने अपने शपथ पत्र के मुख्य भाग में जिरह में यह स्वीकार किया है कि जिस-जिस शाखाओं में अवकाश के कारण जगह रिक्त होती थी वहां उसने कार्य किया था व कुछ कर्मचारियों के नाम भी उसने स्वीकार किये हैं जो उस अवधि में अवकाश पर थे। नियोजक के दोनों गवाह श्री एम० आर० शर्मा व ए० ए०० दोहिया ने शपथ पत्रों में यह अभिकथित किया है कि श्रमिक ने विभिन्न शाखाओं में यह अभिकथित किया है कि कर्मचारियों के अवकाश पर होने के कारण विभिन्न अवधि में कार्य किया था व उन शाखाओं के व उन अवधि के विवरण भी शपथ पत्रों में दिये गये हैं। इन तथ्यों पर कोई भी महत्वपूर्ण जिरह श्रमिक से नहीं की गई है। नियुक्ति आदेश कोई भी श्रमिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है व दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि श्रमिक को अस्थायी नियुक्तियां मौखिक आदेश से दी जाती थी व नियुक्ति की अवधि में उसका मुख्यालय सीकर रहता था। श्रमिक ने यह भी स्वीकार किया है कि जिन जिन शाखाओं में उसने कार्य किया वहां आने जाने का यात्रा भत्ता भी उसे नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में यह मानने का तथ्यात्मक आधार नहीं है कि श्रमिक ने लगातार 3-4-78 से 1-4-79 तक सीकर मुख्यालय पर रहकर ड्यूटी दी थी व उस बीच उसे विभिन्न शाखाओं में काम करने के लिए भेजा जाता था। इसके अलावा दोनों पक्षों के अभिकथन व उपलब्ध साक्ष्य व परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा श्रमिक को अवकाश के एवज में काम करने के लिये पैनाल में शामिल किया गया था व इस कार्य हेतु उसका आवंटन सीकर जिले में किया गया था व संबंधित अवधि में सीकर जिले में जहां अवकाश के कारण खाली जगह हुई वहां उसे काम करने के लिये भेजा गया था। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि श्रमिक ने लगातार 3-4-78 से 1-4-79 तक कार्य किया था व बीच में जो व्यवधान हुए वे काल्पनिक व आधारहीन थे। यह सही है कि प्रवर्ष डब्ल्यू-7 से डब्ल्यू-9 प्रमाण पत्रों में व अभिकथनों में नियोजक ने संबंधित अवधि में कुल 249 दिन काम करने का प्रमाण पत्र श्रमिक के पक्ष में जारी किया है किन्तु उससे यह धारणा नहीं ली जा सकती कि उसने लगातार बिना व्यवधान इस अवधि में कार्य किया था। धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान उसी स्थिति में प्रभाव में आते हैं जब किसी श्रमिक ने लगातार 240 दिन या उससे अधिक अवधि में नियोजक के यहां कार्य किया हो।

6. नियोजक की ओर से जवाब में धारा 2(00) (बीबी) अधिनियम के प्रावधान के संबंध में जो वैधानिक प्रतिरक्षा ली गई है वह इस प्रकरण में इसलिये विचारणीय नहीं है क्योंकि अधिनियम में यह संशोधन 1984 में किया गया था जबकि श्रमिक की सेवा मुक्ति का विवाद 1979 से संबंधित है। इस विधिक स्थिति को देखते हुए नियोजक की ओर से बहस में इस आपर्ति को किसी भी रूप में प्रेरित नहीं किया गया है।

7. श्रमिक यूनियन की ओर से यह बताने के लिये कि श्रमिक का मामला छंटनी की परिभाषा में आता है व उसने 240 दिन से अधिक कार्य लगातार किया था इसलिये धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना के बिना उसकी सेवा मुक्ति की कार्यवाही अनुचित व अवैध है, निम्न विधि दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं:

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम ए०० सुन्दरमणि ए०आई० आर० 1976 (एस० सी०) 478
2. हिन्दुस्तान स्टील लि० बनाम उड़ीसा राज्य एल० ए०० जे० 1977 (एस० सी०) पेज--1
3. दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स बनाम सम्भन्ध मुखर्जी एल० एल० जे० 1978 (एस० सी०) पेज--1
4. ऐवॉन सर्विसेज बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण फरीदाबाद एल० एल० जे० 1979 (एस० सी०) पेज 1
5. संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए०आई० आर० 1980 (एस० सी०) 72
6. मुरेल कुमार बनाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, ए० आई० आर० 1980 (एस० सी०) 386।
7. मोहन लाल बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ए०आई० आर० 1981 पेज--70
8. एल० राबर्ट डिस्जूजा बनाम दक्षिण रेलवे, ए०आई० आर० 1982 (एस० सी०) 330
9. हरीमोहन बनाम श्रम न्यायालय, ए०आई० आर० 1984 (एस० सी०) 32
10. कर्नाटक राज्य परिवहन निगम बनाम शेख अब्दुल कादर ए० आई० आर० 1984 (एस० सी०) 110
11. गैमन इंडिया लि० बनाम निरंजनदाम, ए०आई० आर० 1983 (एस० सी०) 235
12. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के श्रमिकगण बनाम प्रबंधक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ए०आई० आर० 1985 (एस० सी०) 539
13. एच० डी० सिंघ बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए० आई० आर० 1985 (एस० सी०) पेज--3

8. न्यायाधिकरण द्वारा उक्त सभी मिश्रणों का गंभीरता से अध्ययन किया गया व इनमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि जिस मामले में श्रमिक ने निरन्तर 240 दिन कार्य किया हो व उसको सेवा मुक्ति का मामला धारा 2(00) (बी बी) के किसी अपवाद की परिभाषा में नहीं आता हो वहां उसको सेवा मुक्त करने की कार्यवाही धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान की पालना किये बिना नहीं की जा सकती व इस पालना के अभाव में सेवा मुक्ति का आदेश प्रारंभ से ही अनुचित व अवैध माना जायेगा। इस प्रकरण में अभिकथनों व साक्ष्य के आधार पर जो विनिश्चय किया गया है उसे देखते हुए उक्त सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते

हैं। अतः यह विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक ने लगातार 240 दिन विपक्षी बैंक में कार्य नहीं किया था इसलिये सेवा मुक्ति से पूर्व धारा 25-एफ के प्रावधान की पायता किया जाना आज्ञापक नहीं था।

9. श्रमिक ने 14-10-79 को विपक्षी बैंक की त्रिमासिक शाखा में नियमित रूप से नियुक्ति पश्चात् इगुटी जोइन की थी इस तथ्य पर कोई भी विवाद नहीं है। पूर्व में वर्णित तथ्यों व विधिक स्थिति को देखते हुए यह अनुतोष क्लेम किया गया है कि श्रमिक को 1-4-79 से 13-10-79 को अवधि का बकाया वेतन दिलाया जावे व 3-4-79 प्रथम नियुक्ति तिथि मानते हुए वेतन वृद्धियां व अन्य लाभ स्वीकृत किये जावें। चूंकि श्रमिक की सेवा मुक्ति 1-4-79 से अवधि नहीं मानी गई है इसलिये बीच की अवधि का बकाया वेतन प्राप्त करने का वह किसी भी रूप में अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार प्रथम नियुक्ति तिथि 3-7-78 मानते हुए कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी श्रमिक नहीं है क्योंकि उसकी सेवाएं 1-4-79 से विधिवत समाप्त की गई थी इसलिए बीच की अवधि का जो व्यवधान नियमित नियुक्ति से पूर्व उत्पन्न हुआ है उसे देखते हुए श्रमिक को प्रथम नियुक्ति 3-4-78 नहीं मानी जा सकती।

10. श्रमिक यूनियन ने बैंक के परिपत्र 9-5-79 का अवलम्ब लेते हुए यह तर्क दिया है कि चूंकि श्रमिक ने नियमित नियुक्ति में पूर्व अस्थाई रूप से 240 दिन से अधिक कार्य बैंक में किया था इसलिये वह उक्त परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार बैंक के एक अन्य परिपत्र 1-8-77 क्रमांक 336 का अवलम्ब भी श्रमिक यूनियन द्वारा लिया गया है। इस परिपत्र के खण्ड-1 के अनुसार यह समझौता हुआ था कि जिन व्यक्तियों ने अस्थाई रूप से 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया है उन्हें शैक्षणिक योग्यता व चिकितीय रूप से योग्य होने पर बैंक में स्थाई नियुक्ति दी जायेगी व इसके लिये उन्हें 15-9-77 तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस परिपत्र के तहत श्रमिक कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसने मान्य रूप से अस्थाई रूप से बैंक में अप्रैल 1978 के पश्चात् कार्य किया था। क्लेम में श्रमिक ने यह भी वर्णित नहीं किया है कि इस परिपत्र के अनुसार वह स्थाई नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। परिपत्र क्रमांक 436 दिनांक 9-5-79 की शर्त सं० 1, 2, 3 व 11 (जो विपक्षी बैंक के लिखित जवाब में शब्दशः वर्णित किये गये हैं) के सम्मिलित पठन से यह स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति बैंक में इस परिपत्र के तहत सम्पादित समझौते से पूर्व दी गई थी पर जिन्होंने ऐसी नियुक्ति से पूर्व 240 दिन से अधिक अस्थाई रूप से कार्य कर लिया था उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। चूंकि श्रमिक को नियमित नियुक्ति बैंक में 8-10-97 को दी गई थी व उसने 14-10-79 को इगुटी जोइन की था इसलिये वह उक्त परिपत्र की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिपत्र की शर्त सं० 2

में यह भी प्रावधान है कि पूर्व तिथि से अतिरिक्त वेतन वृद्धियां संबंधित मामलों में 1-4-78 से स्वीकृति दी जायेगी व इसके लिये 31-10-79 तक संबंधित श्रमिक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों को नियुक्ति 1-4-78 से पूर्व नियमित रूप में दी गई थी उन्हीं को इस परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का लाभ देय था। श्रमिक यूनियन ने अपने क्लेम में यह अभिकथित किया है कि बैंक ने उक्त समझौते में जिस तिथि का वर्णन किया है वह भेदभावपूर्ण है इसलिये उन सभी कर्मचारियों को यह लाभ मिलना चाहिये जिनकी नियुक्ति परिपत्र के प्रभाव में आने के बाद में किसी भी तिथि को हुई है। वहस भी इस प्रकार की गई है। चूंकि समझौता द्विपक्षीय सम्पन्न हुआ है व उसमें अतिरिक्त लाभ के लिए एक निश्चित अवधि तक वर्णन किया गया है इसलिये यह न्यायाधिकरण इस परिपत्र के तहत यह अनुरोध उन कर्मचारियों को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है जिनकी नियुक्ति बाद की तिथि में हुई है। समझौता श्रमिक यूनियनों द्वारा सम्पादित किया गया है इसलिये निश्चित रूप से वे समझौते की शर्तों से वाध्य हैं व अन्य किसी विधिक स्थिति के अनुसार भी न्यायाधिकरण इस समझौते को अवैधानिक मानने के लिए सक्षम नहीं है। 9-5-79 का सम्पूर्ण समझौता भी पत्रावली पर नियोजक पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अन्य कोई भी तथ्यात्मक या विधिक वहस किसी भी पक्ष की ओर से नहीं की गई है। पूर्व में जिन तथ्यात्मक व विधिक स्थिति पर विचार किया गया है उन्हें देखते हुए श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

11. श्रमिक ने दिनांक 2-4-92 को एक शपथ पत्र न्यायाधिकरण में प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया था कि वह इस विवाद को नहीं चलाना चाहता इसलिये इसे समाप्त किया जावे। श्रमिक यूनियन ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में इस आधार पर आपत्ति की कि विवाद उनके द्वारा प्रायोजित किया हुआ है इसलिये श्रमिक उसे प्रत्याहर्त करने के लिये सक्षम नहीं है। न्यायाधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार किया था व उसी के परिणामस्वरूप आगे कार्यवाही चालू रखी गई। इस बिन्दु पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

12. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा श्रमिक माली राम शर्मा को दिनांक 1-4-79 से सेवा मुक्त करने की कार्यवाही उचित व वैध है व 1-4-79 से 13-10-79 की अवधि का बकाया वेतन व अन्य लाभ प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं है। श्रमिक 3-4-78 से प्रथम नियुक्ति तिथि मानते हुए भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

13. अधिनिर्णय आज दिनांक 28-11-95 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के० एन० व्याम, न्यायाधीश

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1996

का. आ. 2485:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.—12012/285/88—1 आरबी आई]

पी. जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th July, 1996

S.O. 2485.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.B.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 26-7-1996.

[No. L-12012/285/88-1RBI]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 116/89

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश
अमांक एल. 12012/285/88-डी--3 (ए)
दि. 13-4-89

मांगी लाल जैन निवासी खापता, मोती चौक,
जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जोधपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास, आर. एच. जे. एम.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह
अप्रार्थी की ओर से : श्री एम. के. जैन
दिनांक अवाद 27-3-1996
अवाद

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद:

“Whether the action of the management of the State

Bank of India in accepting the conditional resignation of Shri Mangilal Jain, Clerk at their Jodhpur Branch is just and legal? If not, to what relief is the worker concerned entitled to?”

2. श्रमिक यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम में अभिकथित इस्तीफे की स्थिति से पूर्व सेवा की स्थिति के संबंध में यह बताया गया है कि शुरू में श्रमिक ने विपक्षी बैंक में 7-9-72 से 17-11-73 तक अस्थायी रूप से कार्य किया था, 20-1-74 की परीक्षा में सफल होने के बाद 30-4-74 को उसे बैंक में स्थाई रूप से नियुक्त किया गया, 12-11-74 को उसे सेवा में स्थाई किया गया, इसके पश्चात् उसे प्रशिक्षण हेतु अम्बाला भेजा गया व प्रशिक्षण के बाद उसे कुछ समय विपक्षी बैंक की जोधपुर शाखा में कार्य किया व तत्पश्चात् उसे जोधपुर में उक्त शाखा के उप कार्यालय एयर फोर्स जोधपुर में स्थानान्तरित किया गया। श्रमिक के अनुसार उस उप-कार्यालय में कार्य की अधिकता थी कैशियर व क्लर्क का समस्त कार्य उससे लिया जाता था व इसके बावजूद बैंक द्वारा उसे असंतोषजनक कार्य के लिए 11-3-76, 9-7-76 को मीमो दिये गये जिनका उसने उचित जवाब प्रस्तुत किया था। श्रमिक का कथन है कि उप-शाखा व शाखा मैनेजर द्वेषता से उसे तंग करना चाहते थे व इस कारण वह मानसिक रूप से अतृप्त व अशांत हो गया था व इसी कारण उसने सेवा से इस्तीफा प्रस्तुत किया। इसके अलावा श्रमिक का यह भी कथन है कि उसने जोधपुर मुख्य शाखा में बिमारी के कारण स्थानांतरण करने के लिए लिखित आवेदन किया था व यह भी अनुरोध किया था कि उप कार्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए किसी अन्य कर्मचारी को भी नियुक्त करने का अनुरोध किया था। क्लेम के पद सं. 9 में यह उल्लिखित है कि श्रमिक ने अपना इस्तीफा सर्गर्त 24-10-76 को प्रस्तुत किया था जिसके जवाब में बैंक ने 1-12-76 को स्पष्टीकरण मांगा था जिसका उसने मौखिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था। इसके बावजूद 31-1-77 को उसका उक्त इस्तीफा स्वीकार किया गया जो अनुचित एवं अवैध है। इसके पश्चात् श्रमिक ने बैंक में कई पत्र लिखे व यूनियन के माध्यम से समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया जिसमें असफल वार्ता के कारण यह विवाद निर्दिष्ट किया गया। अनुरोध यह मांगा गया है कि नियोजक द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने की कार्यवाही को अवैध मानते हुए श्रमिक को पुनः सेवा में वहाल किया जावे।

3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रारंभिक आपत्ति यह थी गई है कि श्रमिक ने 1977 में इस्तीफा मंजूर होने के बाद करीब 12 वर्ष पश्चात् विवाद प्रायोजित करवाया है व देरी का कोई भी कारण नहीं है इसलिए इस आधार पर विवाद मुनवाई योग्य नहीं है वह यह धारणा लेने का आधार है कि श्रमिक ने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया था। श्रमिक द्वारा वर्णित नियुक्ति, प्रशिक्षण, विपक्षी बैंक को जोधपुर स्थित मुख्य

शाखा व उप कार्यालय में कार्य करने के तथ्यों को किसी भी रूप में विवादग्रस्त नहीं बताया गया है। इस तथ्य को प्रस्वीकार किया गया है कि उप शाखा में श्रमिक से अधिक काम लिया जाता था या उसे परेशान या प्रतर्कित किया जाता था। जो भी मीमो श्रमिक को दिये गये वे उसके असंतोषजनक कार्य के कारण सद्भावनापूर्वक प्रश्रिया से जारी किये गये थे। नियोजक का यह कथन है कि श्रमिक ने अपना इस्तीफा बिना शर्त स्वेच्छा से प्रस्तुत किया था व उसके बावजूद उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था व उसी के बाद उसका इस्तीफा नियमानुसार स्वीकृत किया गया। किसी भी रूप में इस्तीफा मानसिक संकुलन बिगड़ जाने से या अन्य किसी रूप से नियोजक द्वारा परेशान करने के कारण श्रमिक द्वारा प्रस्तुत करने के कारण श्रमिक द्वारा प्रस्तुत करने के तथ्य को प्रस्वीकार किया गया है। यह भी अभिकथित किया गया है कि इस्तीफा स्वीकृत करने के पश्चात् श्रमिक ने बैंक में बकाया पी. एफ. की राशि व अन्य भुगतान प्राप्त कर लिये थे जिससे भी यह प्रकट होता है कि उसने इस्तीफा स्वेच्छा से दिया था। इन तथ्यों के आधार पर क्लेम खारिज करने का अनुरोध किया गया है। श्रमिक ने नियोजक के जवाब का रीजोण्डर प्रस्तुत करते हुए देरी का कारण यह बताया है कि उसने पहले बैंक से पत्र व्यवहार किया था व बाद में यूनियन द्वारा क्लेम प्रायोजित करवाया था। इस्तीफा स्वेच्छा से देने के तथ्य को भी श्रमिक ने प्रस्वीकार किया है।

4. भौखिक साक्ष्य में यूनियन की ओर से श्रमिक का व विपक्षी की ओर से गवाह श्री नन्व लाल मंगला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से कुछ प्रलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं। बहस दोनों पक्षों की सुनी गई।

5. केन्द्र सरकार द्वारा विवाद जिस रूप में निर्देशित किया गया है उसके अनुसार यह निश्चय किया जाता है कि क्या श्रमिक द्वारा इस्तीफा सशर्त प्रस्तुत किया गया था व यदि ऐसा है तो क्या नियोजक द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने की कार्यवाही अनुचित व अवैध है। श्रमिक ने अपने क्लेम में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस्तीफा किन शर्तों पर उसने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जो तमाम पृष्ठभूमि क्लेम में बताई गई है वह यह है कि बैंक में कार्य अधिक होने से, अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से उसके खिलाफ भीमो जारी करने से व उसका स्थानान्तरण मुख्य शाखा में नहीं करने के कारण मानसिक अशांति व दबाव से उसने इस्तीफा दिया था। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में इस्तीफा देने के तथ्य को यदि सही माना जावे तब भी इस्तीफा सशर्त होना प्रमाणित नहीं होता। श्रमिक द्वारा जो इस्तीफा बैंक में प्रस्तुत किया गया था वह परिशिष्ट—12 दिनांक 14-10-76 का है उसमें यह उल्लेख है कि श्रमिक द्वारा नियोजक की ओर से जारी किये गये मीमो दिनांक 9-7-76 व 6-10-76 तक उनके संबंध में

श्रमिक द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब 11-10-76 के संदर्भ में श्रमिक द्वारा सेवा से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत किया गया। परिशिष्ट—10 श्रमिक का लिखित जवाब 11-10-76 का है। जिसमें उसने कार्य की अधिकता के कारण अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने व बीमारी के कारण स्वयं का स्थानान्तरण मुख्य शाखा में करने का अनुरोध किया था। शपथ पत्र में भी श्रमिक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस्तीफा उसने किस प्रकार सशर्त प्रस्तुत किया था व मात्र नियोजक द्वारा जारी किये गये मीमो व अपने स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि उसने सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। शपथ पत्र में इससे पूर्व यह उल्लेख है कि नियोजक के अधिकारियों द्वारा उसे तंग किया गया था व इस कारण उसने सशर्त इस्तीफा प्रस्तुत किया था। नियोजक की ओर से जो गवाह प्रस्तुत हुआ हैं उसने श्रमिक से अनावश्यक अधिक काम लेना, उसे जानबूझकर परेशान करना, अनिश्चित रूप से मीमो जारी करने के तथ्यों को प्रस्वीकार किया है तथा प्रदर्श एम—1 प्रलेख पेश किया है जिसमें श्रमिक ने, लिखित में यह माना था कि उसने अपना कार्य अच्छी प्रकार नहीं किया था। इसके अलावा प्रदर्श एम—2 में उसने यह अनुरोध किया था कि उससे क्लर्क का या कैशियर का काम लिया जावे। नियोजक के गवाह का कथन है कि श्रमिक की नियुक्ति क्लर्क-कम-कैशियर के पद पर थी इसलिए कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उससे कोई भी काम लिया जा सकता था। गवाह श्री नन्दलाल संबंधित शाखा में कार्यरत नहीं था व उसने बयान अभिलेख के आधार पर दिया है। इसके अलावा अन्य कोई भी मौखिक साक्ष्य इस संबंध में सुसंगत नहीं है। श्रमिक द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र परिशिष्ट—12 में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है। यदि तर्क के लिए यह माना जावे कि श्रमिक ने अपने जवाब परिशिष्ट—10 में स्थानान्तरण करना व एक अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने का जो अनुरोध किया था उसी के संदर्भ में उसने इस्तीफा दिया क्योंकि नियोजक द्वारा इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया था तब भी यह त्यागपत्र सशर्त नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी भी कर्मचारी का यह अधिकार नहीं है कि उसे किसी विशिष्ट स्थान पर नियुक्त किया जावे अथवा किसी शाखा में उसकी मांग के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारी लगाया जावे। दोनों ही कार्य करने का विवेकाधिकार नियोजक का है। इसलिए प्रदर्श —10 जवाब के संदर्भ में विचार करने पर भी त्यागपत्र को सशर्त नहीं माना जा सकता।

6. मानसिक रूप से पीड़ित या दबाव में होने के कारण श्रमिक ने इस्तीफा दिया हो यह निश्चय करने का क्षेत्राधिकार निर्देश की शर्त को देखते हुए न्यायाधिकरण को उपसब्ध नहीं है व इसके अलावा भी श्रमिक ने अपनी जिरह में यह कहा है कि उसने त्यागपत्र दबाव से या किसी के कहने से नहीं दिया था। कार्य की अधिकता व मुख्य शाखा में स्थानान्तरण के अनुरोध के जो तथ्य श्रमिक ने

बताये है मात्र उन्हीं को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि त्याग पत्र देने समय श्रमिक का मानसिक संतुलन सही नहीं था या नियोजक के अधिकारियों ने उस पर मानसिक दबाव डालकर त्याग पत्र प्राप्त किया।

7. नियोजक के जवाब व गवाह श्री नन्द लाल के बयान में यह बताया गया है कि परिशिष्ट-12 त्याग पत्र के पश्चात परिशिष्ट 13 पत्र दिनांक 1/12/76 को श्रमिक को भेजा गया था जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उसने इस्तीफा किस कारण से दिया। नियोजक का यह भी कथन है कि इस पत्र का लिखित जवाब श्रमिक ने 10/12/76 को दिया था जिसमें त्यागपत्र अविलम्ब स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। यह पत्र नियोजक द्वारा पत्रावली पर पेश किया हुआ नहीं है व न ही श्रमिक ने उसे प्रस्तुत करवाने का अनुरोध किया है व इसके प्लावा श्रमिक ने रीजोइन्डर में इस पत्र को भेजने के तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है। 1/12/76 के पत्र के संदर्भ में श्रमिक ने क्लेम में यह बताया है कि उसने अपनी स्थिति साक्षात् प्रबंधक को स्पष्ट कर दी थी किन्तु इसका कोई भी विस्तृत विवरण नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में यह धारणा लेने का आधार है कि श्रमिक ने 1/12/76 के पत्र के संदर्भ में भी यह स्पष्ट नहीं किया था कि उसने त्याग पत्र किस कारण से व किस प्रकार सशर्त प्रस्तुत किया था। इस परिस्थिति से यह माना जाता है कि श्रमिक ने त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया था।

8. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में इस प्रारंभिक आपत्ति को प्रेरित नहीं किया है कि श्रमिक द्वारा विवाद आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के कारण क्लेम सरसरी तौर पर खारिज किया जाए व औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू भी नहीं होते हैं। नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने बहस में विवाद देरी से प्रायोजित होने व कुछ अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि श्रमिक ने इस्तीफा स्वेच्छा से दिया था। श्रमिक को त्याग पत्र परिशिष्ट-14 के जरिये 31/1/77 को स्वीकार किया गया था। श्रमिक ने अपने क्लेम व अपने शपथ पत्र में इसके बाबत बैंक में लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करना बताया है किन्तु इसका कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र एक पत्र परिशिष्ट-15 दिनांक 11/4/88 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें त्याग पत्र स्वीकार करने के तथ्य को चुनौती दी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि करीब 11 वर्ष तक श्रमिक ने त्याग पत्र की स्वीकृति के तथ्य को किसी प्रकार चुनौती नहीं दी। दोनों पक्षों के अभिकथनों, मौखिक साक्ष्य व प्रदर्श एम-3 श्रमिक के पत्र बैंक के पत्र एम-4 से यह भी स्पष्ट है कि श्रमिक द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात अपनी समस्त बकाया राशि को भुगतान अविलम्ब प्राप्त कर लिया गया था व उस समय

भी श्रमिक ने त्याग पत्र के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी। उक्त दोनों तथ्यों से अन्य मौखिक व प्रालेखीय साक्ष्य तथा सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना युक्तिसंगत है कि श्रमिक ने अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया था। इसके अतिरिक्त श्रमिक ने जिरह में यह भी माना है कि बैंक में त्याग पत्र स्वीकृत होने के बाद उसने 1-6-84 से 9/3/89 तक चौपड़ा मेटल्स में काम किया था व 10/3/89 से वैलकम ग्रुप में कार्यरत है। यूनियन द्वारा समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद को 1988 में प्रायोजित किया था व इस बाबत भी यह साक्ष्य नहीं आई है कि यूनियन द्वारा श्रमिक की प्रार्थना के बावजूद विवाद देरी से प्रायोजित किया गया हो। तमाम विवेचित मौखिक, प्रालेखिक साक्ष्य व सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए यह विनिश्चय किया जाता है कि श्रमिक द्वारा त्याग पत्र बिना शर्त स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया था व इस कारण नियोजक द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है।

9. श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने विधिक स्थिति के संबंध में निम्न निर्णय प्रस्तुत किये हैं।

1. भारत संघ बनाम गोपाल चंद मिश्रा, एफ.एल. आर. 1978 (एम.सी.) पेज 16

2. सुभांगी भोंसले बनाम ए.डी. देशपाण्डे व अन्य 1974 एल.एल.एन. (बॉम्बे पेज 931)

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय में इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है कि किसी भी कर्मचारी द्वारा अपना त्याग पत्र किसी तिथि तक प्रत्याहरित किया जा सकता है इसलिए तथ्यों को देखते हुए इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस विवाद में सुसंगत नहीं हैं क्योंकि श्रमिक का यह कथन नहीं है कि उसने किसी प्रश्न पर अपना त्याग पत्र वापस लेने का अनुरोध किया हो। दूसरे संदर्भित निर्णय में तथ्यों के आधार पर श्रम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया था कि श्रमिक द्वारा त्याग पत्र मानसिक रूप से असंतुलित होने के कारण प्रस्तुत किया गया था इसलिए उसे स्वीकृत नहीं माना जा सकता। जिन तथ्यों पर इस मामले में विचार किया गया है उनको देखते हुए इस निर्णय के सिद्धान्तों से श्रमिक को कोई भी लाभ नहीं मिल सकता।

2. नियोजक के विद्वान प्रतिनिधि ने 1972 लैब.आई.सी. (एम.सी.) 676 का एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्वेशित विवाद की शर्तों की सीमा में रहते हुए ही न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम पारित किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में यह विनिश्चय किया गया है कि न्यायधिकरण को मात्र यह देखना है कि क्या श्रमिक ने त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया था या सशर्त। 1986 लैब. आई. सी. 896 (इनाहावाद) का एक अन्य निर्णय नियोजक की ओर

से प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतिपादित किया गया है कि अभिकर्तों व साधु के आभाव में यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि किसी श्रमिक द्वारा त्याग पत्र मानसिक दबाव या अनुचित प्रभाव के कारण दिया गया क्योंकि यह विनिश्चय तथ्यों पर आधारित है। अन्य कोई भी तर्क वितर्क किसी भी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि नियोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्रमिक मांगी लाल जैन द्वारा प्रेषित त्याग पत्र दिनांक 24.10.76 को स्वीकृत करने की कार्यवाही उचित व वैध है इस कारण श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

13. अवार्ड आज दिनांक 27-3-96 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का.आ. 2486.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स ई.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद नं. 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/242/90-आई आर (सी-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2486.—In pursuance of Section 17 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. E.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 24-7-96.

[L-20012/242/90-IR(CI)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT
DHANBAD

PRESENT :

Shri D. K. Nayak, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 21 of 1991

PARTIES :

Employees in relation to the management of Gopinathpur Colliery of M/s. E.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—None.

On behalf of the employers.—None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 16th July, 1996

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(242)/90-I.R. (Coal-I), dated, the 17th January, 1991.

SCHEDULE

“Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for reinstatement with full back wages of Shri Sonalal Manjhi, Shri Monath Manjhi Ex-underground loader, Gopinathpur Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited is justified? If so to what relief the workman is entitled to?”

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But neither of the parties appeared nor took any steps. Thereafter several adjournments were granted to them. Then again notices were issued to both of them. But in spite of the issuance of notices to them they neither appeared nor took any steps. It therefore leads me to an inference that there is no dispute presently existing between the parties and in the circumstances, I am constrained to pass a ‘No dispute’ Award in this reference.

D. K. NAYAK, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का.आ. 2487.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद नं. 1 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-24012/11/89-डी-4(बी) डी 4 (ए)]

आई आर (सी-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2487.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 1, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. C.C. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 24-7-96.

[L-24012|11|89-D-4(B)DU(A)IR(CI)]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 134 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of Saru Bera Colliery of M/s. Central Coal-fields Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer
APPEARANCES :

For the Employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workmen.—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 18th July, 1996

AWARD

By Order No. L-24012|11|99-D-4(B)|D-4(A) dated 5-10-1988, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the action of the Management of Sarubera Colliery of M/s. CC L. P.O. Sarubera, Dist. Hazaribagh of Kuju Area in superannuating Sri Tilak Rana (F.B.N. 234), Carpenter w.e.f. 7-11-86 is legal? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. The order of the reference was received in this Tribunal on 14-10-1988. Thereafter notices

were issued to the parties for filing written statements. The parties filed their respective written statements and rejoinders. Thereafter the case was fixed for hearing.

3. In the meantime the concerned workman, Tilak Rana, filed a petition stating therein that he is no longer interested in pursuing the case.

4. It appears that he has no claim against the management. Accordingly, a ‘no dispute’ award is rendered in the present case.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996

का.आ. 2488.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुंबई नं. 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-11012/25/91 आई आर (मि.)
आई आर (सी-1)]

ब्रज मोहन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1996

S.O. 2488.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai No. 2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 24-7-96.

[No. I-11012/25/91-IR(Misc.)IR-C-I]
BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/31 of 1992

Employers in relation to the management of Indian Airlines, Bombay.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. A. R. Kulkarni and Mrs. P. A. Kulkarni, Advocates.

For the Workmen : Mrs. Neelima Kanetkar, Advocate.
Mumbai, dated 9th July, 1996

AWARD—PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. I-11012/25/91-IR(Misc.) dated 12-5-92, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

“Whether the action of the management of Indian Airlines, Bombay in terminating the services of Shri S. R. Palkar, ex-porter with effect from 4-6-1986 is just, proper and legal? If not, to what relief is the workman entitled to?”

2. S. R. Palkar the loader was on duty in the second shift on 14-6-85. He was attending to flight IC-107/Bombay/Bangalore. Mrs. Deviaha with three children holding Lufthansa tickets reported at the check-in-counter. She has eight pieces of baggage weighing 190 kgs. On her request to reduce some weight as she has three small children Mr. C. Creado Traffic Assistant on duty reduced the baggage weight by 80 kgs. and after deducting her free baggage allowance of 80 kgs. asked her to pay the excess baggage charges for 100 kgs. which comes to 530 and odd. She was accompanied by one Jhaveri. She did not pay the excess baggage charges but she was allowed to travel by the same plane and same flight due to the incident which took place. Palkar when searched out was found in possession of Rs. 500. The search was taken by M. R. Dalvi, the security assistant in presence of one A. Prasad. These facts can be said to be admitted facts. The worker contended that he was charged by the Corporation on the ground that the demanded Rs. 400 from the lady passenger Deviaha in a consideration that she will be allowed to go without making payment for extra baggages on 14-6-85. He denied the charges. He submitted that the Domestic Inquiry which was held against him was against the principles of Natural Justice. He was not supplied with the documents nor allowed to defend his case properly. He pleaded that the statement of Mrs. Deviaha on which the Inquiry officer relied was not properly proved. It is asserted that the findings of the inquiry officer are perverse. It is averred that he was discriminated while awarding the punishment. For all these reasons it is prayed that the dismissal order which was passed against him may be set aside and he may be ordered to be reinstated in service with all back wages and other reliefs.

3. The management resisted the claim by the Written Statement Exhibit-3'. It is denied that the domestic inquiry which was held against the principles of Natural Justice. It is averred that all the rules of domestic inquiry were followed. It is emphatically denied that the findings of the inquiry officer are perverse. It is asserted that while awarding the punishment there was no discrimination. It is submitted that for all these reasons the reference may be answered in the favour of the Corporation.

4. My Learned Predecessor framed issues at Exhibit-5'. Issue Nos. 1 and 2 are treated as preliminary issues:

Issues	Findings
1. Whether the inquiry held against the workman was not held properly, legally and validly, and the rules of natural justice were not followed?	The inquiry was legal, proper and rules of natural justice were followed.
2. Whether the findings of the Inquiry Officer are perverse?	No.

REASONS

5. In the statement of claim it is alleged on behalf of the workman that he was not given fair opportunity to defend his case, charge sheet is illegal, standing orders are stayed by the High Court of Delhi, Statement of Mrs. Deviaha was relied even though she was not examined and that he was not supplied with the necessary documents on which the inquiry officer relied. It is therefore, submitted that the domestic inquiry which was held against him is against the Principles of Natural Justice. To substantiate this contention Shrikant Palkar (Exhibit-7) affirmed to that effect. On the other hand L. S. Verma (Exhibit-14), the inquiry officer deposed on behalf of the management and they relied on the documents which are filed alongwith Exhibit-6, to support their case that the Principles of Natural Justice were followed when the domestic inquiry was held against the workman.

6. Exhibit-6/1' is a photo copy of the Charge Sheet dated 8-7-85. After perusal of the Chargesheet it reveals that it is very clear in terms and there is no ambiguity. Clauses of the standing orders are mentioned there in on which the management wants to rely. It could be further seen that the copies of the statements on which the management wanted to rely were supplied to the worker. This clearly suggests that the management wants to examine those persons as their witnesses

No doubt there is no separate list of witnesses given in this chargesheet which were to be examined in the inquiry. But that has not caused prejudice to the workman.

7. Verma the inquiry officer in categorical term asked the worker whether he understood the charges for which he replied in the affirmative. Those charges were explained to him. He understood the same and pleaded not guilty to it (Exhibit-6/7, inquiry proceedings).

8. Palkar in his cross-examination in categorical term stated that he received the document mentioned in the charge sheet after a month after receipt of the charge sheet. But definitely he received the same before the inquiry was started. It has not caused prejudice to him. It can be further seen that his friend that is his representative had at not time raised any objection before the inquiry officer that he is not supplied with the copies of the documents. He admits to have received the copies of the statements in the domestic inquiry. The statement of witnesses were recorded in his presence. He also admitted that his representative verified the genuineness of the documents with the original on the request of the inquiry officer. This fact itself goes to show that the inquiry officer was vigilant to see that no prejudice is caused to the worker. All these facts clearly goes to show that a fair opportunity to defend the workman was given. So far as the staying of the standing orders by the Delhi High Court is concerned from the written argument which is filed on behalf of the worker it reveals that, that contention is given up.

9. The inquiry officer relied upon the letter given by Deviaha (Exhibit-7/5, M/E7). She was not examined before the inquiry officer. On its basis it is tried to submit that a prejudice is caused to him. So far as the fairness of the inquiry is concerned I do not find any merit in it. It is not at all necessary for the management to examine her because that letter-cum-statement dated 14-6-85 was given by her in presence of Dalvi and A. Prasad. They were examined by the management before the inquiry officer who proved the same. I therefore find that there is no illegality in relying upon the same.

10. It is tried to submit that the copy of the inquiry report was not supplied to the worker. The Learned advocate for the management submitted that this submission is incorrect. That copy was served upon the workman alongwith the second show cause notice dated 14/29-4-96. In the last para of that notice it is categorically mentioned that copies of the inquiry officers report and findings of the proceedings of the inquiry are enclosed with it. That letter was relied by the worker on 12-5-86 (Exhibit-6/16). In that letter it is nowhere mentioned that he did not receive the inquiry report and the findings. Therefore it has to be said that he did receive the inquiry report. For all these reasons it has to be stated that Principles of Natural Justice were followed in holding the domestic inquiry.

11. It is tried to argue on behalf of the workman that the findings of the inquiry officer are perverse. In fact, after introduction of Section 11A in the Industrial Disputes Act of 1947 the Tribunal has to satisfy itself whether the charges levelled against the workman are proved to its satisfaction by acceptable evidence. That is what is observed by his Lordship in 1991 II CLR 73.

12. It is tried to argue on behalf of the worker that the inquiry officer relied upon the statement of Mrs. Deviaha while coming to the conclusion that the charges are proved. It is further argued that no opportunity was given for the worker to cross-examine the said witness as she was never produced in the inquiry proceedings. I have already observed above that her statement was recorded in presence of Dalvi & Prasad. They proved that letter before the inquiry officer. What is mentioned in that letter is that she paid Rs. 400 to the workman in respect of excess baggage charge as the bribe. This is a circumstance alongwith other circumstances on the record, for coming to the conclusion that the workman is guilty. The Learned Advocate for the workman tried to argue that without examining Deviaha her statement is relied. Then in that case the letter which was sent by her to the worker which is produced alongwith Exhibit-16 has to be relied upon. From the signature on the letter Exhibit-16/3 it has to be said that it is not of Deviaha. The

letter Exhibit-1/17 which is proved is in her own handwriting. It bears her signature. By comparison of these two letters it can be said that the letter which is produced by the workman of not of the concerned passenger namely Deviaha. It can be further seen that what was the need for her to send such a letter to the worker. It can be further seen that the letter is said to be addressed to M/s. Indian Airlines, Bombay, which is produced by the worker alleged to be received in an envelope carrying his address. What was the reason for her to send that letter. No explanation has come forward regarding it. That letter cannot be relied upon.

13. Dalvi was examined before the inquiry officer at length and he was cross-examined by the workers representative. He was the security assistant at the relevant time. He affirmed that when he was only at that counter he saw suspicious movements of a loader Palkar. He therefore went inside the counter to see that he was doing. He stood behind it. He saw that he is accepting something from the person he was standing outside the counter. Prasad was standing behind Dalvi. He called him and then in his presence he took the personal search of loader and found Rs. 400 with him. Then the amount was confiscated. Prasad corroborates him. From the cross-examination of these two witnesses before the inquiry officer nothing has come on the record to doubt their testimony.

14. In the domestic inquiry a confessional statement (Exhibit-6, pg. 18, M/E8) was produced. That is the statement in the handwriting of Palkar by which he admitted the guilt to the effect that he accepted Rs. 400 from the person who was along with lady. After accepting the amount he asked the concerned person to issue the boarding ticket to the passenger but Craedo did not issue the same. He has also mentioned in the statement that he had given it without any undue influence. It is of the same date and signed by Prasad. It is his argument that he had to write that statement as undue influence was used upon him and he was threatened that if such a statement was not given he would be handed over to the police. This is common ground. In fact if such a statement would have been taken by using undue influence or a threat he would have raised voice against it immediately. The union is one of the forums. He would have written letter to the superiors regarding it. But he had not done so. Not only that, there is nothing on the record to show that when that statement was produced before the inquiry officer he raised objection regarding it. I therefore find that it is a voluntary statement. It is tried to bring on the record that the said statement was dictated by another officer, that is true. But it does not mean that the workman had not voluntarily given the same. The dictation appears to be have given with a view that the facts should be narrated as they happened. There is another circumstance which leads to think that, that statement was a voluntary as the letter was written by the worker on 12th May, 1986 (Exhibit-6, pg. 61). He wrote this letter to the commercial manager who send him letter why the punishment of removal from service of the Corporation should not be awarded as the charges are proved against him. In this letter also he has stated that he should improve himself and would not do any such things in future.

15. The workman examined Mahadeo Rajaram Dalvi (Exhibit-12) as his witness in the matter. While deciding whether the findings of the inquiry officer are not proper the Tribunal has to see the evidence before the inquiry officer and nothing more. The evidence lead before me for deciding that issue has no relevancy at all. Even for the sake of argument it is stated that evidence has to be considered. I do not find any material contradictions to Dalvi's statement before the Tribunal and that of before the inquiry officer. It can be further seen that his statement was recorded about 10 years back before the inquiry officer and in that case there are likelihood of some contradictions but that does not mean that what was deposed by him before the inquiry officer is wrong.

16. J. M. Karekar (Exhibit-13) was the defence representative. His testimony is by no way helpful for the workman for coming to the conclusion that the domestic inquiry which was held against the workman is against the principles of Natural Justice and that the findings of the Inquiry officer are perverse.

1959 GI/96—10.

17. A. N. Mhatre (Exhibit-6/23) was the defence witness in the inquiry proceeding. He is a loader. He says that he was working on another counter when he saw there is a rush where the workman was working. He went thereto help. But he affirmed that when Palkar asked him to help him he refused to do the work. It appears that he was examined by the worker with an intention that his presence has to be shown near him to contradict the statements made by Dalvi and Prasad, but Mahatre's testimony did not support him.

18. C. Craedo (Exhibit-26) the senior traffic assistant, was the defence witness in the inquiry proceeding. He affirmed that he saw a gentleman with the lady passenger talking at the counter. He denied that he asked Balkar to do something in the matter. In fact his testimony supports the case of the management and not that of the worker. Zaveri was the person who accompanied the passenger. It has come from the testimony of Dalvi that he left the place. It is tried to argue on behalf of the worker that he was not examined. It is rightly submitted that it is choice of the management to examine the witness to support the case. If really worker thought it fit he would have examined that man. I do not find any fault with the management on this count. It is also tried to submit that in such case the management should have handed over the workman to the police or to start departmental inquiry. The management decided to choose the later part.

19. From the testimony of the defence witness it reveals that the excess baggage charges were Rs. 530 and the workman had admittedly accepted Rs. 400 from the passenger. It is tried to submit that this was with a view to help the passenger. It cannot be accepted because if there was any anxiety of helping the passenger he would have taken Rs. 530 for making its payment. The fact that he had accepted Rs. 400 for the excess baggage charges clearly suggest that he accepted for other consideration. He wanted to pocket that amount and allow the passenger with that baggage by making less payment.

20. The Inquiry Officer report is at Exhibit-6/8. It is well reasoned. His conclusions are based on the evidences before him. I had also gone through the evidence and the documents on the record and I had found that the charges which were levelled against the workman are duly proved. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following Order:

ORDER

The Inquiry which was held against the workman was proper, legal and valid and the rules of natural justice were followed.

The findings of the inquiry officers are correct.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का.आ. 2489.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में, केन्द्रीय सरकार मैसूर बाबा मारबल सप्लायर्स के प्रबंधन के संबंध निगोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/37/88-डी-3 (बी)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2489.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute

between the employers in relation to the management of M/s. Baba Marbles Suppliers and their workman, which was received by the Central Government on the 30-7-96.

[No. L-29012/37/88-D.III(B)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी. आई.टी. 12/89

रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश
संख्या एल-29012/37/88-डी-3(बी) दिनांक
3-1-89

श्री किशनदास पुत्र श्री शिवदास जी
श्वरन, गांधी जूआदारा पो. मन्वार
तहसील देववार, जि. सिराही (रज.)

—प्राथी

बनाम
मैसर्स बाबा मारबल सप्लायर्स
84/227ए अफीम की कोटी, कानपुर।

—अप्राथी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के. एल. व्यास आर. एच. जे. एम.
प्राथी की ओर से : श्री जे. एल. शाह
अप्राथी की ओर से : श्रीकेवल राम जी व श्रीमती सुमननिगम
अवार्ड दिनांक : 15-1-96

अवार्ड

श्रमिक युनियन की ओर से श्री जे. एल. शाह व
नियोजक की ओर से श्री केवल राम जी व श्रीमती सुमन
निगम उपस्थित। नियोजक की ओर से पूर्व में एकपक्षीय
कार्यवाही को व एकपक्षीय अधिनिर्णय को अवास्त करवाने
का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे स्वीकार करने
में श्रमिक के प्रतिनिधि को आपत्ति नहीं है। अतः पूर्व
में नियोजक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने का व
परिणामस्वरूप एक पक्षीय अधिनिर्णय जो पारित किया
गया था उसे अवास्त किया जाता है। आज दोनों पक्षों ने स्वयं
द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र व उसके साथ एक समझौता
प्रस्तुत किया जिसे अभिप्रमाणित किया गया व पतावली पर रखा
गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौते के अनुसार समझौते
की शर्तों के अनुरूप अधिनिर्णय पारित करने का आदेश
दिया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा
जावे।

के.एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का.आ. 2490.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय
सरकार भारत गोल्ड माईन्स लि. के प्रबंधकों के संबंध

नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निविष्ट
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को
प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/30/95-आईआर (एम)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996.

S.O. 2490.—In pursuance of Section II of the Industrial
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal,
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute
between the employers in relation to the management of
Bharat Gold Mines Ltd. and their workman, which was received
by the Central Government on the 31-7-96.

[No. L-43012/30/95-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT
HYDERABAD

Present :

Sri A. Hanumanthu, M.A., LL.B., Industrial Tribunal-I.
Dated : 10th day of June, 1996
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 31 OF 1996
BETWEEN

Sri Abrham,
Ex-Gen. Labour No. 10,
South Bilberts Block,
Marrikuppam, (PO) K.G.F.-563 119. ..PETITIONER

AND

The Mines Manager,
Chingunta Project, BGML,
Chhingarunta, Chittoor Dist-517 001 ..RESPONDENT

Appearances :

Non-appeared for both the parties.

AWARD

This is a reference made by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its Order No. L-43012/30/95-IR(Misc.) dated 27-3-1996. Under Section 10(1)(d) and 2A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial Dispute mentioned in its schedule which reads as follows :

"Whether the action of the management of Chingargunta Project BGML, Chingargunta, Chittoor Distt. in dismissing the services of Sri Abraham, Ex-Genl. Labour BGML, Chingargunta is legal and justified ?

If not what relief workmen is entitled to ?"

The said reference has been taken on file as I.D. No. 31/96.

2. After registering the I.D., notice was issued to both the parties and the same was acknowledged by them. On 10-6-96 when the matter is called both parties are absent and no representation is made on their behalf though notices were served. Hence they are set-exparte. There are no triable issues as both parties remained exparte. There is no option except to close the reference as both the parties are evincing no interest to prosecute the matter. Hence the reference is closed.

Typed to my dictation given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of June, 1996.

A. HANUMANTHU, Industrial Tribunal-I

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का.आ. 2491:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दरोबा कोपर प्रोजेक्ट के प्रबन्धता के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल.-430-12/26/89-आई आर (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2491.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dariba Copper Project and their workman, which was received by the Central Government on 30-7-1996.

[No. L-43012/26/89-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सो.आई.टी. 32/90

रिफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश

अ. एल.-43012/26/89/आई.आर. (विविध) दि.

3-5-90

जनरल रीट्रेटी कोपर प्रोजेक्ट मजदूर यूनियन, दरोबा जिला अलवर।

—अप्रार्थी

बनाम

परियोजना प्रबन्धक, दरोबा कोपर प्रोजेक्ट, दरोबा जिला अलवर, राजस्थान।

—प्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री के.एल. व्यास, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम.एफ. बेग

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा

दिनांक अवार्ड : 29-3-1996

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न विवाद अधिनियम हेतु निर्देशित किया गया है :

“Whether the action of the management of Dariba Copper Project, Dariba (Alwar) of M/s. HCP Ltd. in accepting the retirement of Shri Ram Singh from 5-8-88 A/N under the VRS is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?”

2. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह स्वीकार किया है कि उसने 30-4-88 की स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के लिए बीमारी के आधार पर लिखित प्रार्थना पत्र नियोजक को प्रस्तुत किया था। दिनांक 5-8-88 से श्रमिक को उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही इस आधार पर घुनीती दी गई है कि श्रमिक ने 4-8-88 को स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया था, स्वीच्छक सेवा निवृत्ति की योजना 15-4-87 के पश्चात् प्रभावी नहीं थी, श्रमिक द्वारा प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया था, सेवा निवृत्ति के आदेश से पूर्व श्रमिक का मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया गया व उस योजना के तहत समुचित लाभ श्रमिक को स्वीकृत नहीं किया गया। श्रमिक का यह भी कथन है कि स्वीच्छक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति का पत्र कभी भी उसे प्राप्त नहीं हुआ व 8-8-88 को नियोजक द्वारा भेजा गया एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ था। इन आधारों पर नियोजक को श्रमिक द्वारा 5-8-88 से स्वीच्छक रूप से सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही की अवधि बताते हुए श्रमिक को पुनः सेवा में बहाल करने का अनुरोध मांगा गया है।

3. नियोजक ने क्लेम के जवाब में यह बताया है कि स्वीच्छक सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र श्रमिक का उसके हित में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया गया था तथा 4-8-88 को स्वीच्छक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति का पत्र श्रमिक को दिया गया जो उसने लेने से मना किया व बाद में यह पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया जो उसने प्राप्त नहीं किया। 8-8-88 के पत्र के जरिये श्रमिक को सेवा निवृत्ति के लाभ के हक में बैंक से राशि भेजी गई जो उसने बैंक से 16-8-88 को प्राप्त की। नियोजक का कथन है कि श्रमिक ने अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने के प्रयास स्वरूप यह क्लेम आधारहीन रूप से प्रस्तुत किया है।

4. मौखिक साक्ष्य में यूनियन की ओर से श्रमिक स्वयं का व नियोजक की ओर से एक गवाह श्री आर.के. आठूजा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियोजक की ओर से प्रदर्श एम-1 से प्रदर्श एम-5 व श्रमिक की ओर से प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-5 प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं। बहस दोनों पक्षों की सुनी गई।

5. सर्वप्रथम श्रमिक की ओर से स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव के संबंध में ली गई तकनीकी आपत्तियों पर विचार किया जाता है। क्लेम व शपथ पत्र में श्रमिक का यह कथन है कि उक्त योजना 15-4-87 के पश्चात् लागू नहीं थी। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी संबंधित विज्ञापन निदेश को बहस के समय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्थिति प्रमाणित होती है कि इसके अलावा योजना के संबंध में जो निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा लिखित में जारी किये गये थे उनमें यह प्रावधान भी है कि प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त निर्देशों में यह प्रावधान नहीं है कि बीमारी के आधार पर स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के लिए कर्मचारी का

मेडीकल परीक्षण करवाया जाना आवश्यक हो। नियोजक के गवाह श्री ग्राहजा ने अपनी जिरह में यह बताया है कि 15-4-89 के पश्चात् भी विशिष्ट मामलों में यह योजना लागू थी व मुख्यालय से स्वीकृति के बाद श्रमिक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। निर्धारित प्रपत्र के संबंध में उन्होंने कोई भी तथ्य अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि योजना के निर्देशानुसार स्वीच्छक सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र एक माह में स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रावधान था किन्तु जो मामले प्रपत्र की परिधि में नहीं आते थे उन्हें मुख्यालय योजना आवश्यक था व इसी कारण श्रमिक को सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र देरों से स्वीकार किया गया। श्रमिक ने विद्वान प्रतिनिधि ने जहस में इस बात को प्रेरित नहीं किया है कि एक माह की अवधि के पश्चात् नियोजक द्वारा श्रमिक ने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करना प्रावधानिक था। इस प्रकार का कोई विधि दृष्टान्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक माह में श्रमिक की प्रार्थना पर विचार नहीं करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र निरर्थक हो जाता है या स्वतः स्वीकृत माना जाता है। यह मान्य स्थिति है कि श्रमिक ने प्रदर्श एम-2 पत्र के जरिये बैंक से भेजी गई राशि का भुगतान 16-8-88 को प्राप्त कर लिया है क्योंकि नियोजक द्वारा लिये गये इस अभिकथन के खण्डन में श्रमिक ने न तो कोई रोजोर्डण्डर दिया है व न ही कोई विवरित साक्ष्य दी है। नियोजक के गवाह श्री ग्राहजा ने अपने शपथ पत्र में इस तथ्य को प्रमाणित किया है व उस पर कोई भी जिरह नहीं है। श्रमिक का श्यागपत्र 4-8-88 से स्वीकृत किया गया था व उसके काफी समय बाद समझौता अजिहारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया गया था इन परिस्थितियों में श्रमिक की ओर से जो तकनीकी आपत्तियाँ ली गई हैं वे मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनके आधार पर नियोजक द्वारा स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जा सकता था। किन्तु श्रमिक द्वारा योजना के तहत विशिष्ट लाभ प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें उक्त आपत्तियों के आधार पर पुनः सेवा में बहाल करने के अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जो भी तकनीकी आपत्तिकाएँ योजना में वर्णित हैं उन पर नियोजक को विचार करना अपेक्षित है व यदि नियोजक द्वारा श्रमिक के हित में उनको अपेक्षित करने हुए सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसी श्रमिक को कोई क्षति होता नहीं माना जा सकता।

6. श्रमिक की ओर से सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह क्लेम में लिया गया है कि उसके द्वारा स्वीच्छक सेवा निवृत्ति के आवेदन को उसकी स्वीकृति से पूर्व वापस ले लिया गया था इसलिए नियोजक उस पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं थे। दोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट है कि श्रमिक ने स्वीच्छक सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को वापस लेने का लिखित अनुरोध 4-8-88 को किया था इसकी प्रतिलिपि प्रदर्श डब्ल्यू-2 है। नियोजक के गवाह श्री ग्राहजा ने जिरह में माना है कि यह पत्र श्रमिक ने श्री गोयल को

4-8-88 को दिया था। इसके आगे किसी की साक्ष्य में या किसी प्रलेख में यह नहीं आया है कि प्रदर्श डब्ल्यू-2 पत्र श्रमिक द्वारा 4-8-88 को किस समय श्री गोयल को दिया गया। स्वीच्छक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति का पत्र प्रदर्श एम-5 है जो भी 4-8-88 का है। श्रमिक को यह पत्र कब प्राप्त हुआ इस बिन्दु पर पहले विचार किया जाता है। श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में यह बताया है कि प्रदर्श एम-5 पत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ व मात्र प्रदर्श डब्ल्यू-5 पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख है कि श्रमिक की सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र 4-8-88 की स्वीकृत किया जाकर उस रोज ही उसे सेवा मुक्त किया गया। 31-12-92 को नियोजक की ओर से लिखित प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रलेख प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह नियोजक के विभाग की टिप्पणी है कि 4-8-88 को श्रमिक ने सेवा निवृत्ति का पत्र व्यक्तिगत लेने से मना किया। 31-3-92 को आदेशिका में यह उल्लेख है कि इस प्रलेख व प्रार्थना पत्र को प्रतिलिपि यूनियन प्रतिनिधि श्री वेग को दी गई। इसके बाद श्रमिक ने इस संबंध में तरदीदी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया था किन्तु उनकी ओर से यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में 31-3-92 को जो प्रलेख नियोजक की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है क्योंकि श्रमिक को इसकी जानकारी दी गई थी व उन्होंने इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह भी किया था। नियोजक के गवाह श्री ग्राहजा की साक्ष्य 25-7-94 को शपथ पत्र के जरिये हुई थी व इस पर श्रमिक द्वारा 1-2-96 को जिरह की गई किन्तु उसमें भी उक्त प्रलेख पर कोई भी जिरह नहीं की गई है। मात्र 31-3-92 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रलेख पर प्रदर्श नहीं लगाने से यह नहीं माना जा सकता कि वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। वैसे भी भाक्ष्य अधिनियम के प्रावधान सम्पूर्ण रूप से व तकनीकी रूप से इस प्रकार के विवाद में लागू नहीं होते हैं। 31-3-92 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रलेख से यह स्थिति स्पष्ट है कि 4-8-88 को ड्यूटी समय में श्रमिक को प्रदर्श एम-5 पत्र लेने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु उसे लेने से मना किया गया। इसके बाद प्रदर्श एम-4 रजिस्ट्री के जरिये 5-8-88 को श्रमिक को भेजा गया था जो उसने लेने से मना किया। इस संबंध में श्रमिक से कोई भी जिरह नहीं की गई है किन्तु नियोजक द्वारा प्रदर्श एम-5 एक अन्य रसीद प्रस्तुत की गई है जिस पर श्रमिक के हस्ताक्षर बताये गये हैं किन्तु जिरह में श्रमिक ने अपने हस्ताक्षर होने से मना किया है। दोनों पक्षों को मौखिक साक्ष्य व पोस्ट आफिस द्वारा किये गये पृष्ठांकन को देखते हुए यह संभावित माना जाता है कि इस पर श्रमिक के हस्ताक्षर हैं। इसके बावजूद यह निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं होता है कि प्रदर्श एम-5 पत्र वास्तव में श्रमिक को किस रोज प्राप्त हुआ। नियोजक के गवाह श्री ग्राहजा ने प्रदर्श एम-5 को साबित करते हुए यह बताया है कि 4-8-88 के आदेश से श्रमिक की सेवा मुक्त किया गया था। आदेश में यह उल्लेख है कि श्रमिक का प्रार्थना पत्र स्वीच्छक सेवा निवृत्ति का सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस तथ्य से यह धारणा लिया जाना भी उचित है कि

4-8-88 से पूर्व श्रमिक का सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। यदि यह माना जावे कि उसी रोज यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा श्रमिक यह बताने में असमर्थ रहा कि उसने 4-8-88 पत्र प्रदर्श एम-5 के जारी होने से पूर्व प्रदर्श डब्ल्यू-2 पत्र नियोजक को प्रस्तुत कर दिया था। दोनों पक्षों को मौखिक साक्ष्य व प्रालेखिक साक्ष्य के आधार पर यह माना जाता है कि श्रमिक द्वारा अपना आवेदन वापस लेने की लिखित प्रार्थना से पूर्व नियोजक द्वारा उसकी सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया था। उक्त तथ्यों को देखते हुए यद्यपि श्रमिक का यह कथन सारहीन हो जाता है कि उसने सेवा निवृत्ति की प्रार्थना की स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व उसे वापस लेने का अनुरोध कर दिया था। जो तथ्य सक्षम से प्रमाणित हैं उनके अनुसार श्रमिक ने सेवा निवृत्ति की प्रार्थना स्वीकृत होने से पूर्व किसी भी रूप में अपने आवेदन को वापस नहीं लिया था। सेवा निवृत्ति के आदेश की स्वीकृति का पत्र भी उसने व्ययक्तता लेने का अस्ताव 4-8-88 को कर दिया गया था इसलिए उसको जानकारी होने की धारणा भी लिया जाना न्याय संगत है। श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह तर्क दिया है कि सेवा मुक्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने से पूर्व व उसकी सूचना श्रमिक को प्राप्त होने से पूर्व वह अपने आवेदन को वापस लेने के लिए स्वतंत्र थे इसलिए प्रदर्श एम-5 स्वीकृति का पत्र अवैधानिक है। इस संबंध में उन्होंने राजकुमार बनाम भारत संघ 1969 लैब. आई. सी. (एस. सी.) 310 का निर्णय प्रस्तुत किया है। नियोजक की ओर से इसी विधि दृष्टान्त का अवलम्ब लिया गया है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां तक किसी कर्मचारी की सेवा से डिसमिस करने का प्रश्न है, वह आदेश तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि श्रमिक को उसकी सूचना नहीं दी जावे। त्याग पत्र के मामले में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है व सक्षम अधिकारी द्वारा पत्रावली पर त्याग पत्र की स्वीकृति करने के आदेश के बावत कर्मचारी द्वारा उसे वापस नहीं लिया जा सकता। प्रस्तुत विवाद में श्रमिक द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्रार्थना पत्र दिया गया था जो त्याग पत्र के समानान्तर है। अतः प्रमाणित तथ्यों व विधि दृष्टान्तों को देखते हुए श्रमिक का यह कथन मान्य नहीं है कि उसने सेवा निवृत्ति के आदेश की स्वीकृति से पूर्व या उसकी सूचना से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लिया था।

7. श्रमिक के क्लेम में एक आपत्ति यह भी है कि त्याग पत्र के वापस लेने के पश्चात् उसे सेवा से हटाने की कार्यवाही छंटनी की परिभाषा में आती है इसलिए धारा 25-एफ जी व एच अधिनियम की पालना के बिना श्रमिक को सेवा से हटाना अनुचित व अवैधानिक है। नियोजक के जवाब में यह प्रतिरक्षा ली है कि किसी भी रूप में यह मामला छंटनी की परिभाषा में नहीं आता है। दोनों पक्षों के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए, श्रमिक को झूठी से मुक्त करने की कार्यवाही उसकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति के अनुरूप मानी जाती है व इस कारण यह मामला छंटनी

की परिभाषा में नहीं आता है उस दृष्टि से विचार किया जाना पूर्ण रूप से अनावश्यक है।

8. निर्देशित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है कि श्रमिक राम सिंह को प्रबन्ध दरीवा कॉपर प्रोजेक्ट दरीवा अखवर द्वारा 5-8-88 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की प्रार्थना को स्वीकार करने हुए सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है इसलिए श्रमिक कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अवार्ड आज दिनांक 29-3-96 को लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

के. एल. व्यास, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2492 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखपटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, विशाखपटनम् के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-8-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-34012/5/94-आई०आर० (विवाद)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2492.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 31-8-1996.

[No. L-34012/5/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Smt. G. Jalshree, B. Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Wednesday, the 17th day of July, 1996

I.T. I.D. No. 5/95(C)

BETWEEN

The General Secretary,
Visakhapatnam Port Employees Union,
Dharmasanti Bhawan, D. No. 26-15-204
Kotharoad Area,
Visakhapatnam-1

Workman.

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam-35.

Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri S. Sivaramdas, Advocate for workman and Sri B. Gowrishankara Raju, Advocate for management, but there is

no representation is made for workman and the court passed the following :

AWARD

Workman and counsel called absent. No representation made. Claim statement not filed. Hence I.T.I.D. is closed and NIL AWARD passed.

Given under my hand and seal of the court this the 17th day of July, 1996.

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2493:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 16 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम् के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-34012/7/94-आई०आर० (विविध)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2493.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 31-7-1996.

[No. L-34012/7/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Smt. G. Jaishree, B. Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Wednesday, the 17th day of July, 1996

I.T.I.D. No. 14/95(C)

BETWEEN

The General Secretary,
Visakhapatnam Port Employees Union,
Dharmasakti Bhawan,
Visakhapatnam-1

.. Workman

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam-35.

... Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri S. Sivaramdas, advocate for workman and Sri B. Gowrisankara Raju, advocate for management, but no representation is made for workman, the court passed the following :

AWARD

Workman and counsel called absent. No representation made. Claim statement not filed. Hence I.T.I.D. is closed and NIL AWARD is passed.

Given under my hand and seal of the court this the 17th day of July, 1996.

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2494:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम् के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-7-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल० 34012/9/94-आई०आर० (विविध)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2494.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 31-7-1996.

[No. L-34012/9/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Smt. G. Jaishree, B.Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Wednesday, the 17th day of July, 1996

I.T.I.D. No. 12/95(C)

BETWEEN

B. Sree Ramulu,
Through :

The General Secretary,
Visakhapatnam Port Employees Union,
Dharmasakti Bhawan,
Visakhapatnam.

... Workman.

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam.

... Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri S. Siva Ramdas, advocate for workman and Sri B. Gowrisankara Raju, advocate for management, but no representation is made, for workman the court passed the following :

AWARD

Workman and counsel called absent. No representation made. Claim statement not filed. Hence I.T.I.D. is closed and NIL AWARD is passed.

Given under my hand and seal of the court this the 17th day of July, 1996.

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2495:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम् पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों

और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-8-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-34011/4/94-आई०आर० (विविध)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2495.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 31-8-96.

[No. L-34011/4/94-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Smt. G. Jaishree, B.Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Wednesday, the 17th day of July, 1996
I.T.I.D. No. 6/95(C)

BETWEEN

The General Secretary,
Visakhapatnam Port Employees Union,
Visakhapatnam. ... Workman.

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam. ... Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri S. Sivaramdas, advocate for workman and Sri B. Gowrishankara Raju, advocate for management, but no representation is made for workman, the court passed the following :

AWARD

Workman and counsel called absent. No representation made. Claim statement not filed. Hence I.T.I.D. is closed and NIL AWARD is passed.

Given under my hand and seal of the court this the 17th day of July, 1996.

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2496:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-8-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-34012/4/95-आई०आर० (विविध)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2496.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 31-8-1996.

[No. L-34012/4/95-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Smt. G. Jaishree, B.Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Wednesday, the 17th day of July, 1996
I.T.I.D. No. 1/96(C)

BETWEEN

The General Secretary,
Port Employees Union (HMS),
Dharma Sakthi Bhawan,
Kotha Road Area,
Visakhapatnam-530001. ... Workman.

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam. ... Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri S. Sivaramdas, advocate for workman and Sri B. Gowrishankara Raju, advocate for management, but no representation is made for workman the court passed the following :

AWARD

Workman and counsel called absent. No representation made. Claim statement not filed. Hence I.T.I.D. is closed and NIL AWARD is passed.

Given under my hand and seal of the court this the 17th day of July, 1996.

G. JAISHREE, Chairman & Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2497:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयन्त ट्रान्सपोर्ट कं० के प्रबंधन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5/8/96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल०-31011/5/89-आई०आर० (विविध)]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2497.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management

of M/s. Jayant Transport Company, Mumbai and their workman, which was received by the Central Government on the 25-8-96.

[No. L-31011/5/89-IR (Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Pansè, Presiding Officer.

Reference int. No. CGIT-2/1 of 1990

Employers in relation to the Management of
M/s. Jayant Transport Co., Bombay

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. M. B. Anchan, Advocate.
For the Workmen : Mr. S. R. Wagh, Advocate.

Mumbai, dated 16th July, 1996

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-31011/5/89-IR(Misc) dated 5-9-1990 has referred to the issue for clarification in respect of one settlement namely —

“Whether the settlement signed by the Bombay Customs House Agents Association, Bombay and the Transport and Dock Workers Union, Bombay before the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi on 27-2-85 is binding on M/s. Jayant Transport Co., Bombay who is signatory to the said settlement ?”

Thereafter by agenda dated 14/25-6-91 a schedule is sent for adjudication. It is in the following terms :

“Whether the demands contained in letter No. TD/31/304/87 dated 12-8-87, addressed by the Transport and Dock Workers Union, Bombay, to M/s. Jayant Transport Company, 15, Dhannur Building, 1st Floor, Sir P. M. Road, Bombay-400001, (copy enclosed as Annexure-1), are justified. If so, what relief the workmen concerned are entitled to and from what date ?”

2. The Secretary, Transport and Dock Workers Union, Bombay filed a statement of claim at Exhibit-3. It is averred that M/s. Jayant Transport Company (herein after called as a Company) is operating in the major port of Bombay as a licenced custom house agent, i.e. clearing and forwarding agent conducting the business of clearing and forwarding at Bombay Port. The fifteen workman employed in the company holding different designations are the members of the union.

3. The duties performed by the workman employed in the custom house agents on the same type of jobs and also of the same work place, that is major

port of Bombay Customs House etc. But their service conditions are different Company Wise. The majority of the companies get themselves organised under the banner of the Bombay Custom House Agents Association. It is averred that the Transport and Dock Workers Union is the sole broking agent in the industry. They raised industrial dispute for improvement in the service conditions of the employees in this sector in the year 1965. The reference was made having No. 2/13 of 1967. The Tribunal gave award in favour of the worker improving service conditions and bringing party. Since then after over three years the union on behalf of the workman and the Bombay Custom House Agents (on behalf of the employers) have entered in to Bi-partite settlement to improve the service conditions. It is pleaded that the Charter of demands are served on individual custom house agents everytime but the settlement is reached industry wise with the employers issued with the understanding that all the Licenced Custom House agents will employment the same. Generally this understanding is complied with bearing very few employers.

4. It is averred that at present the service conditions of the workman employed with Custom House agents are covered by the Bi-partite settlement dtd. 26-6-89. It is submitted that the present dispute arose because M/s. Jayant Transport Company showed its unwillingness to improve the service conditions of its employees. They are paid less and other service conditions are also not in accordance with the settlement and the other workers getting with other custom house agents.

5. On 27-2-85 the union and the association entered into a settlement. That settlement expired on 31-1-88. The other settlement was made between the parties covering the period 1-2-88 to 31-3-92. The union demanded the improved service conditions to the employees from 1-1-85. It is averred the demand of the union to improve the service conditions of the workman is fair, just and proper. It is submitted that the Tribunal be pleased to make an award and direct the management to implement service conditions as per Bi-partite settlement.

6. The Company registered the claim by the Written statement Exhibit-5. It is averred that without consultation, information, the Central Government send the agenda which is illegal and against the principles of Natural Justice. It is pleaded that the Company is a partnership firm and the Central Government has no control over it. As it is a partnership firm the appropriate government in respect of any dispute is the State Government and not the Central Government. On this ground also the reference is bad in law and not maintainable.

7. The Company pleaded that it is not a member of the Bombay Custom House Agents Association. It has no authority to settle any dispute with regard to its employees with the union and therefore the settlement dtd. 26-6-89 arrived at between the association and union is not binding on it. It is submitted that it is wrong to say that company showed its unwillingness to improve the service conditions of its employees which are very poor as compared to the service conditions prevailing in the industry. It is

averred that from 1-4-92 the company had increased the salaries of the employees. They are having all dock holidays declared by the B.P.T. and bonus at the rate of 1½ months wages per year. It also grants leave to the employees. It is pleaded that the financial condition of the company is not sound to bear the burden, if the unions demands are dealt. It is asserted that no company pay the house rent allowance at the rate of 35 per cent as demanded by the union. It is averred that if the demands of the unions are granted then the company has to be closed down. For all these reasons it is submitted that the reference may be answered in favour of the Company.

8. The issue are framed by my Predecessor at Exhibit-6. The issues and my findings there on are as follows :

Issues	Findings
1. Whether this Central Government Industrial Tribunal has jurisdiction to entertain and decide the present Reference ?	Yes.
2. Whether the present Reference is bad in law and not tenable in law ?	No.
3. Whether the demands contained in the letter No. TD/31/304/87 dated 12-8-87, addressed by the Transport and Dock Workers' Union, Bombay, to M/s. Jayant Transport Company, 15, Dhaunur Building, 1st Floor, Sir P M. Road, Bombay-400001, (copy enclosed as Annx-1) are justified ?	Yes. But reliefs as per the final order.
4. If so, what relief the workmen concerned are entitled to, and from what date ?	The reliefs as per the settlement.
5. What Award ?	As per final order.

REASONS

9. The union filed an affidavit of one Laxman Ramchandra Saoba, Assistant Secretary, Transport and Dock Workers union on 26-9-94 but it was never produced for cross examination. In other words the evidence which is lead by him by way of affidavit cannot be considered.

10. S. P. Gadade (Exhibit-10) who works as a dock clerk in the company affirmed that the Company does the business of clearing and forwarding agent and holds the custom house agents license No. CHA/11/466 and there are 19 employees employed. So far as the business and the license of the company is concerned there is no dispute. Rajesh Mirani (Exhibit-17) the witness for the management affirmed that there are only five workmen working in the company. He affirmed that he will produce the register to confirm it but he did not do so. Mr. Wagh the Learned Advocate for the workman in the company and on behalf of the union rightly argued that the number of the employees in that company is im-

material. Those employees who are now serving, are their members and the relief which is sought for has to be given to the employees who are working there now. I find substance in it.

11. Gadade affirmed that they are paid gross salary and their pay is less than the workmen in other company. They are entitled to as per the industry wise settlement dated 4-7-94 between Transport and Dock Workers Union, Bombay and Bombay Custom House Agents Association. He affirmed that the workman working in other clearing and forwarding agents get salary as per the settlements. From the testimony of Mirani it reveals that they are not paying the wages and the service conditions of their employees are not as per the settlement. It is argued and submitted on behalf of the company that if those reliefs are granted the company will not be in position to bear it. To substantiate this contention they have produced the income tax statement showing that their annual income is far less and if this additional burden is put to them it is not possible for them to work. They have to close the industry. I am not inclined to accept it. Infact the company should have considered this aspect while becoming a member of the association in September, 1991.

12. Ramesh Mahatre (Exhibit-11) is a senior dock clerk of the M/s. L. Gorphandas and Company since 1966. His company is a custom house agent and conducts the business of clearing and forwarding at Bombay Port Trust. He affirmed that their service conditions are revised periodically as per their agreements, between the union and the representative of custom house agents (Employees of Transport and Dock Workers Union, Mumbai) From the written statement and the testimony of Mirani its not in dispute that the association and the union entered into the settlement so far as the service conditions of the employees of the custom house agents. There are about 1200 such agents and their employees are the members of the union. It was not practicable to get signed a settlement by every agent. It is, therefore, the representative of the association signs on behalf of the association, and the said settlement is implemented by all the agents.

13. The additional secretary of the Bombay Custom House agents association affirmed that as per the circular No. 15 all custom house agents were directed to register themselves. He further affirmed the Jayant Transport Company is a member of their association since November 1991. This position is not disputed. There are about 880 members of the association and 1100 clearing agents. Naturally who are the members of the association are bound by the settlements. It is not in dispute that since November, 1991 Jayant Transport Company became member of the association.

14. Rajesh Mirani (Exhibit-17) affirmed that there are five workmen in his company. According to him initially there were 21 employees. Thereafter Jayant one of the partner started M/s. Jayant Shipping Agency Pvt. Ltd., in the year 1989. Twelve employees left Jayant Transport Company because they got better jobs. According to him when the dispute referred to this Tribunal in the year 1990 there were

only five employees working there. He had given the details showing since when they are working with him. According to him Parab, Dock clerk from 1983, Halde, Custom clerk-1983. Jadhav : peon from 1987, Panasare : Dock clerk from 1990, Gardhe : Dock clerk from 1990. No questions were put in the cross-examination to deny this position. I accept it to be correct one.

15. Mirani affirmed that from time to time he had increased the wages and service conditions of these employers. But he had nowhere stated that they are provided with the wages and the service conditions as per the settlements. The Learned Advocate for the company relied upon one settlement of Gadade the witness to the fact that "it is wrong to say that our claim is made on the basis of the charter of demands." On its basis it is tried to submit that the union failed to justify its demands. I am not inclined to accept this case. A single admission of such a nature would not vitiate all claim. Infact practically this reference is on the basis of the admitted positions except this. I therefore find that no weightage can be given to this admission while deciding the reference.

16. It is tried to argue on behalf of the company that behind their backs, without their consultation the central government send agenda to the earlier schedule which is against the principles of natural justice. Mirani was asked whether he made any representation to the Central Government, after the agenda was received by the Tribunal. He replied that he do not remember if he had complied to the government regarding it. That itself goes to show that he must not have complained. Otherwise there would have been an office copy of it. It appears that he did not thought it fit to raise any objection regarding it. No doubt in a normal course the Central Government who should have been asked what he has to say regarding it. But by not doing so no injustice is caused to the company. I say so because even if he would have raised an objection the agenda would have been send. It is so because at relevant time the company was not a member of the association. Naturally the reference should have been answered in favour of the company. It is not that the Central Government wants the reference to be answered in favour of the union but it wanted some adjudication. By sending the reference in that fashion would not have been proper as per the demands raised by the union. I therefore find that no injustice is caused to the company.

17. It is also tried to argue on behalf of the company that the workmen who are working there do different types of work. Looking to the nature of the work the Central Government is not the appropriate authority for making the reference. Mr. Wagh the Learned Advocate for the union placed reliance on *Tulsidas Khemji V/s. Jdaobhai* (1961) 1 LLJ 42 and submitted that the Central Government is the appropriate government for making the reference. In the said authority their Lordships observed. A partnership firm was running four departments—(1) clearing and shipping, (2) godown department, (3) the insurance department and (4) the cotton supervising and controlling department. The employer retrenched some of the employees in the departments of clearing and shipping and godown department

treating them as distinct and different industrial establishments. These two departments carried out activities relating to a major port. The workmen contended that all the four departments must be treated as one unit for the purposes of applying the provisions of S. 25-G of the Industrial Disputes Act. The Central Government referred the dispute for adjudication. The validity of such reference was challenged on the ground that the Central Government was not the appropriate Government and also on the ground that the reference included workmen employed in other activities not falling in any of the items mentioned in S. 2 (a) of the Act. Negativating the said contention, held that the activities carried on in the two departments could be said to be concerning the major port and as the dispute related to retrenchment in these two departments, the Central Government would be the appropriate Government for making the reference. It was also admitted that 25 Per Cent of the space in the godowns was utilized for storing the goods for clearing and shipping." Relying on the ratio given in this authority I find that the Central Government is the appropriate authority for making the reference.

18. For the above said reasons it has to be stated that the employees who are working there are entitled to the service conditions as per the settlement after Jayant Transport Company became member of the association in September, 1991. In other words the employees will be entitled to get benefit of the settlements from September, 1991 and not for the earlier period. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The settlement signed by the Bombay Custom House Agent Association, Bombay and the Transport and Dock Workers Union, Bombay before the Chief Labour Commissioner (Central Government), New Delhi on 27-2-1985 is not binding on M/s. Jayant Transport Co., Bombay as it was not a member of the Bombay Custom House Agent Association, Bombay who is a signatory to the settlement.

The demands contained in the letter dated 12-2-87 addressed by the Dock Workers Union, Bombay, to M/s. Jayant Transport Company, 15 Dhonnur Building, 1st Floor, Sir P. M. Road, Bombay are justified

The Company is directed to implement the judgments and give the reliefs to its employees after November, 1991 within three months.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2498 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-8-96 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-32011/06/88-डी 4(ए)]

बी०एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2498.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on the 25-8-96.

[No. L-32011/106/88-D.IV(A)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 13 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their workmen

PRESENT :

Mr. Justice K. C. Jagadeb Roy... Presiding Officer.

APPEARANCE :

On behalf of Management.—Mr. P. Roy, Deputy Labour Advisor and Mr. G. Mukhopadhaya, Personnel Officer.

On behalf of Workmen.—Mr. S. Das, Secretary and Mr. P. C. Mondal, Executive Committee member of the National Union of Waterfront Workmen (I).

None appears—for other Unions.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port.

AWARD

By Order No. L-32011/106/88-D.IV(A) dated 11-4-1991 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of Calcutta Port Trust for not finalising the issue improvement in promotional opportunities as yet as per Clause 19 of the Wage Settlement dated 11-4-1984, is reasonable and justified. If not, to what relief the workers represented by the 5 unions (list attached) are entitled?”

2. Both from the side of the management and the workmen, written statements have been filed. 1999 GI/96--12

As it appears from the body of the reference only 5 labour unions were mentioned as parties to the instant dispute, namely Calcutta Port & Dock Industrial Workmen Union, National Union of Waterfront Workmen (I), Calcutta Port Shramik Janata Panchayat, Calcutta Port Trust Workers' Union and United Port & Dock Workers' Union. Subsequently while the matter was pending before this Tribunal two more unions came in as parties to the reference case, having been allowed by this Tribunal by order dated 24-7-1991 and 9-10-1991 respectively. There two unions are Haldia Calcutta Port and Dock Shramik Union and Calcutta Port & Dock Workers Union. Of those 7 Unions, only 4 Unions namely National Union of Waterfront Workmen (I), Calcutta Port & Dock Industrial Workmen Union, Calcutta Port Trust Workers Union and Haldia Calcutta Port & Dock Shramik Union had filed their written statements. Of those 4 Unions, only National Union of Waterfront Workmen (I) had filed letter of authority in favour of Mr. S. Das, Secretary of the Union and Mr. P. C. Mondal to represent the case of the workmen.

3. The nature of the schedule of reference is such that the workmen are to lead evidence to say if at all the finalisation of the issue of improvement in promotional opportunities as per Clause 19 of the Wage Settlement dated 11-4-1984 have not yet been made and if this act of non-finalisation were reasonable and justified. The only witness who was examined so far on behalf of the workmen is Sri Sunil Banerjee who had been examined as WW-1 being produced by National Union of Waterfront Workmen (I) on 25-5-1993 and was partly cross-examined on the same day. Thereafter this witness never appeared before the Tribunal for cross-examination nor any petition has been filed for deferring the same. In fact no steps has been taken by the said union thereafter to examine him or to lead any evidence in support of their contention. Without subjecting oneself to cross-examination, the statements of the witness cannot be accepted as evidence. Since this witness has not presented himself for his complete cross-examination, anything stated by him in his examination in chief and in his cross-examination in part, is of no consequence. Virtually there is no material from the side of the workmen in justification of any of their demands raised in this reference. Time was allowed on 14-11-1995 to the workmen as last chance to get ready with the witness to be cross-examined on 18-1-1996 which has not been done by the workmen. The case was deferred on 18-1-1996 on the request of the management as their representative was absent and on subsequent dates e.g., 14-5-1996 and 16-7-1996, the said witness had not also appeared for his further cross-examination.

4. Mr. Mukhopadhaya, Personnel Officer appearing for the management however states that

since the workman have not come forward to lead their evidence and nothing is shown in proof of their demand to be answered by the management, it is not necessary for him to lead any evidence and files a memo on 18-7-1996 informing the Tribunal that subsequent to the Wage Settlement dated 11-4-1984 whose Clause 19 is referred to in the reference, two more wage settlements had been arrived at between the parties to this reference and all the clauses of the earlier wage settlement dated 11-4-1984 stood terminated by the wage settlement dated 6-12-1994. According to Mr. Mukhopadhaya, the unions have lost their interest in the present matter since the reference has become infructuous in view of the present wage settlement.

5. The Workmen's Witness No. 1 who has been examined on 25-5-1993 on behalf of the National Union of Waterfront Workmen(I) had stated that the latest settlement had been arrived at on 6-12-1994 and I find from the records that the cross-examination of this witness was closed by order of this Tribunal dated 15-3-1995 and only on the petition filed subsequently on 4-5-1995 this Tribunal permitted Mr. Das appearing for the National Union of Waterfront Workmen (I) to examine his witness whose evidence left half way, the cross-examination having not been completed.

6. Since no adjudication can be made without any evidence on record and in view of the fact that the only evidence that was available was not be accepted as evidence because the witness did not present himself for cross-examination, there is no evidence available on the record for any adjudication.

7. I accordingly hold that there is no merit in the contention of the workmen in saying that the issue of improvement of promotional opportunities as per Clause-19 of the Wage Settlement dated 11-4-1984 had not been carried out and accordingly the action of the Calcutta Port Trust cannot be said to be unreasonable and unjustified in the circumstances.

The reference is answered accordingly.

Dated. Calcutta,

The 24th July, 1996.

K. C. JAGADEB ROY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

का० आ० 2499:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बोम्बे पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित आदेश उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद

में कर्मचारियों पर जोर औद्योगिक विवादों के अन्तर्गत का प्रकाशित करती है, आ केन्द्रीय सरकार को 5-8-96 का आदेश हुआ था।

[सं० एन-31012/17/92-आई० आर (विविध)]

बो० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th August, 1996

S.O. 2499.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bombay Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on the 5-8-96.

[No. L-31012/17/92-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/67 of 1993

Employers in relation to the Management of Bombay Port Trust.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employer.—Shri C. D. Nargolkar Advocate.

For the Workmen.—Shri Jaiprakash Sawant Representative.

Mumbai, dated 15th July, 1996

AWARD-PART-II

On March 12, 1996 by Part-I award I came to the conclusion that the domestic inquiry which was held against the workman was as per the principles of Natural Justice.

2. In nutshell the facts of the case are that Manjrekar the worker was a security guard of Bombay Port Trust at the relevant time. It was alleged that on 6th July, 1988 he was on duty at N/O shed Princess Dock. After his duty hours at about 4.00 p.m. he left the shed. One A. R. Raorane the police who was having the patrolling duty in the Princess Dock accosted the worker on the road in front of the fire station, Princess Dock. He suspected the workman who was carrying the bag in his hand. He called Panchas. In front of the Panchas the bag was searched and he was found a vegetable oil below the clothes and

belt in the bag which was having the mark "Refined Vegetable Oil" furnished by the People of United States of America not to be sold or exchanged, 1 Gallon, 3.785 litres." The tin was seized and worker was taken to the police station where First Information Report was lodged against the workman.

3. The domestic inquiry was initiated against the worker on two charges where in it was alleged that because of his acts he failed to maintain absolute integrity and devotion to duty and violated Regulation 3(1) of the BPT employees conduct Regulations 1976.

4. In the inquiry it was revealed from the statement of the worker that on 23-8-1988 he falsely stated that he chased a vagrant carrying the oil in, he dropped the same and ran away. Then the police came and made inquiries with him and it was witnessed by one Kolambkar, Mazdoor. Thus he committed an Act listed in Regulation 22(1) (f) of the Bombay Port Trust Rules and Regulations for non scheduled staff and exhibited lack of absolute integrity and devotion to duty in violation of Regulation 3(1) of the BPT employees (Conduct Regulations) 1975. After departmental inquiry the inquiry officer came to the conclusion that Charge No. 1 was proved against the worker. So far as charge No. 2 is concerned it was not proved. On the basis of the report of the inquiry officer the disciplinary authority issued a show cause notice to him why he should not be dismissed from service. His explanation was called for. It was not accepted and ultimately he was dismissed from services.

5. The issues now are to be answered and the findings there on are as follows :—

Issues	Findings
1. Whether the action of the management of BPT, Bombay in dismissing Shri K. S. Manjrekar Dock Watchman w.e.f. 8-1-90 from service is just, legal and proper ?	Yes.
2. If not, to what relief is the workman entitled to ?	Does not survive.

REASONS

6. The worker and the management filed a pursuant Exhibit-13 informing the Tribunal that they do not want to lead any oral evidence for the remaining issues.

7. The Representative of the worker filed an application Exhibit-12 contending that some additional issues may be framed to decide the reference. I have passed the order that as Issue No. 2 covers these issues it is not necessary to frame these issues again. Now alongwith issue No. 2

the contention taken in this application will be considered.

8. D. S. Daithankar was appointed as an inquiry officer. Mr. Sawant the Learned Representative of the worker argued that he was not the officer of the BPT and is an outsider. It is therefore the whole inquiry which was held against the workman vitiated. As against this Mr. Nargolkar the Learned Advocate for the management argued that there is no such prohibition under the BPT employees (Classification, Control and Appeal) Regulations 1975. He argued that the appointment is perfectly legal and valid and the Tribunal had already come to the conclusion that the domestic inquiry which was held against the workman was legal and proper.

9. Mr. Sawant the Learned Representative for the worker relied on Siba Kishore Pattanaik V. Chief Engineer, Paradip Port Trust, 1992 LAB. IC 1012. In that case a person who was not an authority of the Paradip Port was appointed as an inquiry officer. While deciding the matter Their Lordship came to the conclusion that the authority contemplated under the Paradip Port Trust Employees (Classification Control and Appeal) Regulations prescribed an authority means an employee of the Port Trust and nothing less. It is therefore they came to the conclusion that the appointment of the inquiry officer who was not an employee of the post is illegal. According to the Learned Representative the Regulations of the Paradip Port and that of the BPT are similar. Therefore, the authority has an application. So far as the regulations of Paradip Port are concerned they are not produced on the record. Therefore it was not possible for me to compare them with that of the regulations of Bombay Port Trust. It can be further seen that so far as the objection for appointment of Daithankar is concerned it was not taken at initial stage not at any time in the inquiry proceedings. It can be seen that no prejudice is caused by such an appointment. A very fair inquiry was conducted. It can be further seen that as I am not in position to compare those regulations with that of B.P.T. the ratio given in the above stated authority has no application.

10. Now it has to be seen whether the charge levelled against the workman is proved to the satisfaction of the Tribunal by acceptable evidence. It is the contention of the workman that the findings of the inquiry officer are perverse. I am not inclined to accept these submissions for the reasons given below.

11. It is tried to argue that the primary fact not proved. Therefore the whole castle collapses. The primary fact means the theft of all from the B.P.Ts. Shed. There is no complaint on behalf of the B.P.T. of a missing tin. Therefore it is tried to

submit that there was not theft at all. This argument was justified. When there was a charge under Section 381 of the IPC. It can be further seen that because of this argument and for the other circumstances the worker could get acquitted in a criminal case. There is a vast difference between appreciation of evidence in criminal case and that in domestic inquiry. In a criminal case the charge is to be proved beyond doubt, but so far as the domestic inquiry is concerned on the preponderance or probabilities it is to be seen whether the charge is proved or not.

12. From the inquiry proceeding it reveals that the management examined five witnesses and relies on the different documents, such as Panchanama, FIR and others as mentioned in the inquiry report. Laxman Das was the shed superintendent of the Bombay Port Trust under whom the workman was working. He affirmed that on 7-7-88 two police officers came into the shed and they inquired where the vegetable oil is stocked. Then he showed them the place. Thereafter the worker who was sitting in the police jeep was called. Das affirmed that in his presence the worker told that the tin which was found is from the said place. There was no tin of vegetable oil at that time. Then the tin was taken out from the jeep and it was kept on the table of Das. Then it was confirmed from Das whether the tin was from that shed. He answered in the affirmative. Das's statement was recorded by the police also.

13. From the mode of cross-examination of all the witnesses for the management it reveals that the worker admitted the fact that the tin was found in his possession. What is tried to suggest that it was in his hand and not in the bag. This admission was with effect to suit the case which he tried to make out. Namely he saw one person carrying the tin in his hand. He asked him to stop but he did not. Then he shouted "thief thief". The person threw the tin and ran away. He lifted the tin and wanted to deposit the same with the authorities. At that time the police came and accosted him.

14. Das in the cross-examination admits that if any property is found to be not claimed by anybody lying out side the shed which is belonging to the B.P.T. then the employees has to either deposit it in the shed or to go to inspector office.

15. Kolambkar was another witness for the management. According to the workman when the incident took place Kolambkar was there but Kolambkar denied this. It is tried to suggest that due to the pressure from the management he is deposing falsely. I am not inclined to accept this. It is because there was no need for Kolambkar to depose like that. Further more the worker disclosed his name before the security officer who recorded the statement before the departmental

proceeding started. Therefore it was necessary for the presenting officer to examine this witness and bring on the record what revealed from the testimony.

16. Ashok Raorane the police man was on the patrolling duty in the compound of the B.P.T. He saw the workman was carrying a bag and behaving suspiciously. He made inquiries with him but he could not satisfy him. He therefore called the Panchas and in their persence searched the bag in his hand and found a tin as stated above. The Panchanama was drawn on the spot. In the domestic inquiry the workman produced a Panchanama which was produced before the metropolitan magistrate and the statement of the witnesses. In the criminal case the Panchanama was not proved. It is common knowledge that if such types of thefts, are there the Panchas never support the case of the prosecution. But the fact remained that the constable affirmed that the tin was found in the bag which was in the hand of the worker, a Panchanama was drawn on the spot. He took the worker and the property to the police station and gave FIR. There was no reason for this constable to depose falsely against the workman. No such enmity has come on the record.

17. Borkar, PSI supports the case, but he had acted on the basis of the FIR given by Raorane. Jadhav, the security officer produced a circular dated 6-7-87. It clearly speaks out that even if the cargo or any other property and/or any other material belonging to and/or in the custody of the port trust is found lying in abandoned condition, intact or loose it should not be touched for shifting from one place to another place for the purpose of safe storage prior to lodgement of a complaint with the police. It is further observed that contravention of the above stipulation shall be charged for violation of the order and or for contending the theft of the cargo from the docks. It is tried to suggest that this circular was not brought to the notice of security department. No doubt there is no endorsement that it is sent to the security department. But it can be seen that this circular is important one. It was sent to shed superintendent staff offices having 200 copies for distribution. That clearly goes to show that it must have been sent to the security department or even if not sent they are widely published on the notice boards and the worker must be aware of this type of circulars. As this is so there was no reason for the worker to touch the tin which was according to him thrown by unknown person and ran away.

18. It is tried to submit that from the testimony of Das it reveals that many of the tins were already taken away by the consignee. It means they are available in the market. From the marking of the tin it reveals that the tins were not for sale. Not only that it is not the case of the worker that he

purchased the tin from a particular shop. He was found in possession of that tin in the premises of the B.P.T. That speaks against the worker. The tin was not found at its proper place where other consignment was lying. That itself goes to show that it was removed by somebody. I am not here to decide whether there was a theft or not. But the fact remains that the tin was in possession of the worker which is contrary to the circular issued by the BPT. Further from the testimony of Ashok Raorane it has to be said that the tin was in the bag of the worker and was from the shed of the BPT.

19. The inquiry officer had given his report on 26-9-89. It is well reasoned. He found that charge No. 1 against the worker was proved and so far as charge No. 2 is concerned it was not proved. The evidence before the inquiry officer satisfied the Tribunal for coming to the conclusion that charge No. 1 is proved.

20. The Learned Representative of the worker placed reliance on Associated Cement Co., V/s. workman (1964) 3 SCR 952, Union of India V. Raghuvir Sharan 1982 LAB IC 1984, A. F. Singh V. Union of India (1987) 3 ATC 834, Sudharkar Das V. Dayanidhi AIR 1965 Ori. 114, Union of India V/s. Sardar Bahadur (1972) 4 SCC 618, K. Chalamaiiah V. Divisional Railway Manager, S.C. Rly., Guntur and Anr. (1990) 12 ATC 353, Govindal Chopra V. Union of India (1988) ATC 40 page 13, Bareilly Electrical Supply V. Workman 1971 (2) SCC 617. All these cases have different set of facts. None of these authorities can be said to have application to the present set of facts. These authorities were relied upon by the worker for coming to the conclusion that the findings of the inquiry officer are perverse. After discussing the evidences before the inquiry officer I find that there is acceptable evidence on record for coming to the conclusion that charge No. 1 is proved. These authorities have no application to the set of facts before me. For the above said reasons I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The action of the management of Bombay Port Trust in dismissing Shri K. S. Manjrekar Dock Watchman w.e.f. 8-1-90 from service is just, legal and proper.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1996

का० आ० 2500.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सूची के अन्तर्गत आने वाले

उनके कर्मचारियों के बीच, अनुसूचन में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के गठन को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-8-96 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या 42011/50/92-आइ०आर० (टीयू)]

के० वी० वी० उन्नी, डेस्क अधिकारी,

New Delhi, the 6th August, 1996

S.O. 2500.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Archaeological Survey and their workman, which was received by the Central Government on 5-8-96.

[No. L-42011/50/92/RC-DU]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 50 of 1994

In the matter of dispute :

BETWEEN

President Archaeological Survey of India Mazdoor Union 2/236, Namneer, Agra.

AND

Assistant Superintendent (Chemical) Archaeological Survey of India, Agra.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-42011/50/92/IR.D.U., dated 6-5-94, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of Assistant Superintendent (Chemicals) Archaeological Survey of India, Agra in terminating the service of S/Sri Narottam Singh, S/o Baboolal, Ramesh S/o Nathilal and Nepal Singh S/o Shankar Lal ex-daily wages w.e.f. 13-8-91 is justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?

2. In this reference there are three workmen names of which have been mentioned in the schedule (supra). It is alleged that they have worked as labour with the opposite party Archaeological Survey of India Chemical Deptt. w.e.f. 28-1-87, 29-3-89 and 5-1-85 respectively. Earlier their services were terminated on 25-4-88 as they had

made claim for regularisation. Matter was carried before ALC(C). There a settlement had taken place on 12-8-91 by virtue of which the opposite party and agreed to take the mback in service without giving back wages. Thereafter, all the concerned workmen were taken back in service. When they again raised their voice for regularisation they were once again saged on 13-8-91. As they had worked continuously there has been breach of Section 25-F and 25-G of I.D. Act. Hence their terminated is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which the number of working days of the concerned workmen have not been denied. The factum of settlement dated 20-3-89 has also not been denied. Their only defence is that all these workmen were not well behaved and shirked work, hence they were deprived from service.

4. In the rejoinder the above mentioned facts have been denied.

5. In view of the above pleadings of fact there is hardly any need for making any reference of any evidence as facts are common. Still reference may be made to the evidence of Ramesh Chandra WW1 who has spoken on behalf of all the three workmen. He has deposed about continuous service rendered by the workmen. There is no evidence in rebuttal. From the pleadings of parties it has emerged out as common ground that all the three workmen had worked from 28-1-1982, 29-3-89 and 5-1-85. Once they were removed from service and subsequently with mutual consent they were taken back in service in 1989. There is un rebutted evidence of Ramesh Chand that since then they had worked continuously upto 13-8-91. In other words they had render more than 240 days in a calendar year. Hence their services could not be terminated without resorting to compliance of section 25F of I.D. Act. Further Acts of misbehaviour and avoiding to do work certainly amounts to misconduct and the workmen could not be removed from service without holding any domestic inquiry. In its absence the act of the opposite party in removal of three workmen is sheer act of high handedness and nothing else which cannot be upheld, in any manner.

6. Hence my answer to reference is that termination of these workmen is bad in law because of non-payment of notice and retrenchment compensation as envisaged by Section 25F of I.D. Act and non-holding of domestic inquiry for alleged acts of misconduct. Accordingly they are entitled for reinstatement with back wages at the rate at which they were getting wages at the time of their removal.

Dated : 10-7-96.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1996

का० आ० 2501.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 563 दिनांक 12 फरवरी, 1996 द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 12 फरवरी 1996 में यह माम की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को यह माम की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 12 अगस्त, 1996 से यह माम की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एम-11017/9/85-डी० 1 (ए) (1)]

एच० सी० गुप्ता, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 9th August, 1996

S.O. 2501.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 563 dated the 12th February, 1996, the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 12th February, 1996;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for further period of six months from the 12th August, 1996.

[No. S-11017/9/85/D.I(A) (i)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1996

का.आ. 2502—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था,

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ह) के उपखंड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अभिसूचना संख्या का.श्र. 562 दिनांक 12 फरवरी, 1996 द्वारा शीशा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 12 फरवरी, 1996 से छह मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

श्रीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ह) के उपखंड (6) के परमूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 12 अगस्त, 1996 से छह मास की

की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एम-11017/9/85-डी-1(ए) (ii)]

एच. सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 9th August, 1996

S.O. 2502.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 562 dated the 12th February, 1996, the Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 12th February, 1996;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 12th August, 1996.

[No. S-11017/9/85-D.I(A)(ii)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

